रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)—73

REGISTERED No. D. (D.N.)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 35] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 28, 1982/भाद्र 6, 1904

No. 35] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 28, 1982/ BHADRA 6, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचना
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)

गृह मंत्रालय

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली 7 अगस्त, 1982

का०आ० 2970.—केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) (दूसरा संशोधन) नियम, 1981, भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 7 मार्च, 1981 में भारत सरकार के गृह मंत्रालय (कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग) की अधिसूचना सं० का०आ० 740, तारीख 18 फरवरी, 1981 के अधीन प्रकाशित किए गए थे ;

और उक्त नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से ही अर्थात् 7 मार्च, 1981 से प्रवृत्त हो गए और इसी प्रकार अब भी प्रवृत्त है,

और उक्त नियम भारत के राजपत्र भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 19 सितम्बर, 1981 में अधिसूचना सं० का० आ० 2428 तारीख 18 फरवरी, 1981 के अधीन अनवधानता से पुन मुद्रित हो गए

और यह आवश्यक समझा गया है कि उक्त मुद्रण संबंधी गलती को दूर किया जाए,

अत अब यह निदेश दिया जाता है कि उक्त अधिसूचना सं० का० आ० 2428 तारीख 18 फरवरी 1981 को उक्त राजपत्र से लोप किया गया समझा जाए।

2 संदेह दूर करने के लिए यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उक्त अधिसूचना सं० का० आ० 740, तारीख 18 फरवरी, 1981 के साथ यथा प्रकाशित उक्त नियम, राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से अर्थात् 7 मार्च, 1981 से ही प्रवृत्त बने हुए हैं।

[सं० 1(13) पे(ए)/80]

एस० पी० मदान, निदेशक (पेंशन)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 7th August, 1982

S.O. 2970.—Whereas the Central Civil Services (Pension) (Second Amendment) Rules, 1981 were published with the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs (Department of Personnel and Administrative Reforms) No. S.O. 740, dated the 18th February, 1981, in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 7th March, 1981;

And whereas the said rules have come into force on and from the date of their publication in the Official Gazette, that is to say, the 7th March, 1981 and continue to be in force as such;

And whereas the said rules were again inadvertently printed in the Gazette of India, Part I[illegible] [illegible]tion (ii),

dated the 19th September, 1981, vide notification No. S.O. 2428, dated the 18th February, 1981;

And whereas it is considered necessary to rectify the said printing error;

Now, therefore, it is hereby directed that the said notification No. S.O. 2428, dated the 18th February, 1981, may be treated as having been omitted from the said Gazette.

2. It is also clarified for removal of doubts that the said rules as published with the said notification No. S.O. 740, dated the 18th February, 1981, continue to be in force on and from the date of their publication in the official Gazette, that is to say the 7th March, 1981.

[No. 1(13)-Pen(A)/80].

S. P. MADAN, Director (Pension).

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Personnel and Administrative Reforms)

(Banking Division)

New Delhi, the 7th August, 1982

S.O. 2971.—In exercise of the powers conferred by sub clause (vi) of clause (d) and also sub-clause (v) of clause of the Explanation to sub-section (1) of Section 42 Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Government hereby notifies for the purposes of the clauses, the following banks, namely :

1. Andhra Bank, Hyderabad,
2. Corporation Bank, Mangalore,
3. New Bank of India, New Delhi,
4. Oriental Bank of Commerce, New Delhi,
5. Punjab & Sind Bank, Amritsar,
6. Vijaya Bank, Bangalore.

[No. 15/14/82-B.O.III]

N. D. BATRA, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 1982

का०आ० 2971.—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण में खंड (घ) के उपखंड (6) तथा साथ ही खंड (ङ) के उपखंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उपखंडों के प्रयोजनार्थ एतद्द्वारा निम्नलिखित बैंकों को अधिसूचित करती है, अर्थात :—

1. आंध्र बैंक, हैदराबाद,
2. कारपोरेशन बैंक, मंगलोर,
3. न्यू बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली,
4. ओरियंटल बैंक आफ कामर्स, नई दिल्ली,
5. पंजाब एण्ड सिंध बैंक, अमृतसर
6. विजया बैंक, बंगलौर

[सं० 15/14/82-बी०ओ०-III]

एन०डी० बत्रा, अवर सचिव

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 1982

का०आ० 2972—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा श्री एन० के० सिन्हा को वैशाली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 1-7-1982 से प्रारम्भ होकर 30-6-1983 को समाप्त होने वाली अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान श्री एन० के० सिन्हा अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

[सं० एफ० 2-44/82 आर० आर० बी०]

राम बेहरा, अवर सचिव,

New Delhi, the 7th August, 1982

S.O. 2972.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri N. K. Sinha as the Chairman of the Vaishali Kshetriya Gramin Bank, Muzaffarpur and specifies the period commencing on the 1-7-1982 and ending with the 30-6-1983 as the period for which the said Shri N. K. Sinha shall hold office as such Chairman.

[No. F. 2-44/82-RRB]

RAAM BEHRA, Under Secy.

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली,

आयकर

का०आ० 2973.—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 126 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समय-समय पर संशोधित अपनी अधिसूचना सं० 1 (फा०सं० 55/233/63-आई०टी०) तारीख 18-5-64 का निम्नलिखित संशोधन करता है ।

उक्त अनुसूची के क्रम सं० 31 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा

अनुसूची

क्रम सं०	व्यक्ति	आई टी ओ	आई ए सी	ए ए सी	सी आई टी (ए)	सी आई टी
1	2	3	4	5	6	7

" कमान, पुणे के

1	2	3	4	5	6	7
	संपरीक्षा नियंत्रणाधीन सैनिक कर्मचारी किन्तु उनको छोड़कर जो नीचे खंड (क) से (ग) में वर्णित है ।	वेतन और प्रतिदाय पुणे	—	—	—	आयकर आयुक्त पुणे
31 (क)	नियंत्रक सैनिक लेखा दक्षिण कमान के संपरीक्षा नियंत्रणाधीन सैनिक कर्मचारी किन्तु वे जिन्हे मद्रास स्थित उप कार्यालय द्वारा संदाय किया जाता है ।	द्वितीय आयकर अधिकारी वेतन सर्किल मद्रास	रेंज 7 मद्रास	ई-रेंज मद्रास	—	तमिलनाडु-4-मद्रास
31 (ख)	नियंत्रक, सैनिक लेखा, दक्षिणी कमान के संपरीक्षा नियंत्रणाधीन सैनिक कर्मचारी किन्तु वे जिन्हे सिकन्दराबाद स्थित उप कार्यालय द्वारा संदाय किया जाता है	बी-वार्ड वेतन सर्किल हैदराबाद	रेंज-4, हैदराबाद	सी-रेंज हैदराबाद	—	ए पी 1 हैदराबाद
31 (ग)	नियंत्रक, सैनिक लेखा दक्षिणी कमान के संपरीक्षा नियंत्रण अधीन सैनिक कर्मचारी किन्तु वे जिन्हे बंगलौर स्थित उप कार्यालय द्वारा संदाय किया जाता है ।	तृतीय आयकर अधिकारी वेतन सर्किल, बंगलौर	रेंज-3 बंगलौर	रेंज 1 बंगलौर	—	कर्नाटक 1 बंगलौर

यह अधिसूचना 1.6.1982 से प्रभावी होगी ।

[सं० 4639/फा०सं० 188/3/80-आई० टी० (ए०आई०)]

वी० बी० श्रीनिवासन, सचिव, केन्द्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

New Delhi, the 25th May, 1982

INCOME-TAX

S. O. 2973.— In exercise of the powers conferred by section 126 of the Income-tax Act, 1963 (43 of 1961) and of all other powers enabling it in this behalf the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendment to the Schedule annexed to its Notification No. 1 (F. No. 55/233/63-IT) dated 18-5-64 amended from time to time.

In the said Schedule at Sl. No. 31 the following shall be substituted :

SCHEDULE

Sl. No.	Persons	ITO	IAC	AAC	CIT(A)	CIT
1	2	3	4	5	6	7
31.	Military employees under the audit control of Controller of Military Accounts Southern Command Pune except those described in clauses (a) to (c) below :	Salaries and Refunds Pune.	—	—	—	C.I.T. Pune.
31. (a)	Military employees under the audit control of Controller of Military Accounts Southern Command but who are being paid by sub-office situated at Madras.	2nd ITO Salary Circle Madras	Range VII Madras	E-Range Madras	—	Tamilnadu IV Madras
31. (b)	Military employees under the audit Control of Controller of Military Accounts Southern Command but who are being paid by sub-office situated at Secunderabad	B-Ward Salary Circle Hyderabad	Range IV Hyderabad	C-Range Hyderabad		A.P.—I Hyderabad
31. (c)	Military employees under the audit control of Controller of Military Accounts Southern Command but who are being paid by sub-office situated at Bangalore.	3rd ITO Salary Circle Bangalore.	Range III Bangalore.	Range I Bangalore.		Karnataka I Bangalore.

This notification will come into force with effect from 1-6-1982.

[No. 4639/F. No. 188/3/80-IT(AI)]

V.B. SRINIVASAN, Secy.
Central Board of Direct Taxes.

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 1982

सं. 196/82-सीमा-शुल्क

का. आ. 2974 :—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र राज्य में बुलढाना जिले के खामगांव को भाण्डागार स्टेशन के रूप में घोषित करता है ।

[फ. सं 473/91/32-सी. शु.-7]

एन. के. कपूर, अवर सचिव,
केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और
सीमा-शुल्क बोर्ड

CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS

New Delhi, the 28th August, 1982

No. 196/82-CUSTOMS

S.O. 2974.—In exercise of the powers conferred by section 9 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby declares Khamgaon of Buldana District in the State of Maharashtra, to be a warehousing station.

[F. No. 473/91/82-CUS. VII]

N. K. KAPUR, Under Secy.
Central Board of Excise and Customs

धनकर आयुक्त कार्यालय, हरियाणा,

रोहतक, 6 अगस्त, 1982

धनकर

का०आ० 2975.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में यह आवश्यक तथा समीचीन है कि धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के अधीन यहां इसके पश्चात विनिर्दिष्ट ऐसे करदाताओं के नाम तथा अन्य विशिष्टियां प्रकाशित की जाएं, जिनका शुद्ध धन वित्तीय वर्ष 1981-82 के दौरान 10 लाख रुपये से अधिक निर्धारित किया गया है ।

और अतः धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की धारा 42-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का तथा इस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने अपने आदेश दिनांक 7 जनवरी, 1975 के द्वारा धनकर के सभी आयुक्तों को अपने क्षेत्राधिकार में स्थित करदाताओं से संबंधित नाम, पते, हैसियत तथा निर्धारित वर्ष तथा ऐसे करदाताओं द्वारा विवरणित धन, निर्धारित किए गए धन तथा वित्तीय वर्ष 1981-82 के दौरान देय धनकर तथा दिए गए धनकर को प्रकाशित करने के लिए प्राधिकृत किया है ।

अतः अब केन्द्रीय सरकार के उपर्युक्त दिनांक 7 जनवरी, 1975 के आदेश के अनुसार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं एतद्द्वारा इसके संलग्न अनुसूची में उपर्युक्त करदाताओं के नाम तथा विशिष्टियां प्रकाशित करता हूं ।

[फा०सं० 418(5)82-83-वसूली]

सी०बी० राठी, धनकर आयुक्त

आयकर विभाग, हरियाणा, रोहतक

धनकर के ऐसे सभी करदाताओं के नाम, जिनका शुद्ध धन वित्तीय वर्ष 1981-82 के दौरान 10 लाख रुपये से अधिक निर्धारित किया गया था । (i) हैसियत के लिए "एच" हिन्दी अविभक्त कुटुम्ब और "आई" व्यक्तिगत के लिए, (ii) कर निर्धारण वर्ष के लिए (iii) दी गई शुद्ध विवरणी (रिटर्न) के लिए (iv) निर्धारित शुद्ध धन के लिए (v) देय कर के लिए (vi) दिए गए कर के लिए ।

1. श्री पन्ना लाल द्वारा ओरिएण्टल साईंस आपरेट्स वर्कशाप अम्बाला कैंट

   (i) "एच" (ii) 1978-79 (iii) 1057760/- (iv) 1189800/- (v) 27900/- (vi) 27900/-

2. श्री लक्ष्मी सागर द्वारा ओरिएण्टल साईंस आपरेट्स वर्कशाप अम्बाला कैंट

   (i) "एच" (ii) 1978-79 (iii) 988600/-(iv) 112000/ (v) 25460/- (vi) 25460/-

Office of the Commissioner of Wealth Tax, Haryana

Rohtak, the 6th August, 1982

WEALTH TAX

S.O. 2975.—Whereas the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the Public interest to publish the names and other particulars hereinafter specified relating to assessees who have been assessed under the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957) on net wealth exceeding Rs. 10 lacs during the financial year 1981-82.

And whereas in exercise of the powers conferred by section 42A of the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957), and all other powers enabling them in this behalf the Central Government has by its order dated 7-1-1975 authorised all Commissioners of Wealth-tax to publish the names, addresses, status and assessment year relating to assessees within their jurisdiction and wealth returned by the wealth assessed on, the wealth-tax payable and the wealth-tax paid by such assessees during the financial year 1981-82.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred upon me by the Central Government by its aforesaid order dated 7-1-1975, I hereby publish in Schedule, hereto annexed, the names and other particulars of the assessees aforesaid.

[F. No. 418(5)/82-83/REC]

C. B. RATHI, Commissioner of Wealth Tax.

INCOME TAX DEPARTMENT, HARYANA, ROHTAK

Names of all wealth-tax assessees assessed on net wealth exceeding Rs. 10 lakhs during the financial year 1981-82 (i) stands for status—'I' for Individual, 'H' for Hindu Undivided Family (ii) for assessment year (iii) for net wealth returned (iv) for net wealth assessed (v) for tax payable and (vi) for tax paid.

1. Shri Panna Lal C/o Oriental Science Apparatus Workshop Ambala Cantt. (i) H(Sp) (ii) 1978-79 (iii) 1057760/- (iv) 11,89,800/- (v) Rs. 27,900/- (vi) 27,900/-.

2. Shri Lakshmi Sagar C/o above (i) H(Sp) (ii) 1978-79 (iii) 9,86,600/- (iv) 11,20,100/- (v) 25,460/- (vi) 25,460/-.

वाणिज्य मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 1982

का०आ० 2976.—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा

प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विद्युत मोटरों तथा जनित्रों का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1980* का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्—

1 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विद्युत मोटरों तथा जनित्रों का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) संशोधन नियम, 1982 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 विद्युत मोटरों तथा जनित्रों का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1980 के नियम 8 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्—

"(8) निरीक्षण फीस —निर्यात कर्ता द्वारा अभिकरण को निरीक्षण फीस निम्नलिखित के अनुसार दी जाएगी

(i) (क) उत्पादन के दौरान क्वालिटी नियंत्रण स्कीम के अधीन निर्यात के लिए प्रति परेषण न्यूनतम 20 रुपये के अधीन रहते हुए, पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 0 2 प्रतिशत की दर से।

(ख) परेषणानुसार निरीक्षण के अधीन निर्यात के लिए प्रति परेषण न्यूनतम 20 रुपए के अधीन रहते हुए, पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 0 1 प्रतिशत की दर से।

(ii) उन विनिर्माताओं/निर्यातकर्ताओं के लिए जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की संबंधित सरकार के साथ लघु उद्योग विनिर्माण एककों के लिए रजिस्ट्रीकृत है, प्रति परेषण न्यूनतम 20 रुपए के अधीन रहते हुए, क्रमशः (क) और (ख) के लिए 0 18 प्रतिशत और 0 36 प्रतिशत की दर से होगी।"

पाद टिप्पण

*का०आ० 2554 तारीख 27-9-80

[पत्र सं० 6(9)/80-नि०नि० तथा नि०उ०]

MINISTRY OF COMMERCE

(Department of Commerce)

New Delhi, the 28th August, 1982

S.O. 2976.—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules to amend the *Export of Electric Motors and Generators (Quality Control and Inspection) Rules, 1980, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Export of Electric Motors and Generators (Quality Control and Inspection) Amendment Rules, 1982

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2 In the Export of Electric Motors and Generators (Quality Control and Inspection) Rules, 1980, for rule 8, the following rule shall be substituted, namely :

"(8) Inspection fee —Inspection fee shall be paid by the exporter to the Agency as under :

(i) (a) For export under in-process quality control scheme at the rate of 0 2 per cent of the F O B. value subject to a minimum of Rs 20/1 per consignment

(b) For exports under consignmentwise inspection at the rate of 0.4 per cent of the F O B. value subject to a minimum of Rs. 20/- per consignment.

(ii) Subject to the minimum of Rs. 20/- per consignment, the rate shall be 0.18 per cent and 0.36 per cent for (a) and (b) respectively for manufacturer-exporter who are registered as Small Scale Manufacturing Units with the concerned Government of States/Union Territories".

*Foot note :—

S O 2554 dated 27-9-1980.

[F. No 6(9)/80-EI&EP]

का०आ० 2977.—केन्द्रीय सरकार निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पटसन मिल के पुर्जे तथा उपसाधन निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1979* का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात

1 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ —

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पटसन मिल के पुर्जे तथा उपसाधन निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) संशोधन नियम, 1982 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 पटसन मिल के पुर्जे तथा उपसाधन निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1979 के नियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् —

'(6) निरीक्षण फीस —निर्यातकर्ता द्वारा अभिकरण को निरीक्षण फीस निम्नलिखित के अनुसार दी जाएगी

(i) (क) उत्पादन के दौरान क्वालिटी नियंत्रण स्कीम के अधीन निर्यात के लिए प्रति परेषण न्यूनतम 20 रुपए के अधीन रहते हुए, पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 0 2 प्रतिशत की दर से।

(ख) परेषणानुसार निरीक्षण के अधीन निर्यात के लिए प्रति परेषण न्यूनतम 20 रुपए के अधीन रहते हुए, पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 0 1 प्रतिशत की दर से।

(ii) उन विनिर्माताओं/निर्यातकर्ताओं के लिए जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की संबंधित सरकारों के साथ लघु उद्योग एककों के लिए रजिस्ट्रीकृत है, प्रति परेषण न्यूनतम 20 रुपए के अधीन रहते हुए, क्रमशः (क) और (ख) के लिए 0 18 प्रतिशत और 0 36 प्रतिशत की दर होगी।

*पाद टिप्पण का०आ० 939 तारीख 17-3-1979

[पत्र सं० 6(9)/80-नि०नि० तथा नि०उ०)]

S.O. 2977.—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules to amend the 'Export of Jute Mill Spares and Accessories (Quality Control and Inspection) Rules, 1979, namley :—

1 Short title and commencement —(1) These rules may be called the Export of Jute Mill Spares and accessories (Quality Control and Inspection) Amendment Rules, 1982.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Export of Jute Mill Spares and Accessories (Quality Control and Inspection) Rules, 1979, for rule 6, the following rule shall be substituted, namely :

"(6) Inspection fee.—Inspection fee shall be paid by exporter to the Agency as under :

(i) (a) For exports under in-process quality control scheme at the rate of 0.2 per cent of the F.O.B. value subject to a minimum of Rs. 20/- per consignment.

(b) For exports under consignmentwise inspection at the rate of 0.4 per cent of the F.O.B. value subject to a minimum of Rs. 20/- per consignment.

(ii) Subject to the minimum of Rs. 20/- per consignment, the rate shall be 0.18 percent and 0.36 per cent for (a) and (b) respectively for manufacturer exporter who are registered as Small Scale Manufacturing Units with the concerned Governments of States/Union Territories".

Foot note:

S.O. 939 dated 17-3-1979.

[F. O. No. 6(9)/80--EI&EP]

का०आ० 2978.—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एल्यूमीनियम के बर्तनों के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1980* का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—

(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम एल्यूमीनियम के बर्तन निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) संशोधन नियम, 1982 है।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 एल्यूमीनियम के बर्तन निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1980 के नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् —

"(7) निरीक्षण फीस :—निर्यातकर्ता द्वारा अभिकरण को निरीक्षण फीस निम्नलिखित के अनुसार दी जाएगी

(i) (क) उत्पादन के दौरान क्वालिटी नियंत्रण के अधीन निर्यात के लिए प्रति परेषण न्यूनतम 20 रुपये के अधीन रहते हुए, पोत, पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 0.2 प्रतिशत की दर से।

(ख) परेषण निरीक्षण के अधीन निर्यात के लिये— प्रति परेषण न्यूनतम 20 रुपए के अधीन रहते हुए पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 0.4 प्रतिशत की दर से।

(ii) उन विनिर्माताओं/निर्यातकर्ताओं के लिए जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की संबंधित सरकारों के साथ लघु उद्योग विनिर्माण एककों के लिए रजिस्ट्रीकृत है, प्रति परेषण न्यूनतम 20 रुपये के अधीन रहते हुए क्रमश (क) और (ख) के लिए 0.18 प्रतिशत और 0.36 प्रतिशत की दर से होगी।"

*पाद टिप्पण—

का०आ० 2440 तारीख 20-9-80

[पत्र सं० 6(9)/80-नि०नि० तथा नि०उ०)]

सी०बी० कुकरेती, संयुक्त निदेशक

S.O. 2978.—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Export of Aluminium Utensils (Quality Control and Inspection) Rules, *1980, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Export of Aluminium Utensils (Quality Control and Inspection) Amendment Rules, 1982.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Export of Aluminium Utensils (Quality Control and Inspection) Rules, 1980, for rule 7, the following rule shall be substituted, namely :—

"(7) Inspection fee.—Inspection fee shall be paid by the exporter to the Agency as under :

(i) (a) For exports under in-process quality control scheme at the rate of 0.2 per cent of the F.O.B. value subject to a minmum of Rs. 20/- per consignment.

(b) For exports under consignmentwise inspection at the rate of 0.4 per cent of the F.O.B. value subject to a minimum of Rs. 20/- per consignment.

(ii) Subject to the minimum of Rs. 20/- per consignment, the rate shall be 0.18 per cent and 0.36 per cent for (a) and (b) respectively for manufacturer exporter who are registered as Small Scale Manufacturing units with the concerned Governments of States/Union Territories".

*Foot note :—

S.O. 2440 dated 20-9-1980.

[F. No 6(9)/80-EI&EP]

C. B. KUKRETI, Jt. Director.

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 1982

(तम्बाकू उद्योग विकास नियंत्रण

का०आ० 2979.—केन्द्रीय सरकार, तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 3 और 4 के साथ पठित तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 (1975 का 4) की धारा 4 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमती अरुणा माखन, निदेशक, वित्त प्रभाग वाणिज्य विभाग नई दिल्ली, डा० डी एन राम, कृषि निदेशक, बिहार सरकार पटना और श्री एस सी बंदोपाध्याय, कृषि उप निदेशक (विपणन) पश्चिमी बंगाल सरकार, कलकत्ता को तम्बाकू बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है, और निदेश देती है कि भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय (तम्बाकू उद्योग विकास नियंत्रण) की अधिसूचना सं० का०आ० 5417 तारीख 17 दिसम्बर, 3975 में निम्नलिखित और संशोधन किए जाएंगे, अर्थात :—

उक्त अधिसूचना में, विद्यमान क्रम सं० 7,21 और 22 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात —

7. श्रीमती अरुणा माखन, निदेशक, वित्त प्रभाग वाणिज्य विभाग, नई दिल्ली —सदस्य	वित्त से सव्यवहार करने वाले मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए

21. श्री एस० सी० बंदोपाध्याय कृषि उप निदेशक (विपणन) पश्चिमी बंगाल सरकार कलकत्ता-मदस्य	पश्चिमी बंगाल सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए	वे दो वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।
22. डा० डी एन० राम कृषि निदेशक बिहार सरकार विकास सचिवालय पटना-15 सदस्य	बिहार सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए	

[सं० 8/3/82-इ० पी० कृषि-6]

ओ० पी० गुप्ता, डेस्क अधिकारी

New Delhi the 17th August, 1982

(TOBACCO INDUSTRY DEVELOPMENT CONTROL)

S.O. 2979 – In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 4 of the Tobacco Board Act, 1975 (4 of 1975) read with rules 3 and 4 of the Tobacco Board Rules, 1976, the Central Government hereby appoints Smt. Aruna Makhan, Director, Finance Division, Department of Commerce, New Delhi, Dr. D.N Ram, Director of Agriculture, Government of Bihar, Patna and Sh. S.C. Bandopadhyaya, Deputy Director of Agriculture (Marketing) Government of West Bengal, Calcutta, as Members of Tobacco Board and directs that the following further amendments shall be made in the Notification of the Government of India in the Ministry of Commerce (Tobacco Industry Development Control) No. S.O. 5417 dated the 17th December, 1975 namely:—

In the said notification, for the existing serial Nos. 7, 21, and 22 and entries relating thereto, the following shall be substituted namely:-

7. Smt. Aruna Makhan, Director, Finance Division, Department of Commerce, New Delhi.	Member to represent the Ministry dealing with Finance.	
21. Sh. S.C. Bandopadhyaya, Deputy Director of Agriculture (Marketing), Government of West-Bengal, Calcutta.	Member to represent the Government of West Bengal	They shall hold office for a period of 2 years
22. Dr. D.N. Ram, Director of Agriculture, Government of Bihar, Vikas Sachivalya, Patna-15.	Member to represent the Government of Bihar.	

[No. 8/3/82-EP-Agri-vi]

O.P. GUPTA, Desk Officer

संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात निर्यात का कार्यालय

बम्बई,

विषय मिडको कन्टेनर्स लि० बम्बई को जारी किए गए अग्रिम लाइसेंस सं० पीकें /0456541, दिनांक 1-9-81 (दोनों प्रतियां) मूल्य 1,93,4000 रुपए और डी ई ई सी संख्या 001841 दिनांक 4-9-81 को रद्द करने का आदेश।

का० आ० 2980.—सर्वश्री मिडको कन्टेनर्स लि० बम्बई को लाइसेंस अवधि अप्रैल—मार्च के लिए इस आदेश के पीछे लिखी मदों के लिए एक अग्रिम लाईसेंस संख्या पी के/0456541, दिनांक 1-9-1981 मूल्य 18,93,400 रुपए और डी ई ई सी संख्या 001841, दिनांक 4-9-81 जारी किए गए थे। उन्होंने इस आधार पर अग्रिम लाईसेंस और डी ई ई सी की अनुलिपि प्रतियां के लिए आवेदन किया है कि मूल प्रतियां चुरा ली गई है।

2 अपने तर्क के समर्थन में आवेदन ने महानगरीय मजिस्ट्रेट, बम्बई के न्यायालय में पंजीयक द्वारा विधिवत् सत्यापित स्टाम्प पेपर पर एक शपथ पत्र दाखिल किया है। मैं संतुष्ट हूं कि लाईसेंस की दोनों मूल प्रतियां और मूल डी ई ई सी खो गई है और निदेश देता हूं कि अग्रिम लाइसेंस की अनुलिपि (दोनों प्रतियां) और डी ई ई सी की अनुलिपि आवेदन को जारी कर दी जाए। अग्रिम लाइसेंस की दोनों मूल प्रतियां और डी ई ई सी रद्द की गई समझी जाए।

[मिसिल सं० ए डी सी /यू डी ई एस /372/055235 /एएम-81/एल/ए एल एस दिनांक 25-1-81]

जी आर० नायर, उप मुख्य नियंत्रक,

आयात-निर्यात

कृते संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

विषय- लाइसेंस संख्या पी के/0456541, दिनांक 1-9-81 की अनुलिपिक सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति की और डी ई ई सी पुस्तिका सं०-001841, दिनांक 4-9-81 की अनुलिपि प्रतियां जारी करना।

यह अनुरोध किया जाता है कि ऊपर उल्लिखित मूल अग्रिम लाइसेंस और डी ई ई सी जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है यदि वे प्रस्तुत किए जाएं तो वे वैध न समझे जाएं और यदि उपयुक्त लाइसेंस की दोनों मूल प्रतियां और डीईईसी आपके पत्तन पर प्रस्तुत किए जाएं या उपयोग किए जाएं तो इसकी सूचना इस कार्यालय को तुरन्त दी जाए।

लाइसेंस सं० और डीईई सी दिनांक	जारी करने वाला कार्यालय का नाम	मदें	अवधि	मूल्य
0456541दिनांक 1-9-81 और डी ई ई सी नं० 001841,दिनांक 4-9-81	संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात का कार्यालय	एम०एस० प्लेटस 8 एमएम प्राईम क्वालीटी 495 एम०टी०	12 मास अप्रैल-मार्च 1982	1893400 रुपए

एम० बालगंगाधरन, नियंत्रक, आयात- निर्यात

कृते संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

Office of the Joint Chief Controller of Imports and Exports

Bombay

Subject : Order for Cancellation of Advance Licence No. PK/0456541 dt. 1-9-81 for Rs. 18,93,400 (both copies) and DEEC No. 001841 dt. 4-9-81 issued in favour of M/s. Midco Containers Ltd., Bombay.

S.O. 2980.—(1) M/s. Midco ontainers Ltd., Bombay were granted advance licence No. PK/0456541 dt. 1-9-81 for Rs. 18,93,400 and DEEC No. 001841 dt. 4-9-81 for the item shown on reverse of this order for Licensing period AM. They have applied for duplicate copy of advance licence and DEEC on the grounds that the same are stolen.

(2) In support of their contention the applicants have filed an affidavit on stamped paper duly attested before the Regist-

rar, Metropolitan Magistrate's Court, Bombay. I am satisfied that original Licence in duplicate and original DEEC have been lost and direct that the duplicate advance licence (both copies) and duplicate DEEC be issued to the applicant. Both copies original of advance licence and DEEC mentioned above may be deemed to have been cancelled.

[F..No. ADV|UDES.372|055235|AM81|L|ALS]

G. R. NAIR, Dy. Chief Controller of Imports & Exports.

For Jt. Chief Controller of Imports and Exports

SUB : Issue of duplicate customs of copy of Licence No. PK/0456541 dt. 1-9-81; and DEEC Book No. 001841 dt. 4-9-81

It is requested that the original advance licence and DEEC mentioned above, particulars given below would not be valid if produced and that intimation would be sent to this office immediately if the original both copies of above licence and DEEC are presented or utilized at his post.

Licence NO. & DEEC. Dt.	Issued by	Items	Valid for period	luvaluecar.
0456541 dt, 1-9-81 & DEEC No. 001841 & dt. 4-9-81	Jt. C C.I & E,	M.S. plates 8mm. prime quality 495 M.T.	AM82 12/months	Rs. 1893400/-

M. BALGANGADHARAN, Controller Of Imports & Exports.

For Jt. Chief Controllers of Imports & Expsors

MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICALS & FERTILIZERS

(Deptt. of Petroleum)

New Delhi, the 7th August, 1982

S.O. 2981—In pursuance of Clause (a) of Section 2 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum Chemicals'S.O. No. 985 dated 6-3-76, the Central Government hereby authorises the authority mentioned in column 1 of the Schedule below to perform the function of the competent authority under the said Act, within the areas mentioned in the corresponding entry in the column 3 of the said Schedule.

SCHEDULE

Name of Person	Address	Territorial jurisdiction
Senior Pipeline Engineer, Indian Oil Corporati n Ltd.	Senior Pipeline Engineer & Liaison Officer, I.O.C. Ltd., (Refineries & Pipelines Divisio 1), near Aliganj Police Station, P.B. No. 58, Allahabad.	Uttar Pradesh

[File No. 12017/2/82- Prod]

पेट्रोलियम, रसायम और उर्वरक मंत्रालय

(पेट्रोलियम विभाग)

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 1982

का०आ० 2981.—पेट्रोलियम एवं खनिज पाइपलाइन (भूमि मे उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) के खण्ड 2 की धारा (क) के अनुसरण मे तथा भारत सरकार, पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अधिसूचना एस० ओ० संख्या 985 दिनांक 6-3-76 का अधिक्रमण करते हुए, केन्द्रीय सरकार नीचे दी गयी अनुसूची के कालम 1 में उल्लिखित प्राधिकारी को उक्त कालम (3) की तदनुरूपी प्रविष्टि में उल्लिखित क्षेत्र की सीमाओ के भीतर उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी के कार्य करने के लिए एतद्द्वारा प्राधिकृत करती है .

अनुसूची

व्यक्ति का नाम	पता	क्षेत्रीय सीमा
सीनियर पाइपलाइन इंजीनियर, इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड	सीनियर पाइपलाइन इंजीनियर तथा सम्पर्क अधिकारी इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (रिफाइनरी व पाइपलाइन प्रभाग) अलीगंज पुलिस स्टेशन के पास पोस्ट बाक्स संख्या 58 इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश

[सं० 12017/2/81 प्रो०]

नई दिल्ली, 9 अगस्त 1982

का० आ० 2982—यत: पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का० आ०स० 941 तारीख 26-6-81 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियो के उपयोग के अधिकारो को पाइप लाईनो को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यत केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची मे विनिर्दिष्ट भूमियो में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची मे विनिर्दिष्ट उक्त भूमियो में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियो मे उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार मे विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी बाधाओ से मुक्त रूप मे, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

कूप नं० एन के० सी०बी० से एन. के बी.यू.एन के सी एन. तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य गुजरात जिला व तालुका. महेसाना

गांव	सर्वे नं०	हेक्टेयर	ए आर	ई सेन्टीआर
धानपुरा	357	0	04	56
	352	0	07	44
	351	0	07	20
	346	0	00	50
	349	0	07	56
	348	0	14	88
	347	0	08	76
	332	0	00	50
	कार्ट ट्रेक	0	00	60
	455	0	03	84
	458	0	15	60
	457	0	03	00
	458/2	0	03	84
	458/1	0	04	08
	459	0	01	92
	465/1	0	06	96
	466	0	10	08
	कार्ट ट्रेक	0	00	96
	463	0	08	16
	473	0	10	20
	474	0	06	60
	कार्ट ट्रेक	0	02	76
	635	0	02	88
	622	0	01	80
	621/2	0	05	28
	620	0	03	48
	कार्ट ट्रेक	0	03	84
	499/1/2	0	07	68
	499/2/1	0	08	40
	496	0	08	36
	495	0	01	00
	कार्ट ट्रेक	0	03	84
	503	0	12	60
	505	0	24	72
	504	0	05	64
	502	0	03	60

[सं० 12016/20/81-प्रोड II]

New Delhi, the 9th August, 1982

S.O. 2982.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, Chemicals & Fertilizer, (Department of Petroleum) S.O. 1941 dated 26-6-81 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for loying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Acquisition of R O.U. From well No. NKCB to NKBU to NKCN.

STATE : GUJARAT DISTRICT & TALUKA : MEHSANA

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
DHANPURA	357	0	04	56
	352	0	07	44
	351	0	07	20
	346	0	00	50
	349	0	07	56
	348	0	14	88
	347	0	08	76
	332	0	00	50
	Cart track	0	00	60
	455	0	03	84
	456	0	15	60
	457	0	03	00
	458/2	0	03	84
	458/1	0	04	08
	459	0	01	92
	465/2	0	06	96
	466	0	10	08
	Cart track	0	00	96
	463	0	08	16
	473	0	10	20
	474	0	06	60
	Cart track	0	02	76
	635	0	02	88
	622	0	01	80
	621/2	0	05	28
	620	0	03	48
	Cart track	0	03	84
	499/1/2	0	07	68
	499/2/1	0	08	40
	496	0	06	36
	495	0	01	00
	Cart track	0	03	84
	503	0	12	60
	505	0	24	72
	504	0	05	64
	502	0	03	60

[No. 12016/20/81—Prod. II]

का० आ० 2983.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का०आ० सं० 187 तारीख द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः समक्ष अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा

अनुसूची

अंकलेश्वर से वडोदरा तक पाइप लाईन

राज्य:—गुजरात जिला एथ तालुका :—भरुच

गांव	सर्वे नं०	हेक्टेयर	एआर	ई सेन्टीयर
भोलाव	25/8	0	00	68
	25/7	0	10	24
	22/P	0	14	70
	27	0	05	00
	81	0	06	33
	69/A	0	18	00

[सं० 12016/57/81-प्रोड II]

S.O. 2983.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, Chemicals & Fertilizer, Department of Petroleum) S.O. 187 dated under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

Pipeline from Ankleshwar to Vadodara

STATE : GUJARAT DISTRICT & TALUKA : BHARUCH

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
BHOLAV	25/8	0	00	68
	25/7	0	10	24
	22/P	0	14	70
	27	0	05	00
	81	0	06	33
	69/A	0	18	00

[No. 12016/57/81-Prod II]

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 1982

का०आ० 2984— पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) के अंतर्गत भारत सरकार, पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) द्वारा जारी अधिसूचना का०आ०सं० 2591 दिनांक 3 10 1982 प्रो० सं० 120 20/7/81-प्रो० दिनांक 17.9.81 के संलग्न अनुसूची में भारत के राजपत्र के भाग II खण्ड 3 उपखण्ड (ii) में (पृष्ठ 3254-72) प्रकाशित तहसील समराला, जिला लुधियाना, राज्य पंजाब ।

		के स्थान पर				पढ़ें			
नाम ग्राम	खसरा सं०	क्षेत्रफल					क्षेत्रफल		
		हे०	ऐ०	व०	मी०		हे०	ए०	व०	मी०
1	2	3								
बावला 177	579 मिन	00	07	84			00	07	34
रैया/321	23/29 मिन	00	05	51			00	00	51
चडी/323	14/27 मिन	00	01	26	14/26 मिन		00	01	26
धरवाली कलां	16/21/1 मिन	00	10	38	16/21/2 मिन		00	10	38
114	322 मिन	00	00	51	332 मिन		00	00	51
मल माजरा	764 मिन	00	18	73			00	18	33
113	932 मिन	00	16	95	1041—1040/		00	16	95
कोटला समसपुर	4/23/1 मिन	00	01	51	932		00	01	52
110	13/3,4,/6/1,6/1,6/2,7/1 ,7/2)				(11/3, 4, 6/1, 6/2, 7/3, 7/2)				
सपरीयां	22/11 /1 मिन	00	00	76	22/11/2		00	00	76
94	22/11/2 मिन	00	10	63	22/11/1 मिन		00	10	63

1	2	3				4		
हरिया खुर्द	3/19/1 मिन	19/2	18/1	18/2	8/19/1 मिन	19/2	18/1	18/2
92	18/11/1 मिन	00	13	16	18/11/2 मिन	00	13	16
	18/11/2 मिन	00	00	76	18/11/1	00	00	76
हरिया कलां	4/11 मिन	00	06	83	4/11/1 मिन	00	06	83
91	4/12 मिन	00	08	10	4/12/1 मिन	00	07	34
					4/12/2 मिन	00	00	76
उरना 93	3/17 मिन	00	00	26	39/17/1 मिन	00	00	26
	43/4 मिन	00	03	04	43/4/2 मिन	00	03	04
गढी तरखाना	13/2 मिन	00	03	29		—	—	—
79	7 मिन	00	00	76		—	—	—
	8 मिन	00	11	89		—	—	—
	9/1 मिन	00	10	63		—	—	—
	9/2 मिन	00	00	26		—	—	—
	13/2 मिन	00	01	01		—	—	—
	14/1 मिन	00	03	29		—	—	—
	14/2 मिन	00	08	35		—	—	—
	15/1 मिन	00	04	81		—	—	—
	15/2 मिन	00	04	05		—	—	—
	16/1 मिन	00	02	02		—	—	—
	14/11/4 मिन	00	00	00		—	—	—
	19/2 मिन	00	07	59		—	—	—
	20/1/मिन	00	05	32		—	—	—
	20/2 मिन	00	07	08		—	—	—
	22 मिन	00	04	55		—	—	—
	23 मिन	00	12	65		—	—	—
	24 मिन	00	02	78		—	—	—
	23/1 मिन	00	01	26		—	—	—
	8 मिन	00	00	26		—	—	—
	9 मिन	00	10	63		—	—	—
	10 मिन	00	11	13		—	—	—
	12 मिन	00	02	02		—	—	—
	13/1 मिन	00	07	08		—	—	—
	13/2 मिन	00	05	32		—	—	—
	14/1 मिन	00	03	29		—	—	—
	14/2 मिन	00	03	54		—	—	—
	16/2 मिन	00	08	10		—	—	—
	23/17/1 मिन	00	02	02		—	—	—
	17/2 मिन	00	00	51		—	—	—
	25 मिन	00	07	84		—	—	—
	24/4/1 मिन	00	03	29		—	—	—
	4/2 मिन	00	06	58		—	—	—
	5 मिन	00	12	40		—	—	—
	6 मिन	00	00	51		—	—	—
	33/19 मिन	00	08	60		—	—	—
	112 मिन	00	00	51		00	01	26
	115 मिन	00	01	52		—	—	—
	117 मिन	00	00	52		—	—	—
	378 मिन	00	01	26		—	—	—
	38.5 मिन	00	00	51		—	—	—
भाटिया	23/11 मिन	00	01	26		00	04	05
78	23/19 मिन	00	03	04		00	06	83
	20 मिन	00	13	16		00	10	12
	22 मिन	00	11	64		00	07	08
	23 मिन	00	04	81		00	09	87
	24/3/1 मिन	00	05	32	24/3/1 मिन	00	00	26
					3/1/2 मिन	00	05	06

1	2	3				4		
	24/6 मिन	00	00	26		00	01	01
	7 मिन	00	13	66		00	13	91
	14 मिन	00	01	26		00	00	51
	24/15 मिन	00	13	16		00	11	89
	16/1 मिन	00	00	26		—	—	—
	28/3 मिन	00	09	36		00	04	05
	4 मिन	00	05	82		00	10	88
	6 मिन	00	08	60		00	11	89
	7 मिन	00	07	84		00	03	04
	15 मिन	00	05	82		00	03	54
	29/2 मिन	00	02	28	29/22 मिन	00	02	28
	29/11 मिन	00	10	63		00	11	64
	34/7 मिन	—	—	—		00	00	25
	71 मिन	00	00	51		00	00	76

[सं० 12020/7/81—प्रो०]

एस० एम० गोयल, निदेशक

CORRIGENDUM

New Delhi, the 15th July, 1982

S.O. 2984.—In the Schedule appended to the notification of the Govt. of India, Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Department of Petroleum) S.O. No. 2591 dated 3-10-1981, notification No. 12020/7/81 prod dated 17-9-1981 issued under sub section) (i) of Section 3 of the Petroleum & Minerals Pipelines (Acquisition of rights of user in land) Act 1962 (50 of 1962) published at page 3254 to 3272 dated 3-10-1981 of Gazette of India Part II, Section 3 of sub section (ii) for Tehsil Samrala Distt. Ludhiana State of Punjab,

Name of village with H. No.	Khasra No.	For				Read			
(1)	(2)			(3)				(4)	
Badla H. No. 177	579 min	00	07	84		00	07	34	
Ria H. No. 321	23/29 min	00	05	51		00	00	51	
Chari H. No. 323	14/27 min	00	01	26	14/26 min	00	01	26	
Barwali Kalan H. No. 114	16/21 min 1	00	10	38	16//21 min 2	00	10	38	
Mal Majra H. No. 113	322 min	00	00	51	332 min	00	00	51	
	764 min	00	18	73		00	18	33	
	932 min	00	16	95	1040—1041 / 932	00	16	95	
Kotla Shamashpur H. No. 110	4/23 min 1	00	01	51		00	01	52	
	13/3, 4, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2)				(11/3, 4, 6/1, 6/2, 7/3, 7/2) areas unchanged)				
Taprian H. No. 94	22/11 — min 1	00	00	76	22/11 — mln 1	00	00	76	
	22/11 — min 2	00	10	63	22/11 — min 2	00	10	63	
Harjon Khurd H. No. 92	(3/19 min 1	19 min 2	18 min 1	18 min 2	(8/19 min 1	19 min 2	18 min 1	18 min 2	areas unchanged
	18/11 min 1	00	13	16	18/11 min 2	00	13	16	
	18/11 min 2	00	00	76	18/11 min 1	00	00	76	

1	2	3			4			
Harjon Kalan H. No. 91	4/11 min	00	06	83	4/11 min —1	00	06	83
	4/12 min	00	08	10	4/12 min —1	00	07	34
					4/12 — min 2	00	00	76
Urna H. No. 93	39/17 min	00	00	26	39/17 min —2	00	00	26
	43/4 min	00	03	04	43/4 min —2	00	03	04
Garhi Tarkhana H. No. 79	13/2 min	00	03	29		—	—	—
	7 min	00	00	76		—	—	—
	8 min	00	11	89		—	—	—
	9/1 min	00	10	63		—	—	—
	9/2 min	00	00	26		—	—	—
	13/2 min	00	01	01		—	—	—
	14/1 min	00	03	29		—	—	—
	14/2 min)	00	08	35		—	—	—
	15/1 min	00	04	81		—	—	—
	15/2 min	00	04	05		—	—	—
	16/1 min	00	02	02		—	—	—
	14/11/4 min	00	00	00		—	—	—
	19/2 min	00	07	59		—	—	—
	20/1 min	00	05	32		—	—	—
	20/2 min	00	07	08		—	—	—
	22 min	00	04	55		—	—	—
	23 min	00	12	65		—	—	—
	24 min	00	02	78		—	—	—
	23/1 min	00	01	26		—	—	—
	8 min	00	00	26		—	—	—
	9 min	00	10	63		—	—	—
	10 min	00	11	13		—	—	—
	12 min	00	02	02		—	—	—
	13/1 min	00	07	08		—	—	—
	13/2 min	00	05	32		—	—	—
	14/1 min	00	03	29		—	—	—
	14/2 min	00	03	54		—	—	—
	16/2 min	00	08	10		—	—	—
	23/17/1 min	00	02	02		—	—	—
	17/2 min	00	00	51		—	—	—
	25 min	00	07	84		—	—	—
	24/4/1 min	00	03	29		—	—	—
	4/2 min	00	06	58		—	—	—
	5 min	00	12	40		—	—	—
	6 min	00	00	51		—	—	—
	33/19 min	00	08	60		—	—	—
	112 min	00	00	51		00	01	26
	115 min	00	01	52		—	—	—
	117 min	00	01	52		—	—	—
	378 min	00	01	26		—	—	—
	385 min	00	00	51		—	—	—
Bhatian H. No. 78	23/11 min	00	01	26		00	04	05
	23/19 min	00	03	04		00	06	83
	20 min	00	13	16		00	10	12
	22 min	00	11	64		00	07	08
	23 min	00	04	81		00	09	87
	24/3/1 min	00	05	32	24/3/1/1 min	00	00	26
					3/1/2 min	00	05	06
	24/6 min	00	00	26		00	01	0
	7 min	00	13	66		00	13	91
	14 min	00	01	26		00	00	51
	24/15 min	00	13	16		00	11	89
	16/1 min	00	00	26		—	—	—

1	2	3				4		
Bhation H. No. 78 (Contd.)	28/3 min	00	C9	36		00	04	05
	4 min	00	05	82		00	10	88
	28/6 min	00	08	60		00	11	89
	7 min	00	07	84		00	03	04
	15 min	00	05	82		00	03	54
	29/2 min	00	02	28	29/22 min	00	02	28
	29/11 min	00	10	63		00	11	64
	34/7 min	—	—	—		00	00	25
	71 min	00	00	51		00	00	76

[12020/7/81-PrC.]
L. M. GOYAL, Direc r

ऊर्जा मंत्रालय

(कोयला विभाग)

नई दिल्ली 6 अगस्त, 1982

का०आ० 2985 :—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में उल्लिखित भूमि में कोयला अभिप्राप्त किए जाने की संभावना है ।

अत:, केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उसमें कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना देती है,

2 इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक का निरीक्षण सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (राजस्व अनुभाग), दरभंगा हाउस, रांची के कार्यालय में या जिला मजिस्ट्रेट धेनकनाल (उड़ीसा) के कार्यालय में अथवा कोयला नियंत्रक, काउन्सिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता के कार्यालय में किया जा सकता है ।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि में हितबद्ध सभी व्यक्ति, उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (7) में निर्दिष्ट सभी नक्शों, चार्टों और अन्य दस्तावेजों को, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 90 दिन के भीतर राजस्व अधिकारी, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, दरभंगा हाउस, रांची को भेजेंगे ।

अनुसूची

गोपाल प्रसाद ब्लाक
(तालचेर कोयला क्षेत्र)

रेखांक सं० राजस्व /106/81
तारीख 28-12-81
(जिसमें पूर्वेक्षण के लिए अधिसूचित भूमि दर्शित की गई है) ।

क्रम सं०	ग्राम	तहसील	थाना	ग्राम सं०	जिला	क्षेत्र	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मार्दाहरिहरपुर	तालचेर	कोयलाखान	55	धेनकानाल	307.20	भाग
2.	चितलपुर	,,	,,	20	,,	416.00	भाग
3	बानाबासपुर	,,	,,	41	,,	346.60	भाग
4.	पुराबेडा	,,	,,	40	,,	139.12	पूर्ण
5.	गोपाल प्रसाद खामर	,,	,,	19	,,	96.40	पूर्ण
6.	तेलीपुर	,,	,,	27	,,	368.83	पूर्ण
7.	आरक्षित वन	,,	,,	—	,,	430.00	पूर्ण
8.	गोपाल प्रसाद	,,	,,	18	,,	961.26	पूर्ण
9.	कुमुन्डा	,,	,,	11	,,	640.00	भाग
10.	बालूगाडिया	,,	,,	52	,,	670.77	पूर्ण
11.	बाधुबोले	,,	,,	44	,,	397.14	पूर्ण
12.	कुसुमपाल	,,	,,	12	,,	103.53	पूर्ण
13.	आक्षानाबाहली	,,	,,	1	,,	105.38	पूर्ण
14.	मालीबान्ध	,,	,,	54	,,	294.49	पूर्ण,
15.	नौमुहिन	,,	,,	36	,,	167.98	पूर्ण
16.	अन्तागाडिया	,,	,,	3	,,	155.93	पूर्ण
17.	कालमाचुईस	,,	,,	6	,	1506.78	पूर्ण
18.	खुरिंगा	,,	,,	16	,,	162.04	पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	खोलोडा	तालचेर	कोयलाखान	63	धेनकानल	1152.50	भाग
20.	बीराबारपुर	,,	,,	48	,,	77.29	पूर्ण
21.	माझीका	,,	,,	53	,,	158.66	पूर्ण
22.	सत्यबाडीपुर	,,	,,	62	,,	73.98	पूर्ण
23.	नाथागाम	,,	,,	34	,,	80.73	पूर्ण
24.	तेलईपासी	,,	,,	26	,,	239.17	पूर्ण
25.	ब्राह्मणबाहली	,,	,,	47	,,	393.76	पूर्ण
26.	छोटाबरिनी	छेंदीपाडा	जरापाडा	64	,,	35.40	भाग
27.	कानकाराई	,,	,,	65	,,	588.80	भाग
28.	पिरखामान	,,	,,	66	,,	246.16	पूर्ण
29.	बालीचन्द्रपुर	,,	,,	67	,,	438.74	पूर्ण
30.	आरक्षित वन (पी०एफ०)	,,	,,	—	,,	1514.00	पूर्ण
31.	नीसा	,,	,,	69	,,	1152.00	भाग
32.	कालियाकाटा	,,	,,	70	,,	473.60	भाग
33.	रामाडीही	अंगुल	अंगुल	—	,,	230.04	भाग
34.	निरंजनपुर	,,	,,	8	,,	192.00	भाग
35.	निरंजनपुर (बी०आई०टी० II)	,,	,,	—	,,	527.20	भाग
36.	आरक्षित वन	,,	,,	—	,,	256.00	भाग
37.	मुवानपुर	,,	,,	10	,,	128.00	भाग
38.	जमनाली	,,	,,	15	,,	50.20	भाग
39	बडाझारन	,,	,,	5	,,	509.01	पूर्ण
40.	आरक्षित वन कुओं जंगल	,,	,,	—	,,	35.00	भाग
41.	बैठियानाली	,,	,,	4	,,	336.83	पूर्ण
42.	बारामहीटोला	,,	,,	7	,,	1132.17	भाग
43.	नाटाडा	,,	,,	3	,,	1429.21	पूर्ण
44.	अम्बापाल	,,	,,	1	,,	624.64	पूर्ण
45.	अम्बापाल जंगल	,,	,,	2	,,	388.40	पूर्ण
46.	खानमाहीटोला	,,	,,	6	,,	51.83	पूर्ण
47.	खाजूरिया	तालचेर	कोयलाखान	15	,,	202.51	पूर्ण
48.	नीलाद्रीपुर	,,	,,	35	,,	34.63	पूर्ण
49.	दामोल	,,	,,	25	,,	91.14	पूर्ण
50.	सारंग	,,	,,	60	,,	75.00	भाग
51.	नाकईपासी	,,	,,	32	,,	460.80	भाग
52.	प्रसान प्रसाद	,,	,,	39	,,	510.42	पूर्ण

कुल क्षेत्र : 21159.70 एकड़ (लगभग)
या : 8562.91 हैक्टर (लगभग)

सीमा वर्णन :

क—ख रेखा ग्राम कालियाकाटा से होकर जाती है और बिंदु 'ख' पर मिलती है।

ख—ग रेखा ग्राम कालियाकाटा, रामाडीही, मुवानपुर, निरंजनपुर, आरक्षित वन, निरंजनपुर बी०आई०टी०-II, बारामहीटोला और जमुनाली से होकर ग्राम बाडाझारन और आरक्षित वन कुओं जंगल की भागतः सम्मिलित सीमा के साथ-साथ जाती हुई आरक्षित वन कुओं जंगल होकर जाती है और बिंदु 'ग' पर मिलती है ।

ग—घ रेखा तहसील अंगुल और तहसील तालचेर की भागतः सम्मिलित सीमा के साथ-साथ जाती है (जो नाटिडी ब्लाक की सम्मिलित सीमा बनाती है) और बिंदु 'घ' पर मिलती है ।

घ—ङ रेखा ग्राम कालमाचुईन और बानरा, ब्राह्मणबाली और बानरा, प्रसान प्रसाद और बानरा, नाकईपासी और बानरा, दामोल और बानरा पुनः नाकईपासी और बानरा की भागतः सम्मिलित सीमा के साथ-साथ जाती है और बिंदु 'ङ' पर मिलती है।

ङ—च रेखा ग्राम नाकईपासी से होकर जाती है (जो अन्नलाबैरिनी ब्लाक की सम्मिलित सीमा बनाती है) और बिंदु 'च' पर मिलती है ।

च—छ—ज रेखा ग्राम नाकईपासी और सारंग से होकर जाती है और बिंदु 'ज' पर मिलती है।

ज—झ रेखा ग्राम खाजुरिया और कान्धोबोली की भागतः सम्मिलित सीमा के साथ-साथ होकर, ग्राम खोलोडो से होकर, ग्राम तेलीपुर, और खोलोडो की सम्मिलित सीमा के साथ-साथ होकर, ग्राम बानाबापुर से होकर जाती है और बिंदु 'झ' पर मिलती है।

झ—ट। रेखा ग्राम बानाबापुर, चितलपुर, मादीहरिहरपुर, और कुमुन्डा से होकर जाती है और बिंदु 'ज' पर मिलती है ।

ञ—ट रेखा नदी से होकर, ग्राम छोटाबेरिनी और कानकाराई से होकर जाती है और बिन्दु 'ट' पर मिलती है।

ट—ठ रेखा सड़क की भागतः पूर्वी दिशा के साथ साथ जाती है और ग्राम नीम में बिंदु 'ठ' पर मिलती है।

ठ—क रेखा ग्राम नीम से होकर, ग्राम नीसा और मालीबाह्मणी, कालियाकाटा और आरक्षित वन की भागतः सम्मिलित सीमा के साथ-साथ होकर जाती है और आरम्भिक बिंदु 'क' पर मिलती है।

[फा०सं० 19/28/82-सी एम]

स्वर्ण सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Coal)

New Delhi, the 6th August 1982

S.O.2985.—Whereas it appears to the Central Government that coal is likely to be obtained from the lands mentioned in the Schedule hereto annexed ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government hereby gives notice of its intention to prospect for coal therein;

The plan of the area covered by this notification can be inspected in the Office of the Central Coalfields Limited (Revenue Section), Darbhanga House, Ranchi, or in the Office of the District Magistrate, Dhenkanal (Orissa), or in the Office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta.

All persons interested in the lands covered by this notification shall deliver all maps, charts and other documents referred to in sub-section (7) of section 13 of the said Act to the Revenue Officer, Central Coalfields Limited, Darbhanga House, Ranchi, within 90 days from the date of publication of this notification :

SCHEDULE

GOPAL PRASAD BLOCK

(Talcher Coalfield)

Drg. No. Rev/106/81, Dated 28-12-81

(Showing lands notified for prospecting)

Sl. No.	Village	Tahsil	Police Station	Village number	Districts	Area	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Mardahariharpur	Talcher	Colliery	55	Dhenkanal	307.20	Part
2.	Chitalpur	-do-	-do-	20	-do-	416.00	-do-
3.	Banabaspur	-do-	-doe	41	-do-	346.60	-do-
4.	Purabeda	-do-	-do-	40	-do-	139.12	Full
5.	Gopal Prasad Khamar	-do-	-do-	19	-do-	96.40	Full
6.	Telipur	-do-	-do-	27	-do-	368.83	-do-
7.	Reserved forest	-do-	-do-	—	-do-	430.00	-do-
8.	Gopal Prasad	-do-	-do-	18	-do-	961.26	-do-
9.	Kumunda	-do-	-do-	11	-do-	640.00	Part
10.	Bhalugadia	-do-	-do-	52	-do-	670.77	Full
11.	Baghubole	-do-	-do-	44	-do-	397.14	-do-
12.	Kusumpal	-do-	-do-	12	-do-	103.53	-do-
13.	Asanabahali	-do-	-do-	1	-do-	105.38	-do-
14.	Malibandha	-do-	-do-	54	-do-	294.49	-do-
15.	Namuhin	-do-	-do-	36	-do-	157.98	-do-
16.	Antagadia	-do-	-do-	3	-do-	155.93	-do-
17.	Kalamachuln	-do-	-do-	6	-do-	1506.78	-do-
18.	Khuringa	-do-	-do-	16	-do-	162.04	-do-
19.	Soloda	-do-	-do-	63	-do-	1152.00	Part
20.	Birabaipur	-do-	-do-	48	-do-	77.29	Full
21.	Majhika	-do-	-do-	53	-do-	158.66	-do-
22.	Satyabadipur	-do-	-do-	62	-do-	73.98	-do
23.	Nathagan	-do-	-do-	34	-do-	80.73	-do-
24.	Teleipasi	-do-	-do-	26	-do-	239.74	-do-
25.	Brahmanbahali	-do-	-do-	47	-do-	393.76	-do-
26.	Chhotaberini	Chhendipada	Jarapada	64	-do-	35.40	Part
27.	Kankarai	-do-	-do-	65	-do-	588.80	-do-
28.	Pirakhaman	-do-	-do-	66	-do-	246.16	Full
29.	Balichandrapur	-do-	-do-	67	-do-	438.74	-do-
30.	Reserved forest (P.F.)	-do-	-do-	—	-do-	1514.00	-do-
31.	Nisa	-do-	-do-	69	-do-	152.00	Part
32.	Kaliakata	-do-	-do-	70	-do-	473.60	-do-
33.	Ramadihi	Angul	Angul	—	-do-	230.40	-do-
34.	Niranjanpur	-do-	-do-	8	-do-	192.00	-do-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
35.	Niranrjanpur BIT.II	Angul	Angul	—	Dhenkanal	527 20	Part
36.	Reserved Forest	-do	-do-	—	-do-	256.00	-do-
37.	Bhubanpur	-do-	-do-	10	-do-	128.00	-do-
38.	Jamunali	-do-	,do-	15	-do-	50 20	-do-
39.	Badajharan	-do-	-do-	5	-do-	509.01	Full
40.	Reserved forest Kueo Jungle	-do-	-do-	—	-do-	35.00	Part
41.	Bethianali	-do-	-do-	4	-do-	336 83	Full
42.	Baramahitola	-do-	-do-	7	-do-	1132.17	Part
43.	Natada	-do-	-do-	3	-do-	1429.21	Full
44.	Ambapal	-do-	-do-	1	-doe	624.64	-do-
45.	Ambapal Jungle	-do	-do-	2	-do-	388.40	-do-
46.	Sanamahitola	-do-	-do-	6	-do-	51.87	-do-
47.	Khajuria	Talcher	Colliery	15	-do-	202.51	-do-
48.	Niladripur	-do-	-do-	35	-do-	34.63	-do-
49.	Damol	-do-	-do-	25	-do-	91.14	-do-
50.	Sarang	-do-	-do-	60	-do-	75.00	Part
51.	Nakeipasi	-do-	-do-	32	-do-	450.80	-do-
52.	Prasan Prasad	-do-	-do-	39	-do-	510 42	Full
		Total area :	21159.70 acres (approx.)				
		or	8562.90 hec. (approx.)				

Boundary Description:—

A—B line passes through village Kaliakata and meets at point 'B'.

B—C line passes through villages Kaliakata, Ramadihi, Bhubanapur, Niranjanpur, Reserved Forest, Niranjanpur BIT-II, Baramahitola and Jamunali, passes along part common boundary of villages Badajharan and Reserve forest Kueo Jungle through reserved forest Kueo Jungle and meets at point 'C'.

C—D line passes along the part common boundary of Tahsil Angul and Tahsil Talcher (which forms common boundary of Natldi Block and meets at point 'D'.

D—E line passes along the part common boundary of villages Kalamachuin and Danra, Brahmanbahali and Danra, Prasan Prasad and Danra, Nakeipasi and Danra, Damol and Danra, again Nakeipasi and Danra and meets at point 'E'.

E—F line passes through village Nakeipasi (which forms common boundary of Anantaberini Block) and meets at point 'F'.

F.G.H. lines pass through villages Nakeipasi and Sarang and meet at point 'H'.

H—I line passes along part common boundary of villages Khajuria and Kandhobuani, through village Soloda, passes along common boundary of villages Telipur and Soloda, through village Banabaspur and meets at point 'I'.

I—J line passes through villages Banabaspur, Chitalpur, Mardahariharpur and Kumunda and meets at point 'J'.

J—K line passes through river through village Chhotaberini and Kankarai and meets at point 'K'.

K—L line passes along part eastern side of road and meets as point 'L' in village Nisa.

L—A line passes through village Nisa, passes along part common boundary of villages Nisa and Malibrahmani, Kaliakata and Reserve forest and meets at starting point 'A'.

[No. 19/28/82-CL]

SWARAN SINGH, Under Secy.

ग्रामीण विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 1982

का०आ० 2986—25 जुलाई, 1967 की अधिसूचना संख्या एफ० 9-1/66-ए एम के तहत गठित तम्बाकू अपीलीय पैनल तत्काल अस्तित्व-हीन हो जाएगा।

[सं० 9-3/72-ए एम]

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

New Delhi, the 13th August, 1982

S.O. 2986.—The Appellate Panel of Tobacco, constituted vide Notification No. F. 9-1/66-AM, dated the 25th July, 1967, shall cease to exist with immediate effect.

[No. 9-3/72-AM]

का०आ० 2987—वनस्पति तेल श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम 1955 में संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का एक प्रारूप कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 द्वारा अपेक्षित रूप में भारत सरकार के ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 39 तारीख 24 दिसम्बर, 1979 के अधीन भारत के राजपत्र भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 5 जनवरी, 1980, पृष्ठ 41-42 पर प्रकाशित किया गया था जिसमें उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि की समाप्ति के पूर्व उन सभी व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है।

और उक्त राजपत्र 12 जनवरी 1980 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था,

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रारूप की बाबत प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है,

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वनस्पति तेल श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1955 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :—

नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वनस्पति तेल श्रेणीकरण और चिह्नांकन (संशोधन) नियम, 1982 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. वनस्पति श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1955 में,—

(i) नियम 3 में "4 से 12" अंकों और शब्द के स्थान पर "4 से 13" अंक और शब्द रखे जायेंगे।

(ii) नियम 4 में "4 से 12" अंकों और शब्द के स्थान पर "4 से 13" अंक और शब्द रखे जायेंगे।

(iii) अनुसूची 2 (घ) में सभी वनस्पति तेल श्रेणी "एक्स" से संबंधित प्रविष्टि (10) को प्रविष्टि (11) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित प्रविष्टि (11) के पूर्व निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात:—

"(10)	धान की भूसि चोकर का तेल परिष्कृत (खाद्य)	नील शोण (मोव)"

(iv) अनुसूची 12 के पश्चात निम्नलिखित अनुसूची अंतः स्थापित की जाएगी, अर्थात

"अनुसूची III

(नियम 3 और 4 देखिए)

तेल का नाम	वर्णन	1 सेल के लंबी माण्ड माप-मान पर रंग जिसे Y+SR के रूप में अभिव्यक्त किया गया है (से गहरा नहीं)*	विनिर्दिष्ट गुरुत्व 30/30 से०*	40 से ग्रे० पर अपवर्तनांक*	साबुनीकरण मान*	आयोडीन (मान) (विजय पद्धति)*	असाबुनीकारक पदार्थ (प्रतिशत से अधिक नहीं)*	अम्लमान प्रतिशत से अधिक नहीं*	आर्द्रता तथा अविलेय अशुद्धता भार के अनुसार अधिकतम प्रतिशत*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
परिष्कृत खाद्य	धान की भूसी का तेल सार्वाजा सटोवा लिन पामकोमिने के धान की कुटाई प्रक्रिया के समय उतारे गये धान के छिलके की परतों से विलायक घोल प्रक्रिया से निकाला जाएगा जिसमें भा०मा० 03470 (ई) 1966 के अनुसार खाद्य श्रेणी के हैक्सीन विलायक का उपयोग किया जाएगा। तेल का परिष्कार अलकली अवचूषक मिट्टी से विरंजित करके और/या संक्रियित कार्बन से किया जाएगा और भाप से निर्गन्धित किया जाएगा। कोई अन्य रासायनिक कर्मक प्रयोग नहीं किया जाएगा। तेल साफ होगा दुर्गन्ध मिलावट, उच्छिष्ट तथा अन्य	20 (गहरा हरा रंग न हो)	0.90 से 0.920 तक	1.4600 से 1.4700 तक	180 से 195 तक	90 से 105 तक	3 0	0.5	0 10

2
विजातीय पदार्थों से और मिलावटी रंग और सुवास तत्वों से मुक्त होगा । बंद कप पद्धति से ज्वलनांक 250 सें० से कम नहीं होगा । छने हुए तेल का नमूना 35 सें० तापक्रम पर 24 घंटे रखे जाने के पश्चात् आविलता से मुक्त होगा ।

*भा०मा० 3448- 1968 से लिया गया ।

[सं० एफ० 10-7/79-ए०एम०]
राम सिंह, अवर सचिव

S.O. 2987.—Whereas a draft of certain rules further to amend the Vegetable Oils Grading and Marking Rules, 1955, were published as required by section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937), at pages 42 and 43 of the Gazette of India, Part II—Section 3—Sub-Section (ii), dated the 5th January, 1980, with the notification of the Government of India, in the Ministry of Rural Reconstruction, No. S.O. 39, dated the 24th December, 1979, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of a period of forty five days from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 12th January, 1980;

And whereas objections and suggestions received in respect of the said draft rules from the public were considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Vegetable Oils Grading and Marking Rules, 1955, namely :—

RULES

1. (1) These rules may be called the Vegetable Oils Grading and Marking (Amendment) Rules, 1982.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Vegetable Oils Grading and Marking Rules, 1955, —

(i) in rule 3, for the figures and word "IV to XII", the figures and word "IV to XIII", shall be substituted;

(ii) in rule 4, for the figures and word "IV to XII", the figures and word "IV to XIII" shall be substituted;

(iii) in Schedule II(d), the entry (x) relating to All Vegetable Oils 'X' grade, shall be renumbered as entry (xi) and before entry (xi) so renumbered, the following entry shall be inserted, namely :—

"(x) Rice Bran Oil Refind* (edible) Mauve"

(iv) after Schedule XII, the following Schedule shall be inserted, namely :—

"SCHEDULE XIII"

(*See* rules 3 and 4)

Grade designation and definition of quality of Rice Bran Oil)

Grade designation	Description	Colour on Lovibond scale in 1" cell expressed as Y+5R (Not deeper than)*	Specific gravity 30°/30° C*	Refractive index at 40° C*	Saponification value*	Iodine value (Wij's method)	Unsaponifiable matter (not more than per cent)*	Acid Value (not more than)*	Moisture and insoluble impurities by wt. per cent maximum*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	01
Refined (edible)	Rice bran oil shall be obtained from the rice bran layers around the endosperm of rice, removed during the process of rice milling from paddy of Oryza Sativa Linn. Fam. Gramineae by a process of solvent extraction using food grade hexane solvent conforming to IS : 3470(E)—1966. The refining of the oil shall be done by neutralisation with alkali, bleaching by adsorbant earth and/or activated carbon and deodourised with	20 (No dominant green colour)	0.910 to 0.920	1.4600 to 1.4700	180 to 195	90 to 105	3.0	0.5	0.10'

1	2
	steam. No other chemical agent shall be used. The oil shall be clear and free from rancidity, adulterants, sediment, suspended and other foreign matter and added colouring and flavouring substance. The flash point by closed cup method shall not be less than 250°C. The filtered sample of the oil shall be free from turbidity after keeping at 35°C for 24 hours."

*Adopted from IS : 3448—1968

[No. F. 10-7/79-A.M.]
RAM SINGH, Under Secy.

अंतरिक्ष विभाग

बंगलौर 14 जुलाई, 1982

का०आ० 2988.—केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में निर्दिष्ट अधिकारी को, जो सरकार के राजपत्रित अधिकारी की पंक्ति के समतुल्य अधिकारी है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सम्पदा अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है, जो उक्त सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट सरकारी स्थानों की बाबत अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सम्पदा अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और अधिरोपित कर्तव्य का पालन करेगा।

अधिकारी का पदाभिधान	सरकारी स्थानों के प्रवर्ग और स्थानीय अधिकारिता की सीमाएं
(1)	(2)
निर्माण इंजीनियर, सिविल इंजीनियरी प्रभाग, अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र, अंतरिक्ष विभाग, अहमदाबाद।	रजिस्ट्रीकरण जिला सिरोही और आबू रोड के उप-जिले का आबू रोड तालुके के मौजे आबू का सर्वे सं० 49, जिसका माप 4.809 एकड़ अर्थात् 19,260 वर्ग मीटर या उसके लगभग है, इसके साथ-साथ एक बंगला उपगृह और अन्य भवन तथा "हिल व्यू" के नाम से ज्ञात उसपर निर्मित संरचना, जिसकी मकान सं० 232/माउंट आबू नगरपालिका का वार्ड सं० 4, जिसकी सीमाएं निम्नलिखित हैं : पूर्व : सरकारी भूमि पश्चिम : के०एल०सेठ० का प्लाट उत्तर : सरकारी भूमि दक्षिण : सरकारी भूमि और पिलिग्रिम रोड

[सं० 9/2(2)/82-III]
के० आर० रामनाथ, अवर सचिव,

DEPARTMENT OF SPACE

Bangalore, 14th, July 1982

S.O. 2988.—In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (40 of 1971) the Central Government hereby appoint the Officer mentioned in column (1) of the Table below, being an officer equivalent to the rank of Gazetted Officer of Government to be Estate Officer for the purpose of the said Act, who shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on Estate Officer by or under the said Act, within the local limits of his jurisdiction in respect of the public premises specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table.

TABLE

Designation of the Officer	Categories of public premises and local limits of the jurisdiction
(1)	(2)
Construction Engineer, Civil Engineering Division, Space Applications Centre, Department of Space, Ahmedabad.	Survey No. 49 of Moujo Abu of Abu Road Taluka the Registration Dist. Sirohi and Sub-District of Abu Road, admeasuring 4 809 acres i.e., 19,260 sq. mtrs. or thereabouts together with a bunglow, outhouse and other buildings and structure constructed thereof known as 'Hill View' bearing house No. 232/Ward No. 4 of the Mount Abu, Nagarpalika and bounded as follows:- East : Government Land West : Plot No. K.L. . Seth North : Government land and South : Government Land and Pilgrim Road

[No. 9/2(2)/82-II.]
K. R. RAMNATH, Under Secy

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 1982

का०आ० 2989—केन्द्रीय सरकार, डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलकत्ता डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1970 का कतिपय और संशोधन करना चाहती है जैसा कि उक्त धारा से अपेक्षित है, प्रस्तावित संशोधनों का निम्नलिखित प्रारूप उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित

किया जा रहा है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है। इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से साठ दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा।

इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि से पूर्व नियमों के उक्त प्रारूप की बाबत जो भी आक्षेप या सुझाव किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे, केन्द्रीय सरकार उन पर विचार करेगी।

प्रारूप स्कीम

1 इस स्कीम का संक्षिप्त नाम कलकत्ता डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) दूसरा संशोधन स्कीम, 1982 है।

2 कलकत्ता डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1970 की अनुसूची 4 की मद 3 (iv) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्

"परन्तु यंत्रचालित स्विंगिंग डेरिक जिसके अन्तर्गत कैंटीलीवर डेरिक भी है, के कार्यकरण की दशा में, किसी विशिष्ट स्थान पर सभी नियंत्रक लेवलों वाले ऐसे प्रत्येक स्विंगिंग डेरिक के प्रचालन के लिए एक विंच चालक और एक भारमोचन विंच चालक रखा जाएगा।"

[फा० सं० एल डी सी/32/82-एल 4]

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 10th August, 1982

S.O. 2989.—The following draft of Scheme further to amend the Calcutta Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1978, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948), is hereby published as required by the said sub-section for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the period so specified will be taken into consideration by the Central Government.

DRAFT SCHEME

1 This Scheme may be called the Calcutta Dock Workers (Regulation of Employment) Second Amendment Scheme, 1982.

2 In the Calcutta Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1978 in Schedule VI, after item No 3(iv), the following proviso shall be inserted, namely .—

"Provided that in the case of working of mechanically operated swinging Dorrick including cantilever swinging Derrick, one Winch Driver and one relieving Winch Driver shall be booked for operation of every such swinging Derrick having all the centrelling levers at one particular place"

[F No LDC/32/82-L IV]

(श्रम प्रभाग)

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 1982

का०आ० 2990—केन्द्रीय सरकार डाक कर्मचारी (नियोजन का विनियमन) अधिनियम 1948 (1948 का 9) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोचीन डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1959 का कतिपय और संशोधन करना चाहती है। जैसा कि उक्त उपधारा में अपेक्षित है प्रस्तावित संशोधनों का निम्नलिखित प्रारूप उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है। इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से साठ दिन के अवसान पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा।

उक्त अवधि के अवसान के पूर्व नियमों के उक्त प्रारूप की बाबत जो भी आक्षेप या सुझाव किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे केन्द्रीय सरकार उन पर विचार करेगी।

प्रारूप नियम

1 (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम कोचीन डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) (संशोधन) स्कीम, 1982 है।

2 कोचीन डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1959 की अनुसूची में मद (छ) के पश्चात् निम्नलिखित मद अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्—

"(ज) मिलान/टेबल पर्यवेक्षक"

[सं० एल०डी०एक्स०/18/82 एल० 4]

वी० शंकरलिंगम, उप सचिव

(LABOUR DIVISION)

New Delhi, the 11th August, 1982

S.O 2990.—The following draft of a Scheme further to amend the Cochin Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1959, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (6 of 1948), is hereby published as required by the said sub-section for the information of all persons likely to be affected hereby; and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objections or suggestions which may be received rom any person with respect to the said draft before the expiry of the said period will be considered by the Central Government

DRAFT SCHEME

1 This Scheme may be called the Cochine Dock Workers (Regulation of Employment) (Amendment) Scheme 1982.

2 In the Cochin Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1959, in the Schedule after item(g) the following item shall be inserted, namely :—

"(h) Tally/Table Supervisor"

[No LDX/18/82-L IV]

V SANKARALINGAM, Dy Secy.

(नौवहन महानिदेशालय)

बम्बई, 13 अगस्त, 1982

(वाणिज्य पोत परिवहन)

का० आ० 2991—भारत सरकार, नौवहन और परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना सं० एम०एस०ई० (6)/77 एम०टी० तारीख 13 जून 1977 के साथ पठित भारतीय वाणिज्य पोत परिवहन (नाविक नियोजन कार्यालय बम्बई) नियम, 1954 के नियम 5 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नौवहन महानिदेशक, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि

के लिए बम्बई पत्तन पर (नाविक नियोजन बोर्ड) (विदेशगामी) की एतद्द्वारा नियुक्ति करते हैं जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

1. नौवहन महानिदेशक 2. नौवहन उप महानिदेशक नाविक नियोजन के प्रभारी 3. श्रम आयुक्त, बम्बई 4. नाविकपाल, बम्बई 5. निदेशक नाविक नियोजन कार्यालय, बम्बई 6. पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी बम्बई	सरकार के प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य
7. कप्तान एम०एम० कोरेरा 8. श्री के० एन० दलाल 9. श्री टी०एस० नारायन 10. श्री के०एस० भण्डारकर 11. श्री डी० एस० दुमाना 12. कमोडोर एल०के० शर्मा	पोतस्वामियों के प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य
13. डा० लि०ओ० बार्न्स 14. श्री याकुब एम० सेरंग 15. श्री यू०एम० अल्मेडा 16. श्री एम० मोइदू 17. श्री एम०टी० जोसेफ 18. श्री ई० प्रभाकरन	नाविकों के प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य

नौवहन महानिदेशक और नाविक नियोजन कार्यालय, बम्बई के प्रभारी नौवहन उप महानिदेशक उक्त बोर्ड के क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे। निदेशक, नाविक नियोजन कार्यालय, बम्बई उक्त बोर्ड के सदस्य-सचिव होंगे।

[सं० 25(1) सी०आर०ए०/79]

भा० कृ० पावर,

नौवहन उप महानिदेशक

(Directorate General of Shipping)

Bombay the 13th August, 1982

MERCHANT SHIPPING

S.O. 2291.—In exercise of the powers conferred by sub-Rule (1) of rule 5 of the Indian Merchant Shipping (Seamen's Employment Office, Bombay) Rules, 1954, read with the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport No. MSF(6)/77 MT, dated the 13th June, 1977 the Director General of Shipping hereby appoints Seamen's Employment Board (Foreign Going) at the Port of Bombay for a period of two years with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, consisting of the following members, namely:—

1. The Director General of Shipping 2. The Deputy Director General of Shipping, Incharge of the Seamen's Employment 3. Labour Commissioner, Bombay. 4. The Shipping Master, Bombay. 5. The Director, Seamen's Employment Office, Bombay. 6. The Port Health Office, Bombay	Members Representing Government,
7. Capt. M. X. Corera. 8. Shri K. N. Dalal. 9. Shri T. S. Narayan. 10. Shri K. S. Bhandarkar. 11. Shri D.S. Dumana. 12. Comdr. L.K. Sharma.	Members Representing Shipowners.
13. Dr. Leo Barnes. 14. Shri Yakub M. Serang. 15. Shri U.M. Almeida. 16. Shri M. Moidoo 17. Shri M. T. Joseph. 18. Shri E. Prabhakaran.	Members Representing Seamen.

The Director General of Shipping and Deputy Director General of Shipping incharge of the Seamen's Employment Office, Bombay shall respectively be the Chairman and the vice Chairman of the aforesaid Board. The Director, Seamen's Employment Office, shall be member-Secretary of the aforesaid Board.

[No. 25(1) CRA/79]

B.K. PAWAR, Deputy Director General of Shipping.

दिल्ली विकास प्राधिकरण

नई दिल्ली, 31 मई, 1982

का०आ० 2992—दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 की सं० 61) की धारा 57 के अन्तर्गत बनाए गए डी०डी०ए० (मैनेजमेंट एंड डिस्पोजल आफ हाऊसिंग इस्टेट्स) रेगुलेशन्स 1968 के रेगुलेशन 4 द्वारा उपाध्यक्ष दिल्ली विकास प्राधिकरण में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपाध्यक्ष दिल्ली विकास प्राधिकरण, सहायक निदेशक, पट्टा प्रशासन (आवास) को उक्त रेगुलेशन्स के अन्तर्गत किए जाने वाले सभी अनुबन्धों को निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

[सं० एफ 1(17)/82-एल ए बी (एच)]

नाथू राम, सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

New Delhi, the 31st May, 1982

S.O. 2992.—In exercise of the power vested in him under Regulation 4 of the D.D.A. (Management and Disposal of Housing Estates) Regulations 1968 framed under Section 57 of the Delhi Development Act, 1957 (No. 61 of 1957), the Vice-Chairman, Delhi Development Authority, authorises, Assistant Director Lease Admn. (Housing) to execute all agreements made under the said Regulations.

[No. F. 1(17)/82-LAB(H)]

NATHU RAM, Secy.

संचार मंत्रालय

(डाक तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 1982

का०आ० 2993—स्थायी आदेश सं० 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने बोम्मान्नी बानागनाहल्लि, ओक, अरमाकुर, बलगोडे, बस्ति अरमाकुर में टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 1-9-1982 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[सं० 5-6/82-पी० एच बी पी टी]

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(P&T Board)

New Delhi, the 10th August, 1982

S.O 2993—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S O. No 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specifies 1 9-1982 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Vommangi, Banaganapalli, OWK, Atmakur, Velgode, Bandi Atmakur Telephone Exchanges Andhra Pradesh Circle

[No. 5-6/82 PHB(Pt.)]

का०आ० 2994—स्थायी आदेश सं० 627 दिनांक 10 अगस्त, 1982 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने, कावालम, पुलिकल्म, मुट्टार, चपकुलम, रामकरि, कोनुनचेरी, टेलीफोन केन्द्र मे दिनांक 1-9-1982 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है।

[सं० 5-10/82-पी एच बी]

S O 2994—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S O. No 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specifies 1-9-1982 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Pulincunnu, Ramangary, Kalvalam, Champakulam, Mutiar & Kozhencherry Telephone Exchanges, Kerala Circle

[No 5-10/82 PHB]

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 1982

का०आ० 2995—स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा (क) के अनुसार डाक तार महानिदेशक ने अन्दिपति टेलीफोन केन्द्र मे दिनांक 1-9-1982 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है ।

[संख्या 5-4/82-पी०एच०बी०]

New Delhi, the 11th August, 1982

S.O. 2995.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S O. No 627 dated 8th March, 1960, the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specifies 1-9-1982 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Aundipatti Telephone Exchange, Tamil Nadu Circle.

[No. 5-4/82-PHB]

नई दिल्ली 19 अगस्त, 1982

का०आ० 2996 —स्थायी आदेश संख्या 627, दिनांक 8 मार्च, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 434 के खंड III के पैरा (क) के अनुसार डाक-तार महानिदेशक ने कालन्चेरी टेलीफोन केन्द्र मे दिनांक 1-9-1982 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू करने का निश्चय किया है ।

[संख्या 5-10/82-पी०एच०बी०]

आर०सी० कटारिया सहायक महानिदेशक (पी०एन्ड०बी०)

New Delhi, the 19th August, 1982

S.O. 2996.—In pursuance of para (a) of Section III of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951, as introduced by S O No 627 dated 8th March, 1960 the Director General, Posts and Telegraphs, hereby specifies 1 9 1982 as the date on which the Measured Rate System will be introduced in Kolencherry Telephone Exchange, Kerala Circle

[No 5-10/82-PHB]

R C KATARIA Assistant Director General (PHB)

(भारतीय डाक तार विभाग)

मंडल इंजीनियर, तार का कार्यालय पालक्काड

पालक्काड, 13 मई, 1982

का०आ० 2997—केन्द्रीय सिविल सेवाए (अस्थायी सेवाए) नियम, 1965 के नियम 5 के उपनियम (1) के परन्तुक के अनुसरण मे मैं ए० परमेश्वरन, मंडल इंजीनियर तार, पालक्काड एतद्द्वारा श्री पेम्यू जोसफ, टेलीफोन आपरेटर, टेलीफोन केन्द्र, आलत्तूर की सेवाए तत्काल समाप्त करता हू और निदेश देता हू कि वह सेवा समाप्ति के तुरन्त पहले जिस दर पर वेतन तथा भत्ते प्राप्त करता था उस दर पर, यथास्थिति, नोटिस की अवधि तक का या ऐसा नोटिस एक महीने से जितने दिन के लिए कम पड़ता है उतने दिन तक का भत्ताओ सहित वेतन का दावा करने के लिए हकदार होगा ।

[सं० एक्स/82/टी०-एम-एन/4]

(INDIAN POSTS & TELEGRAPHS DEPARTMENT)

(Office of the Divisional Engineer Telegraphs, Palghat)

Palghat, the 13th May, 1982

Order of termination of service issued under the proviso to sub-rule (1) of Rule 5 of the Central Civil Services (Temporary Service) Rules, 1965 —

S.O 2997.—In pursuance of the proviso to sub-rule (1) of Rule 5 of the Central Civil Services (Temporary Service) Rules, 1965, I, A Parameswaran, Divisional Engineer, Telegraphs, Palghat hereby terminate forthwith the services of Shri Mathew Joseph, Telephone Operator, Alathur Exchange and direct that he shall be entitled to claim a sum equivalent to the amount of his pay plus allowances for the period of notice at the same rates at which he was drawing them immediately before the termination of his service, or as the case may be, for the period by which such notice falls short of one month

[Memo No X/82/TMN/4]

का०आ० 2998—केन्द्रीय सिविल सेवाए (अस्थायी सेवाए) नियम, 1965 के नियम 5 के उपनियम (1) के परन्तुक के अनुसरण मे मैं ए० परमेश्वरन, मंडल इंजीनियर, तार पालक्काड एतद्द्वारा श्री वी० साजन, टेलीफोन आपरेटर, टेलीफोन केन्द्र, आलत्तूर की सेवाए तत्काल समाप्त करता हू और निदेश देता हू कि वह सेवा समाप्ति के तुरन्त पहले जिस दर पर वेतन तथा भत्ते प्राप्त करता था इस दर पर यथास्थिति नोटिस की अवधि तक का या ऐसा नोटिस एक महीने से जितने दिन के लिए कम पड़ता है उतने दिन तक का भत्ताओ सहित वेतन का दावा करने के लिए हकदार होगा ।

[सं० एक्स/82/टी-एम-एन/2]

Order of termination of service issued under the proviso to sub-rule (1) of Rule 5 of the Central Civil Services (Temporary Service) Rules, 1965 :—

S O. 2998—In pursuance of the proviso to sub-rule (1) of Rule 5 of the Central Civil Services (Temporary Service) Rules, 1965, I, A. Parameswaran, Divisional Engineer, Telegraphs, Palghat hereby terminate forthwith the services of Shri V. Sajan, Telephone Operator, Alathur Exchange and direct that he shall be entitled to claim a sum equivalent to the amount of his pay plus allowances for the period of notice at the same rates at which he was drawing them immediately before the termination of his service, or, as the case may be, for the period by which such notice falls short of one month.

[Memo No. X/82/TMN/2]

का०आ० 2999—केन्द्रीय सिविल सेवाएं (अस्थायी सेवाएं) नियम 1965 के नियम 5 के उपनियम (1) के परन्तुक के अनुसरण में मैं ए० परमेश्वरन्, मंडल इंजीनियर तार, पालक्काड एतद्द्वारा श्री एन० राजेन्द्रन, टेलीफोन आपरेटर, टेलीफोन केन्द्र आलत्तूर की सेवाएं तत्काल समाप्त करता हूं और निदेश देता हूं कि वह सेवा समाप्ति के तुरन्त पहले जिस दर पर वेतन तथा भत्ते प्राप्त करता था उस दर पर, यथास्थिति नोटिस की अवधि तक का या ऐसा नोटिस एक महीने से जितने दिन के लिये कम पड़ता है उतने दिन तक का भत्ताओं सहित वेतन का दावा करने के लिए हकदार होगा।

[सं० एक्स/82/टी०एम-एन/3]

Order of termination of service issued under the proviso to sub-rule (1) of Rule 5 of the Central Civil Services (Temporary Service) Rules, 1965.

S.O. 2999.—In pursuance of the proviso to sub-rule (1) of Rule 5 of the Central Civil Services (Temporary Service) Rules, 1965, I, A. Parameswaran, Divisional Engineer, Telegraphs, Palghat hereby terminate forthwith the services of Shri N. Rajendran, Telephone Operator, Alathur Exchange and direct that he shall be entitled to claim a sum equivalent to the amount of his pay plus allowances for the period of notice at the same rates at which he was drawing them immediately before the termination of his service, or, as the case may be, for the period by which such notice falls short of one month.

[Memo. No. X/82/TMN/3]

का०आ० 3000—केन्द्रीय सिविल सेवाएं (अस्थायी सेवाएं) नियम 1965 के नियम 5 के उपनियम (1) के परन्तुक के अनुसरण मे मैं ए० परमेश्वरन, मंडल इंजीनियर तार, पालक्काड एतद्द्वारा श्री यू०पी० नरेन्द्रनाथ, टेलीफोन आपरेटर, टेलीफोन केन्द्र कोडुवायूर की सेवाएं तत्काल समाप्त करता हूं और निदेश देता हूं कि वह सेवा समाप्ति के तुरन्त पहले जिस दर पर वेतन तथा भत्ते प्राप्त करता था उस दर पर, यथास्थिति नोटिस की अवधि तक का या ऐसा नोटिस एक महीने से जितने दिन के लिए कम पड़ता है उतने दिन तक का भत्ताओं सहित वेतन का दावा करने के लिए हकदार होगा ।

[सं० एक्स/82/टी०एम०एन०/6]

ए० परमेश्वरन मंडल इंजीनियर, तार

Order of termination of service issued under the proviso to sub-rule (1) of Rule 5 of the Central Civil Services (Temporary Service) Rules, 1965.

S.O. 3000—In pursuance of the proviso to sub-rule (1) of Rule 5 of the Central Civil Services (Temporary Service) Rules, 1965, I, A. Parameswaran, Divisional Engineer, Telegraphs, Palghat hereby terminate forthwith the services of Shri U. P. Narendranath, Telephone Operator , Koduvayur Exchange and direct that he shall be entitled to claim a sum equivalent to the amount of his pay plus allowances for the period of notice at the same rates at which he was drawing them immediately before the termination of his service, or, as the case may be, for the period by which such notice falls short of one month.

[Memo No. X/82/TMN/6]

A PARAMESWARAN, Divisional Engineer Telegraphs

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय

(पुनर्वास विभाग)

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 1982

का०आ० 3001— निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम 1950 (1950 का 31) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा हरियाणा सरकार के पुनर्वास विभाग में श्री ओ० पी० तनेजा, संयुक्त सचिव (पुनर्वास) को उक्त अधिनियम द्वारा उसके अधीन सहायक मंडल निरीक्षक को सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करने के लिए तत्काल प्रभाव से सहायक अभिरक्षक, निष्क्रान्त सम्पत्ति के रूप मे नियुक्त करती है ।

इससे विनांक 11 फरवरी, 1982 की अधिसूचना सं० 1(8)विशेष सैल/77- एस०एस-2 (क) का अधिक्रमण किया जाता है ।

[सं० 1 (14)/विशेषसैल/82-एस०एस०-2 (क)]

MINISTRY OF SUPPLY AND REHABILITATION

(Department of Rehabilitation)

New Delhi, the 30th July, 1982

S O. 3001.—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Administration of Evacuee Property Act, 1950 (XXXI of 1950), the Central Government hereby appoints Shri O. P. Taneja, Joint Secretary (Rehabilitation) in the Rehabilitation Department, Government of Haryana, as Assistant Custodian General of Evacuee Property for the purpose of discharging the duties imposed on such Assistant Custodian General by or under the said Act with immediate effect.

This supersedes Notification No. 1(8)/Spl-Cell/77-SS.II(A) dated 11th February 1982.

[No. 1(14)/Spl. Cell/82-SS.II(A)]

का० आ० 3002—विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम 1954 (1954 का 44) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा हरियाणा राज्य के पुनर्वास विभाग मे संयुक्त सचिव, श्री ओ०पी० तनेजा को उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन बंदोबस्त आयुक्त को सौंपे गए कार्यों को निष्पादित करने के लिए बन्दोबस्त आयुक्त के रूप में नियुक्त करती है ।

2 इससे इस विभाग की अधिसूचना संख्या 1 (14)/विशेष सेल/82 एस एस-2 (ए) दिनांक 19 2 82 का अधिक्रमण किया जाता है ।

[संख्या 1(15)/विशेष सेल/82-एस०एस-2 (ए)]

महेन्द्र कुमार कपाल, अवर सचिव

S.O. 3002.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954), the Central Government hereby appoints Shri O. P. Taneja, Joint Secretary in the Rehabilitation Department in the Government of Haryana, as Settlement Commissioner in the State of Haryana for the purpose of performing the functions assigned to a Settlement Commissioner by or under the said Act.

This Notification supersedes Notification No. 1(14)/Spl. Cell/75-SS.II, dated the 19th February, 1981.

[No. 1(15)/Spl Cell/82-SS.II.(A)]
M. K. KANSAL, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 1982

का०आ० 3003—विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44) की धारा 34 की उप-धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त इसके द्वारा हरियाणा सरकार के पुनर्वास विभाग में संयुक्त सचिव, श्री ओ० पी० तनेजा को, जो बन्दोबस्त आयुक्त की शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं उक्त अधिनियम की धारा 23, 24, 28 और 35 के अधीन, हरियाणा राज्य में ग्रामीण एवं शहरी निष्क्रांत भूमियों और सम्पत्तियों के बारे में शक्तियों के प्रयोग के संबंध में अपनी शक्तियां सौंपते हैं।

इससे दिनांक 19 फरवरी, 1981 के आदेश सं० 1(14)/विशेष सेल/75-एस०एस०-2 का अधिक्रमण किया जाता है।

[सं० 1(15)/विशेष सेल/82-एम०एस०-2 (बी)]

ORDER

New Delhi, the 30th July, 1982

S.O. 3003.—In exercise of the powers conferred on the Chief Settlement Commissioner by sub-section (2) of Section 34 of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954), the Chief Settlement Commissioner hereby delegates to Shri O. P. Taneja, Joint Secretary in the Rehabilitation Department of the Government of Haryana, exercising the powers of Settlement Commissioner, the powers conferred on the Chief Settlement Commissioner under section 23, 24, 28 and 35 of the said Act, in so far as such powers may be exercised in respect of rural and urban evacuee lands and properties situated in Haryana State.

Tis order supersedes Order No. 1(14)/Spl. Cell/75-SS.II, dated the 19th February, 1981.

[No. 1(15)/Spl. Cell/82-SS.II(B)]

का०आ० 3004—विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर और पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44) की धारा 34 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा राज्य के पुनर्वास विभाग में संयुक्त सचिव, श्री ओ०पी० तनेजा को, जो बन्दोबस्त आयुक्त की शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं, फरीदाबाद में मुआवजा पूल की सरकार द्वारा निर्मित परिसंपत्तियों और निष्क्रांत संपत्तियों के निपटान के लिए, जिन्हें प्रशासनिक और वित्तीय व्यवस्था के अन्तर्गत हरियाणा सरकार को हस्तांतरित किया गया है, उक्त अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम सं० 87, 88, 90 (1) क, 90 (1) (ख), 90(11), 90(12) और 101 के अधीन प्रदत्त शक्तियां सौंपते हैं।

2 इससे दिनांक 2 नवम्बर, 1981 की अधिसूचना सं० 1(14)/विशेष सेल/75-एम एस-2 का अधिक्रमण किया जाता है।

[सं० 1(15)/विशेष सेल/82-एम एस2(सी)]

एस०के० बसु, मु० बन्दोबस्त आ०

S.O. 3004.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 34 of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954), the Chief Settlement Commissioner hereby delegates to Shri O. P. Taneja, Joint Secretary, Rehabilitation Department, Government of Haryana, exercising the powers of the Settlement Commissioner his powers under rules 87, 88, 90(1)(a) 90(1)(b), 90(11), 90(12) framed under the said Act, for the purpose of disposal of all lands and properties in Faridabad forming part of the Compensation Pool, transferred to the Government of Haryana, under administrative and financial arrangements.

2. This supersedes notification No. 1(14)Spl.Cell/75-SS.II, dated the 2nd November, 1981.

[No. 1(15)/Spl.Cell/82-SS.II(C)]
S. K. BASU, Chief Settlement Commissioner

श्रम मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 13 मई, 1982

का०आ० 3005—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में भारतीय खाद्य निगम, नालागोंडा के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान है,

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है,

अतः, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री बी०प्रसाद राव होंगे जिनका मुख्यालय हैदराबाद में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है।

अनुसूची

"क्या भारतीय खाद्य निगम के प्रबंधतंत्र को 110 श्रमिकों की, जिनके नाम उपाबंध में वर्णित है, सेवाओं को उक्त उपाबंध में प्रत्येक के सामने वर्णित तारीखों से समाप्त करने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो संबंधित कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं ?"

उपाबंध

1	2
सर्वश्री	
1 आरिफ अहमद	28-7-81
2. ए० मोहन रेड्डी	,,

1	2
3. मोहम्मद यूशुफ अली	28-7-81
4. के० राम मोहन	,,
5. जे० चन्द्रय्या	,,
6. डी० लोकनाथन	,,
7. मो० बाबर	,,
8. के० करनाकर	,,
9. मो० जहांगीर	,,
10. मो० जामीमियां	,,
11. वी० किशन	,,
12. बी० बसवैय्या	,,
13. बी० अशोक	,,
14. मो० ख्वाजा, मुईनउद्दीन	,,
15. एन० सैवुलु	,,
16. मो० सलीम	,,
17. पी० दुर्गाप्रसाद	,,
18. मो० गौस	,,
19. के० थोडन्न रेड्डी	,,
20. मो० इस्माइल	,,
21. जी० लिंगैया	,,
22. ए० शेषीया	,,
23. पी० पनमैय्या	,,
24. मो० महबूब खां	,,
25. मो शेशगिरि राव	,,
26. एस० विषणम	,,
27. एन० नागभूषणम	,,
28. एन० सत्यनारायण	,,
29. चो० मरसिंह	,,
30. ई० सत्यनारायण	,,
31. के० अंजयया	,,
32. एन गुर्वशन रेड्डी	,,
33. एस०पी० राजू	,,
34. एस० लतीफ	,,
35. के० के० राम राव	,,
36. ए० मत्ता माले	,,
37. के० मोहन रेड्डी	,,
38. पी० कृपय्या	,,
39. मो० फकीरुद्दीन	,,
40. मो० हबीबुद्दीन	,,
41. जी० रामा लिंगपया	,,
42. जी० समियाल	,,
43. सैयद ख्वाजा मियां	,,
44. सैयर अहमद हुसैन	,,
45. वी० रामूलू	,,
46. जी० कोलैय्या	,,
47. बी० रामास्वामी	,,
48. एन० लाजारेस	,,
49. मो० अमीर अफखां	,,
50. एस० बोयोजू	,,
51. पी० कोरनल	,,
52. के० मिक्षमय्या	,,
53. चो० येलेश	,,
54. के० सुन्दर राव	,,
55. चो० नागेश्वर राव	,,
56. डी० रूबेम	,,
57. डी० रैयल	,,
58. एम० लिंगया	,,
59. डी० नगय्या	28-7-81
60. डी० नागेश्वर राव	,,
61. के० मुरारी	,,
62. वी० अजय्या	,,
63. टी० रंगाचारी	,,
64. जी० गुरुय्या	,,
65. शेख मो० अली	,,
66. एम० राजैय्या	,,
67. पी० नरमय्या	,,
68. नजीर अहमद	,,
69. ई० सिरुपतय्या	,,
70. जे० सुबाराव	,,
71. मो० बशीरुद्दीन	,,
72. के० रामूलू	,,
73. जी० वीरस्वामी	,,
74. ए० प्रताप	,,
75. वाई० स्वर्ण कुमार	,,
76. एस० नरसिंहुलु	,,
77. टी० पुलैय्या	,,
78. पी० मरसिंय्या	,,
79. बी० नरेंद्रचारी	,,
80. के० जान	,,
81. ई० सेदुलु	,,
82. पी० प्रसाद	,,
83. चो० श्रीनिवासचारी	,,
84. एम०ए० राउफ	,,
85. ए० कुलाशेखर	,,
86. वी० नागेश्वर राव	,,
87. आर० लज्जार	,,
88. मो० जाफर	,,
89. एल० राजारत्नम	,,
90. एस० के० बाबू	,,
91. वी० कृष्णय्या	,,
92. बी० गोपाल राव	,,
93. मो० अफजल हुसैन	,,
94. एम० नरसिंह	,,
95. चो० प्रकाश	,,
96. एम० नरसिंह राव	,,
97. डी० सत्यनारायण	,,
98. चो० प्रताप	,,
99. एम० शिवलिंगम	,,
100. जी० नरसिंह	,,
101. मो० ख्वाजा मोईनउद्दीन	,,
102. बी० वेंकन्ना	31-12-77
103. जी० वेंकटय्या	28-7-81
104. शेख जान मियां	27-7-81
105. शमसुद्दीन	15-7-81
106. हसन अहमद	15-7-81
107. आर० यदुगिरी राव	28-7-81
108. मो० मकबूल पाशा	28-7-81
109. मो० अबदुल गनी	28-7-81
110. मो० सिद्दीकी	23-2-81

[सं० एल-42011(27)/81-डी-4ए]

टी०बी० सीतारमन, डैस्क अधिकारी

MINISTRY OF LABOUR

ORDER

New Delhi, the 13th May, 1982

S.O. 3005.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the Food Corporation of India, Nalgonda and their workmen in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed ;

And, Whereas, the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 7A, and clause (d) of sub section (1), of section 10, of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an industrial Tribunal of which Shri B. Prasada Rao, shall be the Presiding Officer with headquarters at Hyderabad and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

"Whether the management of Food Corporation of India, Nalgonda is justified in terminating the services of 110 workmen, whose names have been mentioned in Annexure with effect from the dates mentioned against each in the said Annexure ? If not, to what relief are the concerned workmen entitled ?"

ANNEXURE

1.	Shri Aroef Ahmed	28-7-81
2.	,, A. Mohan Reddy	,,
3.	,, Md. Yousuf Ali	,,
4.	,, K. Ram Mohan	,,
5.	,, J. Chandraiah	,,
6.	,, D. Lokanadham	,,
7.	,, Md. Babar	,,
8.	,, K. Karnakar	,,
9.	,, Md. Jahangir	,,
10.	,, Md. Janimia	,,
11.	,, V. Kishan	,,
12.	,, B. Basavaiah	,,
13.	,, B. Ashok	,,
14.	,, Md. Khaja Moinuddin	,,
15.	,, N. Saidulu	,,
16.	,, Md. Saleem	,,
17.	,, P. Durgaprasad	,,
18.	,, Md. Gouse	,,
19.	,, K. Kondal Reddy	,,
20.	,, Md. Ismail	,,
21.	,, G. Lingaiah	,,
22.	,, A. Sheshaiah	,,
23.	,, P. Panmaiah	,,
24.	,, Md. Mahaboob Khan	,,
25.	,, M. Sheshagiri Rao	,,
26.	,, S. Biksham	,,
27.	,, N. Nagabooshanam	,,
28.	,, N. Sathyanarayana	,,
29.	,, Ch. Narsimha	,,
30.	,, E. Sathyanarayana	,,
31.	,, K. Anjaiah	,,
32.	,, N. Sudharshan Reddy	,,
33.	,, S.P. Raju	,,
34.	,, S. Latheef	,,
35.	,, K.K. Ram Rao	,,
36.	,, A. Matta Malle	,,
37.	,, K. Mohan Reddy	,,
38.	,, P. Krishnaiah	,,
39.	,, Md. Faquiroddin	,,
40.	,, Md. Habeebuddin	,,
41.	,, G. Rama Lingaiah	23-7-81
42.	,, G. Samial	,,
43.	,, Syed Khaja Miya	,,
44.	,, Syed Ahmed Hussain	,,
45.	,, V. Ramulu	,,
46.	,, G. Kotaiah	,,
47.	,, B. Rama Swamy	,,
48.	,, N. Lazarace	,,
49.	,, Md. Anjer Afkhan	,,
50.	,, S. Boyoju	,,
51.	,, P. Kernel	,,
52.	,, K. Bikshamaiah	,,
53.	,, Ch. Yellesh	,,
54.	,, K. Sunder Rao	,,
55.	,, Ch. Nageshwar Rao	,,
56.	,, D. Rubben	,,
57.	,, D. Rayol	,,
58.	,, M. Lingaiah	,,
59.	,, D. Nagaiah	,,
60.	,, D.Nageshwar Rao	,,
61.	,, K. Murahari	,,
62.	,, B. Anjaiah	,,
63.	,, T. Ranga Charry	,,
64.	,, G. Gurvaiah	,,
65.	,, Sk. Mahaboob Ali	,,
66.	,, M. Rajaiah	,,
67.	,, P. Narsaiah	,,
68.	,, Nazeer Ahmed	,,
69.	,, E. Thirupathaiah	,,
70.	,, J. Subba Rao	,,
71.	,, Md. Basheeruddin	,,
72.	,, K. Ramulu	,,
73.	,, G. Veera Swamy	,,
74.	,, A. Prathap	,,
75.	,, Y. Srawan Kumar	,,
76.	,, L. Narsimhulu	,,
77.	,, T. Pullaiah	,,
78.	,, P. Narsaiah	,,
79.	,, B. Narendra Chary	,,
80.	,, K. Jan	,,
81.	,, E. Saidulu	,,
82.	,, P. Prasad	,,
83.	,, Ch. Srinivasa Chary	,,
84.	,, M.A. Raoof	,,
85.	,, A. Kula Shekar	,,
86.	,, V. Nageshwar Rao	,,
87.	,, R. Lazzar	,,
88.	,, Md. Jaffar	,,
89.	,, L. Rajarathnam	,,
90.	,, S.K. Babu	,,
91.	,, V. Krishnaiah	,,
92.	,, B. Gopala Rao	,,
93.	,, Md. Afzal Hussain	,,
94.	,, M. Narsimha	,,
95.	,, Ch. Prakasha	,,
96.	,, M. Narasinga Rao	,,
97.	,, D. Sathyanarayana	,,
98.	,, Ch. Prathap	,,
99.	,, M. Sivalingam	,,
100.	,, G. Narisimha	,,
101.	,, Md. Khaja Moinuddin	,,
102.	,, K. Venkanna	31-12-87
103.	,, G. Venkataiah	28-7-81
104.	,, Sk. Janimia	27-7-81
105.	,, Sk. Shamsuddin	15-7-81
106.	,, Sk. Hasan Ahmed	15-7-81

107.	Sari R. Yadagiri Rao	28-7-81
108.	,, Md. Maqbool Pasha	28-7-81
109.	,, Md. Abdul Gani	28-7-81
110.	,, Md. Siddiquo	23-2-81

[No. L-42011(27)/81-D. IV(A]

New Delhi, the 17th August, 1982

S.O. 3006.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur in the industrial dispute between the employers in relation to the management of National Insurance Company Limited, Indore and their workmen, which was received by the Central Government on the 3rd August, 1982.

BEFORE JUSTICE SHRI S.R. VYAS (RETD.) PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (M.P.)

Case No. CGIT/LC (R) (18) 1979.

PARTIES :

Employers in relation the management of National Insurance Company Limited, Indore, and their workman Shri Ramesh Kumar Toshniwal, Assistant represented through the General Insurance Employees' Union (Western Zone), Indore Unit C/o Shri Sharad Mahajan, Nilkanth Colony, Indore-45002.

APPEARANCES :

For workman—Shri L. N. Malhotra, Advocate.

For management—Shri P. V. Pandit, Advocate.

INDUSTRY : Insurance DISTRICT : Indore (M.P.)

Dated the 22th July, 1982

AWARD

In exercise of the powers conferred by Clause (d) of subsection 1 of the Industrial Disputes Act 1947 (14 of 1947), the Central Government in the Ministry of Labour has referred the following dispute to his Tribunal for adjudication vide Notification No. L-17012 (3) /79-D. IV (A) Dated 31st July 1979 :—

'Whether the action of the Divisional Manager of National Insurance Company Limited, Indore, in fixing the basic pay of their workman, Shri Ramesh Kumar Toshniwal Assistant, at Rs. 175/ per month on his appointment on probation on the 27th April, 1976 without giving him the benefit of his past service and the Annual Grade Increments, is justified ? If not, to what relief is the concerned workman entitled ?"

2. The claim of the workman, Shri Ramesh Kumar Toshniwal, hereinafter referred to as the workman is as follows :—

The management of the National Insurance Company appointed the workman in its Divisional Office at Indore from 1st July 1974 in a permanent vacancy. Though this appointment was against a permanent vacancy it was termed as temporary appointment only. The appointment was continued upto 5-9-1974. He was again appointed on 9-9-1974 and this appointment continued upto 8-11-1974. He was again appointed on 11-11-1974 and continued upto 23-4-1976. Thus in the aforesaid appointments there were breaks of 3, 2 and 3 days respectively. Lastly, the workman was again appointed in a substantive capacity from 27-4-1976 and confirmed on 28-10-76.

3. The contention of the workman is that the aforesaid three breaks were only artificial and colourable so as to give an appearance of temporary employment to deprive the workman the rights of a continuous workman. During these temporary appointments he was initially given a consolidated pay of Rs. 150/- p.m. On confirmation as aforesaid he was granted a time scale of Rs. 175-585. The workman, therefore, claims that his appointment from the very beginning should be treated as a continuous appointment and the should be granted annual increments on 1-1-1975, 1-7-1975 and so on upto the last July 1979 and allowed all arrears and other consequential benefits.

4. The contention of the management is that this Tribunal has no jurisdiction to adjudicate upon the alleged dispute as the jurisdiction is barred by virtue of Sec. 16(5) and (7) of the General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972. It is further alleged that the Union which has raised this dispute is not competent as the concerned workman is not a member of that Union. It is also urged that according to the General Insurance (Rationalisation and Revision of Pay Scales and other Conditions of Service of Supervisory, Clerical and Subordinate Staff) Scheme, 1974, the present claim is not maintainable. As regards the nature of the appointments given to the workman, the management contends that it was in exercise of their rights that under peculiar circumstances temporary appointments were given to the workman as and when necessary; that there was no permanent post against which the workman could be appointed; that subsequently when there was a vacancy the workman was given substantive appointment on a pay admissible to the post in which he was appointed; that the terms and conditions laid down in the appointment order were voluntarily accepted by the workman without any objection and that the workman is not entitled to any relief.

5. Rejoinders were filed by both the parties in which they have maintained their pleas raised in their respective statements of claims.

6. As per order pased on 1-5-1980 the only issue that arises is that which is mentioned in the order of reference. Consequently no separate issue was framed. For the sake of convenience the issues contemplated by the order dated 1-5-1980 may be formulated as under :—

ISSUES

1. Whether the reference is not maintainable?

2. Whether the action of the Division Manager of the National Insurance Company Limited, Indore, was justified in fixing the basic wage of Shri Ramesh Kumar Toshniwal, Assistant, at Rs. 175/- per month on his appointment on 27-4-76?

3. If not, whether the management should have given the benefit of past service and annual graded increments as claimed by the workman?

4. To what relief are the parties entitled?

7. Having considered the evidence given by both the parties my findings on the aforesaid issues are as under :—

Issue No. 1.—Reference is maintainable.

Issue No. 2.—The management of the National Insurance Company Limited was not justified in fixing the pay of Shri Ramesh Kumar Toshniwal at Rs. 175/- p.m. on his appointment on 27-4-1976.

Issue No. 3.—The management of the National Insurance Company Ltd. should have given the benefit of past service and annual graded increments to the workman as claimed by him.

Issue No. 4.—As per order passed below.

8. In this case both the parties have led oral and documentary evidence which will be referred to at the relevant stage.

Reasons for the above findings :

9. Issue No. 1.—On behalf of the management nothing has been shown as to how the reference is not maintainable. All that was urged was that before the nationalisation of the General Insurance Business there were different companies carrying on insurance business in India; that before integration of all the companies into one different units were working under different names and that consequent upon the integration of the companies certain schemes referred to in the statement of claim were framed for the fixation of the pay of the employees working in different units. The Scheme envisaged rationalisation of the service conditions and pay of the staff but in my opinion all the Scheme etc. are not relevant in the present case as the workman in this case is a post nationalisation insurance employee and is not a workman employed by any company affected by the General Insurance business (nationalisation) Act. Consequently, the scheme and other provisions of the Nationalisation Act are not at all relevant in this case and they cannot govern the dispute raised by the workman in these proceedings.

10. The next contention is that the workman is not a member of the Union which has raised this dispute and consequently the reference is not maintainable. The workman was questioned in para 15 of his statement and he has made a categorical statement that from 1975 he was a member of the union which has raised this dispute. No evidence has been given to the contrary by the management. Consequently, in view of the fact that the workman is a member of the Union which has raised this dispute, it cannot be said that the reference at the instance of the union is not maintainable. Issue No. 1 is accordingly answered against the management.

11. Issue No. 2.—It is not disputed that but for the three breaks in appointments i.e. from 6th to 8th September, 1974, 9th and 10th November, 1974 and 24th to 26th April, 1976, the workman was in the employment with the management on a consolidated salary of Rs. 150 per month. It may be mentioned here that later on the management has given him salary for the aforesaid period i. e. from 1st July, 1974 to 23rd of April, 1976 except for the three breaks mentioned above. The salary applicable to the post. The question is as to how this service with colourable breaks, according to the workman, and that the real breaks according to the management, has to be treated.

12. It cannot be disputed that on 27-4-1976 when the management gave the workman a substantive appointment vide appointment letter Ex. E/11 dated 27-4-1976, the workman had been in service from 1-7-1974 including the aforesaid three breaks. Before his appointment vide Ex. F/11 on 27-4-1976 the workman had already completed 240 days as an employee of the management. Even the last period of appointment from 11th November, 1974 to 23rd April, 1976 had exceeded 240 days. Consequently, in the light of the decision of their Lordship of the Supreme Court in Mohanlal Vs. Bharat Electronics (AIR 1981 SC. p. 1255) the workman had acquired the status of continuous workman. The management, therefore, could not terminate his service without proper compliance of the Industrial Disputes Act regarding the payment of retrenchment compensation. Since there was no such compliance the workman has to be deemed in continuous service.

13. As regards the affect of the temporary breaks, the workman contends that though in official records there were temporary breaks recorded by the management but in fact he had been discharging his duties on the post on which he was appointed. He has referred to certain documents Ex. E/1, E/12, E/19, F/16 and F/17 which are said to be in his handwritings and are of the break periods. These documents, according to the workman, show that though officially he was shown as being not an employee during the break periods yet for all practical purposes he was discharging his duties as usual.

14. The management's witness (MW. 1) Babulal Gupta has stated that since there was no post vacant the workman was given only temporary appointments to cope up with the additional work in the office and that he was given permanent appointment only when a post was sanctioned. I fail to understand as to how there should have been burden on the official work from July, 1974 to April, 1976 continuously but for the broken periods referred to above. It appears that the management deliberately gave artificial breaks to the appointments given to the workman so that he can be deprived of the status of a continuous workman if and when such a status is claimed by him. What is the effect of such artificial and colourable breaks has been considered in S. K. Verma Vs. CGIT (AIR 1981 SC. p. 423) as also in State Bank of India Vs. N. Sundermony (AIR 1976 SC. p. 1111). In this connection, a reference may also be made to the decision in S. K. Gupta Vs. Bank of Patiala (AIR 1980 SC p. 1819). In all these cases, it has been held that once in a calendar year the workman completes 240 working days he acquires the status of a continuous workman. In the instant case, the workman had been in employment from July 1974 to 27-4-1976 but for the three breaks (1) for 3 days in September 1974, (2) 2 days in November 1974 and (3) for 3 days in April 1976. Thus he had, as already stated above, completed more than 240 days before he was given the so called substantive appointment on 27-4-1976. The breaks, as already stated above, were all colourable and artificial and were given only with a view to deprive the workman of acquiring the status of a continuous workman. Such breaks cannot come in the way of the workman's right which he was earned by completing 240 days working. Accordingly the workman should be deemed to be in service from 1-7-1974. Consequently, it is held that the management of the National Insurance Company Limited, Indore, Divisional Manager's Office, was not justified in fixing the pay of the workman at Rs. 175 per month from 27-4-1976.

15. Issue No. 3.—As a consequence of the findings given on Issue No. 2, it has to be held that the management was bound to give the benefit of past service from 1-7-1974 to the workman while fixing his pay on his appointment on 27th April, 1976. The management shall therefore fix his pay on 27-4-1976 on the basis that he was appointed in a substantive capacity on 1-7-1974 as an Assistant and grant him future increments as admissible under the rules to him. The workman shall also be entitled to such arrears of pay, increements etc. which may be work out on the aforesaid basis.

16. Issue No. 4.—The workman is entitled to the relief mentioned above. Accordingly for the reasons given above, it is directed that the management shall fix the pay of the workman, Shri Ramesh Kumar Toshniwal, on the basis that he was in continuous service in substantive capacity from 1-7-1974. His pay on the aforesaid basis shall be fixed in accordance with the time scale of pay applicable to the post on which he was formally appointed on 27-4-1976. Further his pay on 27-4-1976 shall be fixed on the aforesaid basis with all previous increments earned by him after 1-7-1974. Arrears of pay and increments on the basis of such fixation shall also be paid to him. In the circumstances of the case, both the parties are directed to bear their own costs as incurred.

Sd/-
S. R. VYAS, Presiding Officer
[No. L-17012/3/79/D.IV(A)]

New Delhi, the 18th August, 1982

S.O. 3007.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 2, Bombay in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Messrs Sanghavi Brothers, Bombay and their workmen, which was received by the Central Government on the 31st July, 1982.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. ?

PRESENT :

Shri M.A. Deshpanda, Presiding Officer.

Reference No. CGIT-2/12 of 1982

PARTIES :

Employers in relation to the Management of Messrs Sanghavi Bros. Bombay.

AND

Their Workman

APPEARANCES :

For the Employers—No appearance.

For the workmen —No appearance.

INDUSTRY : Ports & Docks STATE : Maharashtra

Bombay, dated the 19th July, 1982

AWARD

By order No. L-31012 (17)|81 D. IV (A) dated 19-2-1982 the Central Government has referred the following dispute for adjudication under Section 10 (1) (d) of the Industrial Disputes Act, 1947 :—

"Whether the action of the management of Messrs Sanghavi Bros., Bombay in terminating the services of Sarvashri S. H. Jainullah, Jaifulla Mainulla and Tawakullah Mainulla, Watchmen, is justified ? If not, to what relief are the concerned workmen entitled ?"

2. The dispute relates to the termination of services of three workmen by the management of Messrs Sanghavi Bros., Bombay, but despite several attempts neither the management could be traced nor the union has filed any statement of claim justifying the reference. In these circumstances there is no other go but to reject the reference.

Award accordingly,
No order as to costs.

Sd/-

M. A. DESHPANDE, Presiding Officer
Central Govt. Industrial Tribunal No. 2 Bombay.

[No. L-31012/17/81-D. IV (A)]

T. B. SITARAMAN, Desk Officer

New Delhi, the 9th August, 1982

S.O. 3008.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Bombay, in the industrial dispute between the employers in relation to the Food Corporation of India, Nagpur and their workmen, which was received by the Central Government on the 30th July, 1982.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, BOMBAY

Reference No. CGIT-2/5 of 1980

PARTIES :

Employers in relation to the Food Corporation of India.

AND

Their workmen

APPEARANCES :

For the Employers—1. Shri J. J. Srivastava, Dy. Manager (Legal). 2. Shri P. V. Balakrishnan Dy. Manager (QC). 3. Shri M. B. Sarvodaya, Asstt. Manager (QC).

For the workmen—1. Shri G. R. Gondre, 2. Shri P. Gondane, Bharatiya Khadya Nigam Kamgar Sangh.

INDUSTRY : Food Corporation STATE . Maharashtra.

Bombay, dated the 15th July, 1982

AWARD

By their order No. L-42011(39)/79 L.II(B) dated 14-4-1980 the Central Government referred the following dispute for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 :—

"Whether the demands of Food Corporation of India Employees Association, Nagpur, relating to Special Allowance of Rs. 10/- p.m. from inception of depot to the daily rated, called as Casual Labourers, engaged in Quality Control Section and Medical Assistance/Attendance on the pattern available to those regulars who work in Quality Control Section of Food Corporation of India are justified? If not, to what relief they are entitled."

2. The matters relates to the work alleged to have performed by the Casual Labourers engaged by the Food Corporation of Inda in their Quality Control Depots where the Dusting Operator who are in regular service of the Food Corporation of India are being paid special allowance of Rs. 10/- per month and these casual labourers who are alleged to be assisting the Dusting Operators and perform certain duties in the same shed or godown who come in contact with the poisonous substances and because of the hazardous nature of their work they want Special Allowance of Rs. 10/- per month and medical facilities as are made available to the regular workmen.

3. The Food Corporation of India by their written statement Exhibit 3/M have denied all these averments and contended that all the work as described by the Union in fact is performed by the Dusting Operators and because of those duties they are paid Rs. 10 per month extra and the casual labourers even posted today quality control work do not perform such hazardous duties but carry on only what is known as coolies duties.

4. Points therefore arise for determination are :—

Issues	Findings
(i) whether the casual labourers posted to perform qualify control duties do work similar to that of Dusting operator	yes
(ii) If yes whether they are entitled to extra allowance and any medical facilties	yes —Extra allowance. No —medical facility

REASONS

5. Even though at the time of evidence an attempt was made to suggest that Dusting Operators are paid Rs 10/- by way of spcial Allowance although the duties are not hazardous, the written statement of the Food Corporation of India Ex. 3/M in clear terms admitted in paragraphs 2 and 3 thereof that because of handling of chemicals etc. by the Dusting Operators they are being paid Rs 10/- by way of special pay per month. The suggestion that the Special Allowance is granted as and incentive to attract the employees of lower cadre to accept the posting of Dusting Operator must fail. Furthermore, if the watchmen, Sweepers, shifters are not prepared to accept a post carrying Rs. 10/- extra, it means that they must have their own reason and though the witness for the Food Corporation tried to suggest thereby the employees in the lower cadre lose their overtime, the reasons must be as suggested by the Union.

6. What is then the nature of the duties performed by the casual labourers, whether similar to the work undertaken by the Dusting Operators or they merely worked as

coolies rendering the assistance to those regular employees? In fact having regard to the circumstances namely the casual labourers are in the service of the Food Corporation of India from 1974-75 onwards, the designation as casual labourers is itself misnomer and they are nothing else but regular employees, and the said status might be to avoid giving various benefits. On behalf of the Union there are two witnesses who have described the nature of the duties performed by the casual labourers namely Shri P. Gondane and Shri G. R. Gondre and both have asserted that the casual labourers are performing the same duties as are done by the regular employees, namely the Dusting Operators like cover fumigation, spray pesticides and salvaging. They also say that because they are required to work in a packed shed, they suffer physically yet for want of medical facility they had to approach the private Doctor. Against this the Assistant Manager of the Food Corporation of India when examined tried to reiterate the plea as raised in the written statement but in cross-examination he has admitted these casual labourerrs assist the Dusting Operators in the work of salvaging, spraying and fumigation and that they work in the same shed where the Dusting Operators work. There is further admission that the duties performed by the casual labourers are entered in the register but no such register has come forward meaning thereby that the entries therein might not be supporting the Corporation. The two witnesses examined by the Union claimed to have actually worked in the Quality Control Section though in rotation and they have described the material facts of the handling of pesticides and fumigants. I do not think that any imagination is necessary for assessing the chemical effects which is a matter of common experience especially when residential houses are fumigated or sprayed. Having regard to the admissions of the Assistant Manager and further having regard to the nature of the duties performed by the casual labourers who work side by side with the Dusting Operators, I do not think that there is any justification in denying the casual labourers of the special alowance, merely because, though they work, under the Food Corporation of India for several years have not been absorbed in the regular duties but still kept as casual labourers.

7. The Dusting Operators get Rs. 10/- per month by way of special allowance and there is no difficulty in calculating because they are in regular employment. Such may not be the case with the Casual labourers who are required to work in Quality Control Section only on rotation basis. No order therefore can be passed to pay Rs. 10/- per month as in other case, but since they are still termed as casual labourers and since there must not be any fixed number of days in the rotation for work in Quality Control Section, at the same time having justified the demand, the only order which is possible is that those casual labourers who are asked to work in Quality Control Section and required to assist the Dusting Operators shall be paid 33 paise per day for the period of their work in the Quality Control Section.

8. From the oral evidence of the witnesses of the Union although there is grievance regarding absence of medical facilities there is nothing to show that any of the casual labourers or to that effect even the Dusting Operators suffered physically requiring medical attention. Even the superior officers are present and had there been any mal-effect, the presence of the superior officers could not have been noticed. Therefore the prayer regarding medical facility has to be rejected.

9. The result is that the demand of special allowance at the rate of 33 paise per day when any casual labourer works in Quality Control Section is held to be justified but not the demand for medical facility. The Food Corporation shall pay the special allowance at this rate from the date of this Award.

Award accordingly.

No order as to costs.

Sd/-
M. A. DESHPANDE, Presiding Officer

[No. L-42011(39)/79-D.II(B)]

S.O. 3009.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Nagpur Telephone District and their workman, which was received by the Central Government on the 30-7-72

BEFORE JUSTICE SHRI S. R VYAS (RETD.) PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (M.P.)

1. Case No. CGIT/LC(R) (10)/1982

(Ministry's Reference Order No. L-40012 (8)-78-B.II.D) dated 29th January 1982)

2. Case No. CGIT/LC(R) (11)/1982

(Ministry's Reference Order No. L-40012(8)/78-B.II.D) dated 30th January, 1982)

PARTIES :

Employers in relation to the management of Nagpur Telephone District and their workman Shri Manoranjan Hiranji Kothare, Gorewada P.O. (C.P.W.D. Quarters), Nagpur-440013.

APPEARANCES :

For workman—None.

For Management—None.

INDUSTRY : Telegraph DISTRICE : Nagpur (M.S.)

Dated : July 26, 1982

AWARD

By an order dated 29-1-82 the Government of India in the Ministry of Labour has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the management of Nagpur Telephone District under the control of District Maanger, Telephones, Nagpur, in stopping from work Shri Manoranjan Hiranji Kothare, with effect from 3-2-1977 is legal and justified? If not, to what relief he is entitled?"

2. By another order dated 30-1-1982 the aforesaid dispute was referred to this Tribunal for adjudication. Therefore this award will also govern Reference Case No. 11/1982.

3. It is evident that an identical dispute between the management of the Nagpur Telephones under the control of the District Manager (Telephones) Nagpur has been referred by two separate orders one dated 29-1-1982 and the other dated 30-1-1982. As the dispute was identical though referred to by two different orders bearing the same number two notices were issued to both the parties to file their statements of claims. Notices were served on both the parties. As the workman did not appear on the service of tht first notice, a fresh notice was issued. The first notice was received on 12-4-1982 and the other was received on 20-5-1982. In response to neither of these two notices the workman came forward. Consequently, no statement of claim was filed by the workman.

4. In the notice issued by this Tribunal to both the parties they were directed to file the statements of claims and served copies thereof on the otherside. A date for filing rejoinders with a copy to the other side was also fixed. Only the management of the Telephones Department sent by post a statement stating that since the copy of the statement of the workman was not received they were unable to file the statement of claim. Even thereafter no statement of claim was filed either by the workman or by the management of the Telephones Department. The result was that since that date neither the statement of claims nor rejoinders nor documents were filed by the parties. In these circumstances the references were reserved for award.

5. From the order of reference it appears that the dispute between the parties was with regard to stopping from work Shri Manoranjan Hiranji Kothare with effect from 3-2-1977. The workman has not come forward to give details as regards the circumstances in which he was stopped from work by the management of the Nagpur Telephone District. The management have also not filed any statement to indicate as to how, for what reasons and in what circumstances, the workman was or was not stopped from working in the Department. In these circumstances, the only inference to be drawn is that there is no subsisting dispute between the parties which requires adjudication by this Tribunal. Consequently, the reference has to be answered as under :—

"As there is no subsisting dispute between the parties with regard to the alleged stopping from work of the workman, Shri Manoranjan Harmanji Kothare, no adjudication is called for Reference is answered accordingly."

S. R. VYAS, Presiding Officer

[No. L-40012(8)/78-D.II(B)]

S.O. 3010.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Posts and Telegraphs Department, Divisional Telegraph Office Nagpur, and their workman, which was received by the Central Government on 3-6-82.

BEFORE JUSTICE SHRI S. R. VYAS (RETD.) PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, JABALPUR (M.P.)

Case No. CGIT/LC(R)(46)/1981

PARTIES :

Employers in relation to the management of Posts and Telegraph Department, Divisional Telegraph Office, Nagpur Division, Nagpur and their workman Smt. Bhojabai, Waterman-cum-Farash-cum-Sweeper, represented through the All India Posts and Telegraph Traffic Karamchari Sangh, Nagpur Division, C/o D.T.O. Nagpur City (M.S.)

APPEARANCES :

For workman—Shri P. S. Nair, Advocate.

For Management—Shri K. K. Adhikari, Advocate.

INDUSTRY : Post and Telegraphs DISTRICT : Nagpur (M.S.)

Dated the July 26, 1982

AWARD

This is a reference made by the Government of India in the Ministry of Labour, vide Notification No. L-40012(1)/78-D.II(B) dated 31st December, 1981, for the adjudication of the following dispute by this Tribunal :—

"Whether the action of the Post and Telegraph Department (Divisional Telegraph Office) Gandhibagh, Nagpur in treating Smt. Bhojabai, Waterwoman-cum-Farash-cum-Sweeper as casual employees, and allowing her wages and other service conditions accordingly in spite of her 19 years service, since August, 1958 in the Department is fair and justified ? If not, to what relief is the employee entitled ?"

2. Briefly stated the facts giving rise to this reference are these. Smt. Bhojabai, the workman concerned, hereinafter referred to as the workman, was appointed as a Partime Employee in the capacity of a Waterwoman-cum-Farash-cum-Sweeper on 1-9-1958 in the Central Telegraph Office Nagpur under the management of the Divisional Telegraphs Engineer's Office Nagpur on a daily wages of Rs. 3 which was subsequently raised to Rs. 5.

3. The grievance of the workman is that though she has been discharging her duties as a Waterman-cum-Farash-cum-Sweeper since 1958 even then the department has not considered her claim for regular appointment even though she has been continuously working for 8 hours per day. She made a number of representations to the department but her claim remained unsatisfied. She has, therefore, prayed for her regularisation from the date of her first appointment.

4. The claim put forward by the Divisional Engineer is that the Post and Telegraphs Department is not an industry hence the provisions of the Industrial Disputes Act do not apply in the present case; that the workman has been working on the post of Waterwoman-cum-Farash-cum-Sweeper as a contingent employee purely on daily wages that at the time of the first appointment the workman neither got herself registered with the Employment Exchange nor the employment Exchange recommended her name; that under the Departmental rules such registration and recommendation are obligatory for substantive appointment; that at the time of her first appointment the workman was 34 years of age i.e. she had crossed the maximum permissible age of 30 years; that as and when the worker applied for absorption on the regular establishment her applications were duly considered and rejected; that the workman being illiterate was not eligible to the appointment to the Class IV post either of a Sweeper or Aayya; that the workman was again asked to produce certificate about her being a member of the Scheduled Castes but no such certificate was produced; that the Union which has espoused the cause of the applicant is not competent to do so as the workman is only a part time workman and is not a member of the Union and that in these proceedings the workman is not entitled to any relief.

5. Rejoinder was filed only by the Post and Telegraphs Department in which the allegations made by the worker in her statement of claim about fresh appointments in 1962 were denied. It was further alleged that since after the workman started working on daily wages on a casual basis no post had fallen vacant in Class IV on which she could be appointed and that for the reasons already stated in the statement of claim filed earlier the workman could not and should not be regularised on any post in the Department.

6. On these rival claims of both the parties the following issues were framed on 14th April, 1982 :—

Issues :

1. Whether on the facts and circumstances of this case the management of P&T Department (Divisional Telegraph Office, Nagpur) was justified in treating the workman Smt. Bhojabai Ramteke as a casual employee inspite of her continuous service from August 1958 ?

2. To what relief is the workman entitled ?

Oral and documentary evidence was given by the workman only. Post and Telegraphs Department filed certain copies of Government orders etc. as annexure to the statement of claim and rejoinder. However, no oral evidence was given.

7. I have considered the evidence of both the parties. My findings on the aforesaid issues are as under :—

Issue No. 1.—The management of the Post and Telegraphs Department (D.H.T. Office Nagpur) was not justified in treating Smt. Bhojabai Ramteke as a casual employee in spite of her continuous service from August 1958.

Issue No. 2.—Smt. Bhojabai Ramteke, workman, in this case is entitled to be regularised and also entitled to payment of back wages on the lowest post in the aforesaid office from the date when a permanent post at the lowest grade had fallen vacant.

Reasons for the above findings :

8 Issue No 1.—In her statement it is stated by the workman that ever since her first appointment she has been working continuously for the last 24 years and discharging the duties of a Sweeperess and Waterwoman. Her duty hours were 8 hours per day and she was paid firstly Rs. 3 per day and then Rs. 5 per day without any holiday. She also says that she was registered in the Employment Exchange and at the time of her first appointment her name was recommended to the Post and Telegraphs Department by the Employment Exchange. She has in this Court produced certificates about

her being a member of the Schedule Caste as also about her date of birth. In her cross examination she said that for the first time she made her first application for her appointment in Class IV in the year 1973. She denied that at the time of her first appointment she had represented that she was 34 years of age. She said that she became member of the Union in 1961 and since then Union had also been making representations for her regular appointment W.W.-2, Shri Ramchandra Ganpatrao Dange, an Overseer in the same office said that the workman had been working for 8 hours per day in two intervals, that she was registered in the Employment Exchange and was a member of the Schedule Caste. He refers to an affidavit Ex. W/1A sworn before the Taluka Magistrate, Nagpur in which she had stated her date of birth as 14-5-1932 according to which she was 26 years of age at the time of her first appointment in 1958 He lastly states that though she and the Union represenative had been pressing the worker's claim for he regular appointment but the Department did not grant her request. He also says that the documents Ex. W/1 to W/5 were handed over by him to the Department officer when they were demanded.

9 From the aforesaid evidence, it is clear that the worker, Smt. Bhojabai, had been working continuously from August 1958 only as a casual worker. She is being paid either daily or monthly wages but she has not been absorbed against any vacant post on the permanent establishment. The fact that she is a member of the Scheduled Caste is not denied There is an application dated 12-10-1961 made by the worker addressed to the Telegraph Master Incharge duty at Nagpur in which she had prayed for being regularised. The Telegraph Master recommended her permanent appointment but it appears that the recommendation was not accepted. In the annexures filed along with the statement and rejoinder by the department there is a certificate dated 8-11-1960 (Ex M/2) in which the applicant on being referred to the Civil Surgeon her age is shown as 34 years both according to the statement of the worker as also according to her appearance. There is another letter Ex. M/5 according to which the services of one Vishwanath were terminated by the Telegraphs Department on 6-6-1961. According to Annexures 1, 2, 3, 4, and 5 which are orders passed by the Departmental Higher Authorities and the Government of India, the worker could not be regularised because she on the date of her first appointment, was not only over the prescribed age but was also not sponsored by the Employment Exchange for her appointment The workman, has, however, made a categorical statement that her name was sponsored by the Employment Exchange with which she was registered. As regards her age Annexure 6 which purports to be an entry from the Birth Register, a daughter was born to Hatia Upishya Mahar on 8-5-1932 This document has been produced by the department itself It appears that this certificate was filed by the worker when demanded by the department. If this certificate relates to the birth of the workman then at the time of her initial appointment she was only 26 years of age and not 34 years as alleged by the department.

10. However, apart from the question of age at the time of her initial appointment the fact is that the workman has been continuously in service since 1958 till date. There is no rebuttal of her statement about her discharging of duties of 8 hours per day. The relevant record of service the attendance register, the wage sheets etc have not been filed by the department. Not a single witness has been examined to deny on oath the statements made by the workman and her witness. If the workman has been continuously working from August 1958 till date then she is right in making her claim for being regularised. A workman who completes 240 days on a particular post acquires the status of a continuous workman as laid down in Mohanlal Vs. Bharat Electronics (AIR 1981 SC p. 1255). According to the recommendation of the Telegraph Master dated 12-10-1961 made on the applicant's application on the same date she was recommended for appointment on the regular establishment Even if it is assumed that the applicant's name was not sponsored by the Employment Exchange, for which also there is no evidence, it is too late for the department to contend that the worker is not entitled to be regularised even after she has put in 24 years of service. So far as the question of workman being over age at the time of her appointment is concerned, I find that she was not 34 years of age but was only 26 years as per birth certificate filed in this case. Observations of the Civil Surgeon regarding age of the applicant by appearance cannot be said to be an authentic piece of evidence about the exact age of the workman. Considering the length of service of the workman I feel she is entitled to be regularised on such vacant post in the permanent establishment as and when it had fallen vacant after the workman had completed 240 days employment in the department The department should have therefore regularised her as claimed in this case by the workman. Issue No. 1 is therefore answered against the department

11. Issue No. 2.—As regards the relief to be granted to the workman, I have already indicated as to the nature of the relief to which the applicant is found entitled. The management of the Post and Telegraphs Department (Divisional Telegraph Office Nagpur) shall within three months from the date of this award comes in force examine the case of the workman, Smt. Bhojabai, and regularise her on the lowest post in Class IV on its permanent establishment from the date when a substantive post had fallen vacant after 240 days of continuous service of the workman from August 1958. On being so regularised, the workman Smt. Bhojabai shall be entitled to all consequential benefits of an employee on the aforesaid post. An award is accordingly passed in favour of the workman as indicated above. In the circumstances of the case both parties are directed to bear their own costs as incurred.

S R. VYAS, Presiding Officer
[No. L-40012(1)/78-D.II(B)]

S.O. 3011.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Madras, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Government of India, Poduction Centre, Ettumanoor, and their workman, which was received by the Central Government on the 3-8-82.

BEFORE THIRU T. SUDARSANAM DANIEL, B.A., B.L.

(Constituted by the Government of India)

Wednesday, the 28th day of July, 1982

Industrial Dispute No 69 of 1981

(In the matter of the dispute for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the workmen and the Management of Government of India, Production Centre, Ettumanoor.)

BETWEEN

Thiru V. Gangadharan, V. G. Bhavan, Nadaivanam, Nedumparampu P.O. (Via), Alancode, Trivandrum District.

AND

The Director Government of India Production Centre, Ettumanoor.

REFERENCE

Order No. L. 42012/(15)/81-D II(B), dated 25-8-1981 of the Ministry of Labour, Government of India

This dispute coming on for final hearing on Wednesday the 21st day of July, 1982 upon perusing the reference, claim and counter statements and all other material papers on record and upon hearing the arguments of Thiru P. C. Chacko, Central Government Standing Counsel appearing for the Management and the workman being absent and this dispute having stood over till this day for consideration, this Tribunal made the following award.

AWARD

This is an Industrial Dispute between the workmen and the Management of Government of India Production Centre, Ettumanoor, Kerala State referred to this Tribunal for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 by the Government of India in Order No. L.

42012(15)/81 D.II(B), dated 25-8-1981 of the Ministry of Labour in respect of the following issue :

"Whether the Director, Government of India, Production Centre, Ettumanoor was justified in not offering re-employment to Shri V. Gangadharan and in appointing Shri Gopinathan Chettiar as Helper with effect from February, 1980, in contravention of Section 25H of the Industrial Disputes Act, 1947 ? If not, to what relief the workman is entitled?"

(2) Facts leading upto this dispute are as follows : The Management is the Director, Government of India Production Centre, Ettumanoor, Kerala State. The Government of India, Extension Centre, Attingal is a factory registered under the Factories Act and is owned by the Central Government of India. This Centre functions under the administrative control of the Director of Production Centres as Ettumanoor, who is also the appointing as well as disciplinary authority This is a permanent department of the Central Government—Central Government Small Scale Industries Development Organisation under the Ministry of Industry. This Centre is supervised by an Assistant Director Aluminium/Steel Utensils, Hospital wares etc., are produced for commercial purpose at this Centre. The aggrieved workman in the present reference made by the Government of India, Ministry of Labour is Thiru V. Gangadharan. He was engaged as a Casual Labourer from 1-4-1964 to 10-11-1968—vide Ex. W-1, the certificate issued. He was retrenched as can be gathered from Ex. W-1 for want of raw materials. It is not disputed that when he was retrenched and he was also given eligible benefits. After the retrenchment in 1968, subsequently also the workman concerned was engaged by the Management as Casual Labourer not continuously, between February, 1974 and July, 1974 as and when work could be allotted to him. It is common case that subsequent to July, 1974, the workman was not at all employed by the Management. Thiru Gopinathan Chettiar was appointed as Helper by the Management in August, 1980 in accordance with the rules of the Management. The claim of the concerned workman is that the Tribunal may be pleased to pass an order appointing him as Helper at Government of India, Extension Centre, Attingal in the place of Thiru Gopinathan Chettiar with retrospective effect

(3) In the first place, the concerned workman Thiru V. Gangadharan seeks to support his claim to be a Helper under the Management in the light of the Award rendered by Industrial Tribunal, Alleppey, Kerala State in I.D. No 1 of 1974 dated 28th June, 1975. Ex. W-3 is the typed copy of extract from the Award rendered by the said Tribunal. As a matter of fact on 13-2-1980 the workman concerned in this dispute Thiru V. Gangadharan made a representation under the original of Ex. W-4 that his retrenchment is hit by Section 25(T) of the Industrial Disputes Act, 1947 and also the Award passed by Industrial Tribunal, Alleppey. The Award extract which has been produced as Ex. W-3 related to certain casual workmen employed in the various production centres in Kerala with a direction to be absorbed in the regular scales of pay with effect from 1-1-1972. In that dispute, the Director of the Management had given a list of casual labourers entitled to the benefit of the Award and the same is marked as Ext. M-1 before this Tribunal The Management admits that the Award rendered by the Industrial Tribunal, Alleppey in I.D No 1/1974 related to 36 casual workers who are declared to be Helpers But it should be remembered that the concerned workman Thiru V. Gangadharan was not in the employment of the Management after 10-11-1968—vide Ex. W-1, but was only entertained in February, 1974. It is significant that Ex M-1 does not contain the concerned workman Thiru V. Gangadharan. Furthermore, even according to the admission of Thiru V. Gangadharan under Ex. W-4, his claim has been overlooked in the Award passed by the Industrial Tribunal, Alleppey in I.D. No. 1/1974. Looked at from any point of view, it is difficult to accept the case of the workman that he would be entitled to be reinstated as a Helper or even as a Casual Workman pursuant to the Award passed by the Industrial Tribunal, Alleppey in ID. No. 1/1974.

(4) Secondly, it is stated that the appointment of the Management of Thiru Gopinathan Chettiar as a Helper in August, 1980 is in direct violation of the right conferred on the workman concerned in this dispute, namely, Thiru V. Gangadharan under Section 25(H) of the Industrial Disputes Act, 1947. The claim put forward by Thiru V. Gangadharan is under Ex. W-4 on 13-2-1980, more than six years after his last engagement under the Management in July, 1974 The aforesaid Gopinathan Chettiar has not been made a party at any stage of the conciliation proceedings. Although the reference made by the Government of India, Ministry of Labour specifically refers to the appointment of Thiru Gopinathan Chettiar yet even in the reference Thiru Gopinathan Chettiar has not been made a party to the reference or dispute. Therefore in the absence of Thiru Gopinathan Chettiar no effective adjudication can be made. That apart, on the materials place before this Tribunal, it is difficult to accept the claim of the workman Thiru V. Gangadharan that he is entitled to invoke the provisions of Section 25(H) of the Industrial Disputes Act, 1947. Therefore, in the state of circumstances of the evidence now available, it cannot be held that there has been any valuation of Section 25(H) of the Industrial Disputes Act, Act, 1947 to the detriment of the workman concerned in this dispute, namely, Thiru V Gangadharan.

(5) Finally, on behalf of the Management it is pointed out that the concerned workman Thiru V. Gangadharan was never employed in any 'industry' as contemplated under Section 2(j) of the Industrial Disputes Act, 1947. I have already pointed out that this Centre, namely, Government of India Extension Centre, Attingal is a factory registered under the Factories Act and is owned by the Central Government. This Centre functions under the administrative control of the Director of Production Centres at Ettumanur, who is the disciplinary as well as the appointing authority. This Centre is being supervised by an Assistant Director. Merely because Aluminium/Steel utensils, hospital wares etc., are produced for commercial purposes, it cannot be said that it would be an "industry" as contemplated under Section 2(j) of the Industrial Disputes Act, 1947. On the other hand, the Director of Production Centre at Ettumanur who is arrayed as a Management in this dispute functioning under the Central Government is a permanent department of the Central Government, i.e., Central Government Small Scale Industries Development Organisation under the Ministry of Industry. Therefore, it cannot be seriously disputed that the employees under the Production Centres of Government of India would be covered by Central Civil Service Rules and Recruitment Rules framed under Article 309 of the Constitution. In the latest decision of the Supreme Court in Bangalore Water Board's case reported in 1978—I—L.L.J. Page 349 the functions of the sovereign State would be excluded from the operation of the Industrial Disputes Act, 1947. More so, the employees of the Management would be Central Government employees and as such they would be entitled to the constitutional remedy of Article 311 of the Constitution. Looked at from that point of view, the reference under the Industrial Disputes Act, 1947 must be held to be incompetent.

(6) In view of my findings in paragraph supra, I hold that the present reference is not maintainable under the Industrial Disputes Act, 1947. However regard being had to the fact that the workman concerned in this dispute, namely Thiru V. Gangadharan had been employed under the Management from 1-4-1964 upto 10-11-1968 and also intermittently from February, 1974 to July, 1974 and also regard being had to the age of the workman and the souls dependant on him and his broken financial circumstances, the Management may favourably consider of giving him some casual employment atleast as and when possible to the concerned worker Thiru V. Gangadharan if that would be permissible. In the peculiar circumstances I direct the parties to bear their respective costs.

Dated, this 28th day of July, 1982.

WITNESSES EXAMINED

For both sides : None.

DOCUMENTS MARKED

For Workman : None

Ex. W-1/16-12-68—Employment Certificate of the workman.

Ex. W-2/10-12-68—Memo issued to the workman by the Management requesting to receive retrenchment benefits.

Ex. W-3/28-6-75—Award of the Industrial Tribunal, Alleppey in I.D. No. 1/74 (Central) (extract of paras 19 and 20)

Ex W-4/13-2-80—Copy of representation of the workman to the Assistant Director, Government of India, Extension Centre, Attingal for appointment, (Exs. W-1 to W-4—Annexure to claim statement).

For Management :

Ex M-1—Statement showing the names of workers, date of appointment, present wages etc. in Production Centre, Ettumanur, Tiruvalla and Extension Centres at Attingal and Muvattupuzha. (Annexure to counter statement).

T. SUNDARSANAM DANIEL, Presiding Officer
[No. L-42012(15)/81-D II(B)]

S.O. 3012.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 2, Bombay, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Telephone, Nagpur and their workmen, which received by the Central Government on the 3-8-82

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL No. 2, BOMBAY

Reference No. CGIT-2/26 of 1981

PARTIES :

Employers in relation to the management of Telephones', Nagpur.

AND

Their Workmen

APPEARANCES :

For the Employers—Shri V. G. Bhangde, Advocate.

For the Workmen—Shri N. H. Kumbhare, President, Nagpur Telephone Casual Worker Union.

INDUSTRY : Telephones STATE : Maharashtra

Bombay, the 16th July, 1982

AWARD

By their order No. L-40012(3)/81-D II(B) dated 24-10-1981 the Central Government has referred the following dispute for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 :—

"Whether the action of Divisional Engineer (Telephones) (W&A) Nagpur, in terminating the services of Shri Ramesh Vishwanath Bodhkar, Ex-Chowkidar with effect from 1-12-1980 is justified ? If not, to what relief is he entitled ?"

2. The case of the Union on behalf of the workman Shri Ramesh Vishwanath Bodhkar is that he was serving as a Watchman in the establishment of Nagpur Telephones and worked with them for more then two years. It is alleged that on 1-12-1980, despite having put in more than two years continuous service, the workman concerned was not allowed to join the duties and this act on the part of the Respondent is alleged to be illegal amounting to removal from service and therefore the relief of reinstatement is being sought.

3. By written statement the Respondent admits that Shri Bodhkar was in their service but they say that he was a casual worker on daily wages in the Nagpur Telephone District and that he was not employed continuously and his employment was as and when required depending upon the work. It is alleged that in the initial stage he worked as a casual worker from January, 1975 to September, 1976 and again during the period July, 1978 to November, 1980. It is further alleged that in the month of November 1980 the work of recovery of old cables was in progress from Medical College Hospital to Baidyanath Chowk when the workman concerned was posted on duty as a Watchman to keep a watch on the cable drum and watch the line rendered open on account of work of recovery of the old cable undertaken and a tent was put up for the purpose of stay of watchman where another watchman Gangaram Duba was on duty as a watchman. The cables which were disinterred may be of 100 pairs & 1/2 pounds.

4. On 27-11-1980 it is alleged that a theft of these cables while Shri Bodhkar was on duty took place. It is alleged that it was only when Shri Shyamrao Bisan Ukey arrived on duty in the morning on 27-11-1980 that the story regarding the theft was narrated to him by the Watchman. According to the Respondent although the theft was alleged to have occurred about 1.30 A.M., neither the theft was reported to the Police Station by the Watchman nor the Superior officers were apprised thereof and it was only on the arrival of the Junior Engineer and other and that ultimately complaint to the Police was lodged. In this manner it is alleged that the watchman is guilty of dereliction in duty and since by his negligence loss of valuable property occasioned the responsibility was on the watchman himself. They therefore allege that when all these facts were admitted by the watchmen when his statement was recorded and when he was found guilty of negligence etc., the Respondent had to terminate the services which amounts to punishment after enquiry and therefore cannot be challenged. It is further contended that the activities of the telephones being of regal nature the Industrial Tribunal has no jurisdiction to entertain the reference or to grant any relief.

5. Admittedly there was no domestic enquiry as such and when therefore it is an admitted fact that the watchman was for more than two years in the service namely from July, 1978 to November, 1980 as well as admitted by the Respondent, when the workman was to be dismissed by way of punishment, either the Respondent was duty bound to hold a domestic enquiry or if there was no such enquiry atleast to lay before the Tribunal sufficient material substantiating the charge of alleged misconduct. Now what is contended by the management is that the workman who was a watchman on the relevant date during the night of 26-11-1980 and 27-11-1980 failed to report the incident of theft either to the superior officers or to the Police. In this connection the statement of Shri Bodhkar is that he was assaulted by the decoits armed with knives and was threatened and that 3 or 4 of them caught hold of him while the remaining decoits decamped with the cables. It is further alleged that he was stunned and for a while he could not understand as to what should be done and that when he recovered from the shock he narrated the incident to the co-workers whose tent was beyond the road and when Shyamrao Ukey arrived also reported the matter to him and lastly to the police when he was produced before the Police by the Superior officers. What has happened during the night was not only narrated by the workman before the superior officer but also appears in the statments of workmen recorded by Shri Parate and thereof are on record the statements of Gangaram Dube, Shyamrao Bisan Ukey and Jaising Nago Dhurve.

6. On going through the material which is placed before me to establish the charge of negligence, even if the contention of the Respondent is accepted and even if it is held that by not taking action immediately either by reporting the matter to the Superior officers or to the Police, the watchman failed in his duties, still it would be an act of negligence, of work once but would never be an habitual negligence. I was told that the Telephones are governed by the Industrial Employment (Standing Orders) Act and the model standing orders under Schedule I, and if the parties are governed by those standing orders, under standing order No. 14 (3)(i) the punishment of dismissal is only if the misconduct is of habitual negligence or neglect work. The standing orders therefore require that before any workman is dismissed for the misconduct, something more than a single act of negligence is necessary otherwise the extreme punishment of dismissal could not be justified. In my view therefore even accepting the contention of the Respondent in full, having regard to the narration of the workman concerned, the only fault which can be attributed to him is non-reporting

the matter to the higher authorities or to the Police It was tried to suggest that the watchman must be hand-in-glove with the culprits but there is absolutely no evidence in this regard nor at any time the case was made out that he himself either aided or abetted the commission of the theft Once we arrived at this conclusion and we notice that the workman concerned was in continuous service for more than two years service prior to the date of alleged termination and once we find that there is no misconduct established which would justify the dismissal by way of punishment the termination has to be set aside However since the workman was a casual workman and since as a watchman there was some negligence on his part I do not think that this is a case where reinstatement can be ordered but the workman deserves the relief of compensation only While determining the quantum of compensation we have to take into account the fact that had there been no termination the workman would have continued in service and for bringing the law of severence of the relationship of the employer employee the provisions of Section 25F of the Industrial Disputes Act would have required to be followed which the Respondent failed to do hence the order

ORDER

The termination of services of Shri Ramesh Vishwanath Bodhkar, Ex Chowkidar with effect from 1 12-1980 is held to be not justified, but however instead of reinstatement he shall be paid a compensation of Rs 4000 (Rupees four thousand only)

No order as to costs

M A DESHPANDE, Presiding Officer

Central Govt Industrial Tribunal No 2 Bombay

[No L 40012(3) 81 D II(B)]

S S PRASHER Desk Officer

New Delhi the 11th August 1982

S.O. 3013—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act 1947 (14 of 1947) the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal Calcutta in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Bejdih Colliery of Messrs Eastern Coalfields Limited Post Office Sitarampur and their workmen which was received by the Central Government on the 5 8 1982

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL

AT CALCUTTA

Reference No 52 of 1980

PARTIES

Employers in relation to the management of Bejdih Colliery under Eastern Coalfields Limited

AND

Their Workmen.

PRESENT

Mr Justice M P Singh Presiding Officer

APPEARANCES

On behalf of Employers—Mr B N Lala, Advocate

On behalf Workmen—Mr Mohit Mondal the concerned workman

STATE West Bengal INDUSTRY Coal Mine

AWARD

By Order No L-19012(64)/79-D IV(B) dated 7th July, 1980 the Government of India Ministry of Labour sent an industrial dispute existing between the employers in relation to the management of Bejdih Colliery under Eastern Coalfields Limited Post Office Sitarampur District Burdwan and their workmen to this Tribunal for adjudication The Schedule to the Order of Reference reads as

'Whether the action of the management of Bejdih Colliery under Eastern Coalfields Limited Post Office Sitarampur District Burdwan in refusing Shri Mohit Mondal General Mazdoor employment with effect from 16th January 1978 is justified ? If not, to what relief is the concerned workman entitled ?'

2 When the case was taken up for hearing both the parties appeared and submitted that the matter has been settled between them and filed a memorandum of settlement and prayed for an award in terms of the settlement I have gone through the settlement and I find the same to be legal, bonafide and in the interest of both the parties

3 In view of above I accept the settlement and pass an award in terms of the settlement The memorandum of settlement will form part of this award which is marked Annexure A"

Dated Calcutta

The 29th July, 1982

M P SINGH Presiding Officer

ANNEXURE 'A'

BEFORE THE HON'BLE PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT INDUSTRIAL TRIBUNAL, CALCUTTA

Reference No 52 of 1980

PARTIES

Employers in relation to the Management of Bejdih Colliery under Eastern Coalfields Limited P O Sitarampur Dist. Burdwan

AND

Their workman represented by West Bengal Khan Mazdoor Sangh (UTUC) Chinakuri P O Sundarchak, Dist Burdwan

Both the parties above named file joint petition of compromise as per terms mentioned hereunder

That the Government of India Ministry of Labour Order No L 9012(64)/79 D IV(B) dated 7th July 80 referred the alleged dispute for adjudication by the Hon'ble Tribunal

That the above matter is pending before the Hon'ble Tribunal and the matter has not been heard as yet

That the West Bengal Khan Mazdoor Sangh (UTUC) the concerned union of the workman Sri Mohit Mondal has approached to the management for settlement of the alleged dispute That the matter has been discussed between the management and the concerned union and the management without prejudice to its averments made before the Hon'ble Tribunal has agreed to settle the alleged dispute on the following terms and conditions

(i) Sri Mohit Mondal will be taken into service as under ground general mazdoor Category I within 7 days from the date of filing the settlement and the Hon'ble Tribunal will be requested to pass the award on the basis of the terms of settlement He shall be posted at any colliery under ECL depending on vacancy but for the present he shall be posted at Bejdih Colliery

(ii) The offer shall remain open upto 15 days from the date of filing the settlement after which the management shall not be responsible for giving employment

(iii) Responsibility for producing proof for identity shall be with the union

(iv) For the period from the date of unauthorised absence to the date of joining Sri Mondal shall not get any payment on no work no pay basis and the said period shall be treated as continuous service for the purpose of gratuity only and nothing else

(v) The pay of Sri Mondal shall be fixed in Cat I with basic rate of Rs 15 00 (Rupees Fifteen) per day as per NCWA II

at the initial stage of the scale and his next increment will fall due in September 1983.

(vi) The rules and regulations as applicable to other employees of the company in the same category in which the concerned workman will be placed shall also be applicable to Sri Mohit Mondal. He shall also abide by the rules and regulations and terms of employment as applicable to the other employees of the company and shall always obey and act according to the direction of the management.

(vii) Sri Mohit Mondal will have no claim whatsoever on account of back wages otherwise from the management and this settlement resolves all dispute and claim of the concerned wokman including those of the reference dated 7th July '80 namely the instant reference 52 of 1980.

(viii) Neither party will be entitled to any cost and the parties will bear their respective cost of the proceedings.

That both the parties submit that the Hon'ble Tribunal may be pleased to accept the aforementioned terms and conditions as agreed by both the parties for maintaining harmonious relation between the parties and industrial peace at the establishment.

That both the parties jointly pray that the Hon'ble Tribunal may be pleased to accord approval to the proposed settlement which is considered by both the parties as quite fair and reasonable and pass the award accordingly treating this settlement as part thereof.

And for this your petitioners shall ever pray,
Dated this the 20th day of July 1982.
Madhu Banerjee
For and on behalf of
the workman
General Secretary
West Bengal Khan
Mazdoor Sangh
(U.T.U.C.)

Prem Chand Ray,
For and on behalf of the
Employers.
Dy. Personnel Manager,
Sitarampur Area.
Eastern Coalfields Limited

Sri Mohit Mandal.
Signature of the Workman.

[No. L-19012(64)/79-DIV(B)]
S. S. MEHTA, Desk Officer.

New Delhi, the 11th August, 1982

S.O. 3014.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Khas Karanpur Colliery of Central Coalfields Limited, District Hazaribagh and their workmen, which was received by the Central Government on the 5th August, 1982.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) DHANBAD

Reference No. 46 of 1979

In the matter of an industrial dispute under S. 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947.

PARTIES :

Employers in relation to the management of Khas Karanpura Colliery of Central Coalfields Limited, Hazaribagh and their workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the employers—Shri T. P. Choudhury, Advocate.

On behalf of the workmen—Shri S. Bose, Advocate.

STATE : Bihar INDUSTRY : Coal.

Dhanbad, 30th July, 1982

AWARD

This is a reference under S.10 of the I.D. Act, 1947. The Central Government by its order No. L-20012/218/78-D.III(A) dated 2nd July, 1979 has referred this dispute to this tribunal for adjudication on the following terms :

SCHEDULE

"Whether the demand of the workmen of Khas Karanpura Colliery of Central Coalfields Limited District Hazaribagh for treating the Overburden removal workers mentioned in annexure 'A' as their workmen is justified ? If so, to what relief are the said workmen entitled ?

ANNEXURE 'A'

Sl. No. Name.

1. Shri Deo Chand
2. Shri Lal Muni
3. Shri Nagwa
4. Shri Gopal
5. Shri Tersha
6. Shri Jit Mohan
7. Shri Johan
8. Shri Mangra
9. Shri Ram Deo
10. Shri Baldeo
11. Shri Hiraman
12. Shri Sushila
13. Shri Sanichar
14. Shri Salman
15. Shri Albana
16. Shri Rajnath
17. Shri Somara
18. Shri Sukarmuni
19. Shri Jageshwar
20. Shri Jagdish
21. Shri Basmati
22. Shri Jagani
23. Shri Kishani
24. Shri Hiram
25. Shri Bandhu
26. Shri Sukari
27. Shri Dasrath
28. Shri Purani
29. Shri Bigal
30. Shri Birshi No. 1
31. Shri Budhni
32. Shri Waris
33. Shri Sukar
34. Shri Birashi
35. Shri Rani
36. Shri Sudhan
37. Shri Ram Charan

38. Shri Mangra
39. Shri Budhani
40. Shri Etwaria
41. Shri Silina
42. Shri Malani
43. Shri Elisha
44. Shri Sukarmani
45. Shri Hira
46. Shri Sherophina

2. The Koyala Chetra Janta Mazdoor Sangh represent 19 out of 46 workmen mentioned in the annexure to the schedule, while the remaining 27 workmen are represented by United Coal Workers Union. It so happened that after the filing of the written statements by these unions they gave up contest. These 46 workmen thereafter prayed for being represented by Shri Sankar Bose, Advocate and Secretary, Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh. On behalf of the management there was no objection and Shri Sankar Bose was permitted to represent their case. Written statement was filed by Shri Sankar Bose adopting the written statement filed earlier. The management had already filed their rejoinder to the written statement filed by the unions, and so no further written statement was filed by them. In the course of argument Shri T. P. Choudhury has conceded that the management had no ground to contest on the ground that these workmen are not represented by their unions who had raised the dispute, So his point is settled at rest.

3. The simple case of the workmen is that they are over-burden removal workers (O.B.R.) even from the time of the private owners and continues as such. But the management of Khas Karanpura colliery of Central Coalfields Limited do not regard them as their workmen. Their prayer is that these 46 concerned O.B.R. workers should be treated as workmen of the colliery. The management, on the other hand, has taken the plea that the concerned workmen were never O.B.R. workers of the colliery. According to the management a list of workers of all categories had been prepared immediately after the take over and in consultation with the trade union leaders the names of workers were finalised. In respect of the workers from this colliery the number of workers on their roll was 1343 and out of them after screening 1291 workers were taken in leaving out only 52. These concerned workmen were not screened in and never preferred any appeal before the Dy. Custodian General. Furthermore, their names did not appear in Form B register and they were never members of Coal Mines Provident Fund. Apart from that no vouchers were available mentioning their names. The specific case of the management is that the aforesaid 1291 workers were taken in after screening were backed-up by these two unions who raised this dispute. On this basis the management's case is that the prayer for recognition of these concerned workmen as the workmen of the colliery should be rejected and the reference should be answered accordingly

4. The management has filed documents in support of their contention

Ext. M1 is a list of piece rated workmen of O.B.R. of Khas Karanpura colliery. Ext. M2 and Ext. M3 are bonus registers. Ext. M4 to Ext. M4/3 are applications for gratuity by the workmen. Ext. M5 is an act of appeal before the R.L.C(C) Dhanbad under Payment of Gratuity Act, 1972 filed by the management. Ext. M6 is also an act of appeal filed by the management under Payment of Gratuity Act, 1972. Ext. M7 is also an appeal by the management filed before the RLC(C) Dhanbad Ext. M8 and Ext. M9 are also appeals filed by the management before the RLC(C) Dhanbad.

5. Three witnesses were examined on behalf of the management. MW-1 is Shri S. K Tayal, who was manager of Khas Karanpura colliery from November, 1972 to April, 1973. He has said that the colliery was taken over by the Central Government on 31-7-73. He was thereafter asked to prepare a list of workmen employed in the colliery. With regard to the list Ext. M1 he has said that he has prepared the list on 19-2-73 He has denied that besides the workmen mentioned in the list, there were 139 O.B.R workers. He has further said that there was two unions viz. United Coal Workers Union and Rastriya Colliery Mazdoor Sangh union who were operating in the colliery and these two unions were associated with the screening. The total number of workers employed in the colliery was 1291. According to him another list was prepared for other types of workmen. He has denied the suggestion of the workmen that O.B.R. work was done through contractors. He has admitted that the workers of this colliery were residents of the locality. He has denied that O.B.R. workers used to work under a gang leader who used to submit bills in respect of the work done by each gang. He has also denied that the payment was made to gang leader only. He has admitted that it was not possible that each O.B.R. worker could be paid Rs. 500 per week or 38,500 annually.

6. The next witness is MW-2, Shri P. M. Lal, Senior Personnel Officer. His evidence is similar to MW1. He has further deposed that Sl. No. 1, 7, 13, 17, 29 and 16 were students reading in the school during his time In cross-examination he has said that there were 900 employees in Khas Karanpura colliery rather he joined in June, 1965. With regard to the number of workers who were reading in school, he has said that he saw them reading between 1965 and 1973 and not thereafter. He knew them only because they were living in Khas Karanpura area and were sons and daughters of the colliery workers. With regard to Ext. M2 he has said that he was only an officer who had signed on that document. With regard to Ext. M3 he has said that it was not signed by any clerk officer of the colliery. He has further said that he had left the colliery in 1973 and he has no idea if the concerned workmen worked after his departure from the colliery. He also did not know if they were stopped from work.

7. MW-3 Shri R. P. Pathak started working as manager of Khas Karanpura colliery in 1975. He has come to say about 4 original applications about gratuity. They were in respect of Jitu, Raghiya, Bhujo widow of Sayana and Sukra. The colliery manager, Mr. Panja or Pan had signed these applications, Exts. M4 to M4/3 are those applications. The gratuity claimed through these applications are at varying rates of Rs. 49 to 63 per day. His evidence is that according to NCWA-I the maximum earning of a OBR worker per day could not go beyond Rs. 16 per day. Since the claim was an exaggerated rate an enquiry was held by Mr. Gulhati, Assistant C.P.O. The papers in connection with the wages to O.B.R. workers had been seized and sent to the head-quarters He has no idea as to what happened to that enquiry. In his cross-examination he has said that these 4 applications Exts. M4 to M4/3 are on N.C.D.C. form. It appears the signature of the manager in the exhibits and therefore the amount of basic wage mentioned in the application has been admitted by these unions to be correct The union has said that the management fought that gratuity case.

8. On the part of the concerned workmen the original file of the Assistant Labour Commissioner(C) Hazaribagh in which the dispute was considered leading to this reference was called for and it has been extensively used by Shri Bose. The record has not been disputed by the management No other document had been placed on behalf of the workmen except the A.L.C(C) record in this dispute. But two witnesses have been examined. WW-1 Badal Chandra Biswas was working in Khas Karanpura colliery as surveyor between 1975 and 1978. He has said that while he was at Khas Karanpura colliery, quarry was functioning, and removal of overburden was made manual labour. He used to go to the quarry for measurement work. He further said that surface subsistence in depillering area occured during his time and to fill up that area manual labour was employed. He was not able to give an idea about the labour force employed for the purpose of removal of over burden. WW-2 is Bigal a workman in Sl. No. 29. He has said that there were 10 OBR worker in one gang and there were 15 to 16 such gang. The surveyor used to measure the work done by them. With regard to the concerned workmen he has said that they were working since before the nationalisation and in the year 1978 they were stopped from work. His evidence is that they have been left idle on account of their stoppage of work. WW.3 is Mangra who worked in Khas Karanpura colliery for 10 years before he retired 2 years ago. He was OBR worker in the colliery. According to him the over-burden removal worked in gang consisting of 10 persons in each gang He has identified bigal (WW-1) as one of the overburden removal worker. He has said that the surveyor used to measure the work done and bills used to be prepared in the name of the gang sirdar who was paid by the colliery

office. The gang sirdar used to give his signature or LTI on a piece of paper after receiving the amount of the bill. In cross examination he has said that he and others filed gratuity case at Hazaribagh. He has further said that he and others were demanding gratuity at the rate of Rs. 1500 but the wages were fixed at Rs. 1000.

9 From the evidence produced by the management it will appear that none of the witnesses have admitted the existence of these workmen as OBR workers working in Khas Karanpura colliery. They have not even admitted that they were working under gang leaders and the gang leaders were paid on the basis of the bills presented by them for the work done by the group of which they were leaders. But it is an admitted position that six of the gang leaders had filed gratuity applications and the management has filed the original applications of 4 of them and also the position of the gratuity cases. While at the conciliation stage the management did not admit these 46 concerned workmen as OBR workers, the position taken by the management in the gratuity case was that the persons claiming gratuity were in fact group leaders and payment was made to them for the entire group and not for individual earning of each of them. So, the position is that the contention made by these workmen that they were OBR workers of the colliery and the payment was made to them through the group leaders was virtually admitted by the management. The ALC(C) Hazaribagh has made full mention of this fact in a letter dated 23-1-1980 signed by Shri S. B. Singh, Assistant Labour Commissioner (Central) Hazaribagh addressed to the Manager, Khas Karanpura Colliery of Central Coalfields Limited. This fact further was highlighted at the conciliation stage in respect of these 46 workmen under reference.

10. In a case like this there is bound to be paucity of evidence on behalf of the workmen from the time of the private owners. The private owners engaged miners and OBR workers through a system called sardari system. The miners and OBR workers used to work under gang leaders and payments were used to be made for the work done by them through the group leaders. The object of nationalisation was to abolish this system because it was a mal-practice depriving the actual workers from their due wages as envisaged in the wage board recommendation. These facts can be taken judicial notice of, particularly because the Government of India nationalised these collieries with the very important purpose of providing just wages to the workers of the coal industry. After nationalisation an attempt was made by the Government to eliminate the intermediaries and to put on the rolls of the colliery the workers engaged in the production of coal including the OBR workers. But even then the vested interests at work did not permit genuine workers to be put on the roll of the colliery and allowed induction of their men as workers of the colliery. It will appear that out of the list of OBR workers, 50 were not screened in for the reason best known to the unions working at that time and also the officers of the colliery as soon as the nationalisation took place. But ever since then some of the unions agitated about these OBR workers and also some others about whom even the Assistant Labour Commissioner(C) expressed some doubts about their genuineness. But so far as these 46 concerned workmen, they appeared to be consistent with the list and about whom the conciliation officer (Central) was also satisfied. Their case is backed up by the inflated claim made by some of the group leaders and also by the fact that the management admitted that OBR workers worked under groups

11. Thus having considered various aspects of the case I have to hold that the demand of the workmen of Khas Karanpura colliery of Central Coalfields Limited, District Hazaribagh for treating the 46 Overburden Removal Workers mentioned in the Annexure 'A' as their workmen is justified. Consequently, they should be put in the list of Overburden Removal Workers. In the written statement claim for back wages have been made. But this is not supported by the facts and they themselves have said that they did not work during the period. Consequently, the Overburden Removal Workers named in the Annexure 'A' to the schedule of the reference must appear before the management for their enrolment as Overburden Removal Workers within a month of the publication of this award, failing which they should be treated as not interested in regularisation of their jobs.

This is my award.

J. P. SINGH, Presiding Officer.

[No. L-20012/218/78-DIII(A)]

A. V. S. SARMA, Desk Officer

आदेश

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 1982

का०आ० 3015.—मैसर्स भारत कोकिंग कोल लि०, डाकघर कुसुन्दा, जिला धनबाद की कुसुन्दा क्षेत्र संख्या 6 के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, जिनका प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ (इन्टक) करती है, एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और उक्त नियोजकों और कर्मकारों ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10क की उपधारा (1) के अनुसरण, में एक लिखित करार द्वारा उक्त विवाद को माध्यस्थम के लिए निर्देशित करने का करार कर लिया है और उक्त माध्यस्थम करार की एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजी गई है ;

अतः अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10क की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार उक्त माध्यस्थम करार को, जो उसे 31 जुलाई, 1982 को मिला था, एतद्द्वारा प्रकाशित करती है ।

(करार)

(औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10क के अधीन)

पक्षकारों के नाम :

नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले

श्री एम०एन० सिन्हा, कार्मिक प्रबंधक, मैसर्स भारत कोकिंग कोल लि०, कुसुन्दा क्षेत्र संख्या 6, डाकघर कुसुन्दा, जिला धनबाद ।

कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले

1. श्री जी० डी० पाण्डे, सैक्रेटरी, राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ राजेन्द्र पथ, धनबाद ।

पक्षकारों के बीच निम्नलिखित औद्योगिक विवाद को श्री श्याम कृष्ण क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), धनबाद के माध्यस्थम के लिए निर्देशित करने का करार किया गया है ।

1. **विनिर्दिष्ट विवाद्यक विषय :**

"क्या यूनियन की यह मांग कि श्री राम कुमार सिंह, श्री राजेन्द्र प्रसाद वर्मा, श्री जी० एन० शर्मा और श्री मालन सिंह को पूर्वापेक्षी प्रभाव से लिपिकीय ग्रेड-2 से लिपिकीय ग्रेड-1 में पदोन्नत किया जाना चाहिए, न्यायसंगत है ? यदि हां तो कर्मकार किस अनुतोष के हकदार हैं ।

2. विवाद के पक्षकारों का विवरण जिसमें अंतर्वलित स्थापन या उपक्रम का नाम तथा पता भी सम्मिलित है ।	मैसर्स भारत कोकिंग कोल लि० डाकघर कुसुन्दा (धनबाद) की कुसुन्दा क्षेत्र संख्या 6 के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजक ।
3 कर्मकार का नाम, यदि वह विवाद में स्वयं शामिल है या यूनियन का नाम यदि कोई हो तो प्रश्नगत कर्मकार का प्रतिनिधित्व करती है।	राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ (इंटक) राजेन्द्र पथ, धनबाद।

4 प्रभावित उपक्रम में नियोजित कर्मकारों की कुल संख्या	1500
5 विवाद द्वारा प्रभावित या संभाव्यतः प्रभावित होने वाले कर्मकारों की प्राक्कलित संख्या	4 (चार)

मध्यस्थ अपना पंचाट राजपत्र में मध्यस्थ करार के प्रकाशन की तारीख से छः मास की अवधि के भीतर या इतने समय के भीतर जो हमारे बीच पारस्परिक लिखित करार द्वारा बढ़ाया जाए, देगा। यदि उपर्युक्त कालावधि के भीतर पंचाट नहीं किया जाता तो मध्यस्थम के लिए निदेश स्थगित हो जाएगा और हम नए मध्यस्थम के लिए बातचीत करने को स्वतंत्र होंगे।

पक्षकारों के हस्ताक्षर

ह०/-	ह०/-
(एस०एन० सिन्हा)	(जी० डी० पांडे)
कार्मिक प्रबंधक	मंत्री
मैसर्स बी० सी० सी० एल०	राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ
की कुसुण्डा क्षेत्र सं० 6,	राजेन्द्र पथ धनबाद।
डाकघर कुसुण्डा, जिला धनबाद।	24-7-1982
24-7-1982	

साक्ष्य

1 अपाठ्य

2 अपाठ्य

मैं औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 10क के अन्तर्गत उक्त विवाद में मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए अपनी सहमति देता हूं।

श्याम कृष्ण, क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय)
धनबाद।

[फा० संख्या एल०-20013(7)/82-डी० 3 (ए०)]

ORDER

New Delhi, the 16th August, 1982

S.O. 3015—Whereas an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Kusunda Area No. VI of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Kusunda, District Dhanbad and their workmen represented by Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh (INTUC);

And Whereas, the said employers and their workmen have by a written agreement under sub-section (1) of section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), agreed to refer the said dispute to arbitration and have forwarded to the Central Government a copy of the said arbitration agreement;

Now Therefore, in pursuance of sub-section (3) of section 10A of the said Act, the Central Government hereby publishes the said agreement which was received by it on the 31st July, 1982.

AGREEMENT

(Under section 10A of the Industrial Dispute Act, 1947)

BETWEEN

Name of Parties:

Representing Employer:	Shri S.N. Sinha, Personnel Manager, Kusunda Areea No. VI of M/s. Bharat Coking Coal Limited, P.O. Kusunda, Distt. Dhanbad.
Representing workmen	Shri G.D. pandey, Secretary, Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh, Rajendra Path, Dhanbad.

It is hereby agreed between the parties to refer the following dispute to the arbitration of Shri Shyam Krishna, Regional Labour Commissioner (Central), Dhanbad.

(i) Specific matters in dispute:

"Whether the demand of union that Shri Ram Kumar Singh Shri Rajendra Prasad Verma, Shri D N. Sharma and Sri Lalan Singh should be promoted from Clerical Grade-II to Clerical Grade-I with retrospective effect is justified? If so, to what relief the workmen are entitled?".

(ii) Details of the parties to the dispute including the name and address of the establishment of undertaking involve :	Employer in relation to the management of Kusunda Area No. VI of M/s. Bharat Coking Coal Ltd., P O Kusunda (Dhabid)
(iii) Name of the workman in case he himself is involved in the dispute or the name of the union, if any, representing the workman or workmen in question:	Rashtraya Colliery Mazdoor Sangh (INTUC), Rajendra path, Dhanbad.
(iv) Total number of workmen employed in the undertaking affected:	1500
(v) Estimated number of of workmen affected or likely to be affected by the dispute:	4 (four)

The Arbitrator shall make his award within a period of six months from the date of publication of the arbitration agreement in the official gazette or within such further time as is extended by mutual agreement between us in writing. In case the award is not made within the period aforementioned, the reference to arbitration shall stand automatically cancelled and we shall be free to negotiate for fresh arbitration

SIGNATURE OF THE PARTIES.

Sd/-	Sd/-
(S.N. Sinha)	(G.D. Pandey)
Personnel Manager,	Secretary,
Kusunda Area,	Rashtriya Colliery
No. VI of M/s BCCL,	Mazdoor Sangh,
P.O Kusunda,	Rajendra Path,
Distt. Dhanbad.	Dhanbad.
24-7-1982	24-7-1982

WITNESSES.

1. Sd/-

2. Sd/-

I hereby give my consent to act as Arbitrator under section 0A of the Industrial Disputes Act, 1947 in the above dispute.

Sd/-
SHYAM KRISHNA,
Regional Labour Commissioner (Central),
Dhanbad.
[No. L-20012(7)/82-D. III (A)]

आदेश

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 1982

का० आ० 3916—मैसर्स इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी लिमिटेड डाकघर भागा जिला धनबाद के नूनूडीह जीतपुर कोलियरी के प्रबंधतंत्र से

सम्बद्ध नियोजकों और उनके कमकारों के बीच जिनका प्रतिनिधित्व कोल माइन्स इंजीनियरिंग वर्कर्स एसोसिएशन, पोलीटेकनीक रोड, बेकर बंध धनबाद करती है एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है,

और उक्त नियोजको और कर्मकारों ने औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 10क की उपधारा (1) के अन्तर्गत एक लिखित करार द्वारा उक्त विवाद को माध्यस्थम के लिए निर्देशित करने का करार कर लिया है और उक्त माध्यस्थम करार की एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजी गई है,

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 10-क की उपधारा (3) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार उक्त माध्यस्थम करार को जो उसे 31 जुलाई 1982 को मिला था एतद्वारा प्रकाशित करती है ।

(करार)

(औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 10-क के अधीन)

पक्षकारों के नाम :

नियोजक का प्रतिनिधित्व करने वाले:	श्री एस० पी० मेहरा, एरिया प्रबंधक मैसर्स इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी लि० की नूनूडीह जीतपुर कोलियरी, डाकघर भागा, जिला धनबाद।
कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले :	श्री एम० एन० मलिक जनरल सैक्रेटरी कोल माइंस इंजीनियरिंग वर्कर्स एसोसिएशन, पोलीटेकनीक रोड, बेकर बंध, धनबाद।

पक्षकारों के बीच निम्नलिखित औद्योगिक विवाद को श्री श्याम कृष्णन, क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), धनबाद के माध्यस्थम के लिए निर्देशित करने का करार किया गया है।

1. विनिर्दिष्ट विवादग्रस्त विषय.

"क्या स्टोइंग विभाग, जीतपुर कोलियरी के श्री मुनिलाल और 26 अन्य कर्मकारों की उचित पदनाम और वर्ग मजदूरी की मांग उचित है ? यदि हां तो वे किस अनुतोष के हकदार है ?"

2 विवाद के पक्षकारो का विवरण, जिसमें प्रतिस्थापन या उपक्रम का नाम और पता भी सम्मिलित है।	मैसर्स इंडियन आयरन एंड स्टील कं० लि०, डाकघर भागा, जिला धनबाद की नूनूडीह जीतपुर कोलियरी के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजक।
3 कर्मकार का नाम यदि वह स्वयं विवाद में ग्रस्तग्रस्त है या यदि कोई संघ प्रश्नगत कर्मकार या कर्मकारो का प्रतिनिधित्व करता हो तो उसका नाम :	कोल माइन्स इंजीनियरिंग वर्कर्स एसोसिएशन, पोलीटेकनीक रोड, बेकर बंध, धनबाद।
4. प्रभावित उपक्रम मे नियोजित कर्मकारों की कुल संख्या	2700
5. विवाद द्वारा प्रभावित या सम्भाव्यतः प्रभावित होने वाले कर्मकरों की प्राक्कलित संख्या	27

मध्यस्थ अपना पंचाट इस माध्यस्थम करार के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से छ. मास की कालावधि या इतने और समय के भीतर जो हमारे बीच पारस्परिक लिखित करार द्वारा बढ़ाया जाए देगा। यदि पूर्व वर्णित कालावधि के भीतर पंचाट नही दिया जाता, तो माध्यस्थम के लिए निदेश स्वतः रद्द हो जाएगा और हम नए माध्यस्थम के लिए बातचीत करने को स्वतंत्र होंगे।

पक्षकारों के हस्ताक्षर

ह०/-(एस० पी० मेहरा)	ह०/-(एम० एन० मलिक)
एरिया प्रबंधक नूनूडीह	जनरल सैक्रेटरी
जीतपुर कोलियरी	कोल माइंस इंजीनियरिंग वर्कर्स
मैसर्स इसको लि०	ऐसोसिएशन, बेकर बंध,
डाकघर भागा (धनबाद)	धनबाद।
24-7-1982	24-7-1982

साक्षी

1 ह०/-अपठनीय

2. ह०/-अपठनीय

नूनूडीह जीतपुर कोलियरी, मैसर्स इंडियन आयरन एंड स्टील कं० लि०, डाकघर भाग (धनबाद) के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजक

और

कोल माइन्स इंजीनियरिंग वर्कर्स एसोसिएशन बेकर बंध, धनबाद—श्री मुनीलाल और 26 अन्य कर्मकार "स्टोइंग विभाग नूनूडीह जीतपुर कोलियरी मैसर्स इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी लि० के बारे में—

के बीच में औद्योगिक विवाद के मामले में

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10-क के अधीन में उपयुक्त विवाद में मध्यस्थ के रूप में काम करने की सहमति देता हूं ।

श्याम कृष्ण, क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय)
धनबाद ।

[संख्या एल०-20013/5/82-डी० 3 (ए)]

ORDER

New Delhi, the 16th August, 1982.

S.O. 3016.—Whereas an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Noonodih Jitpur Colliery of Messrs Indian Iron and Steel Company Limited, Post Office Bhaga, District Dhanbad and their workmen represented by Coal Mines Engineering workers 'Association, Polytechnic Road, Bekar Bandh, Dhanbad;

And Whereas, the said employers and their workmen have by a written agreement under sub-section (1) of section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) agreed to refer the said dispute to arbitration & have forwarded to the Central Government a copy of the said arbitration agreement;

Now therefore, in pursuance of sub-section (3) of section 10A of the said Act, the Central Government hereby publishes the said agreement which was received by it on 31st July, 1982.

AGREEMENT

(Under section 10A of the Industrial Dispute Act, 1947).

BETWEEN

Name of partics:	
Representing Employer:	Shri S.P. Mehra, Area Manager, Noonudih Jitpur Colliery of M/s. Indian Iron & Steel Co. Ltd., P.O. Bhaga, Distt. Dhabad
Representing workmen:	Shri M.N. Mallick, General Secretary, Coal Mines Engineering workers Association, Polytechnic Road Bekar Bandh, Dhanbad.

It is hereby agreed between the parties to refer the following dispute to the arbitration of Shri Shyam Krishna, Regional Labour Commissioner (Central), Dhanbad.

(i) Specific matters in dispute:

"Whether the demand of Shri Munilal & 26 others, workers of Stowing Department, Jitpur Colliery for proper designation and category wages is justified? If so, to what relief they are entitled?".

(ii) Details of the parties to the dispute including the name and address of the establishment of undertaking involved:	Employer in relation to the Management of Noonudih Jitpur Colliery of M/s. Indian Iron & Steel Co. Ltd., P O. Bhaga, Distt Dhanbad
(iii) Name of the workmen in case he himself is involved in the dispute or the name of the union, if any, representing the workman or workmen in question:	Coal Mines Engineering Workers' Association, Poly technic Road, Bekar Bandh Dhanbad.
(iv) Total number of workman employed in the undertaking affected:	2700
(v) Estimated number of workmen affected or likely to be affected by the dispute:	27

The Arbitrator shall make his award within a period of six months from the date of publication of the arbitration agreement in the official gazette or within such further time as is extended by mutual agreement between us in miting. In case the award is not made within the period aforementioned, the reference to arbitration shall stand automatically cancelled and we shall be free to negotiate for fresh arbitration.

SIGNATURE OF THE PARTIES.

Sd/-	Sd/-
(S.P. Mehra)	(M.N. Mallick)
Area Manager,	General Secretary,
Noonudih Jitpur Colliery,	Coal Mines Engineering
M/s. II SCO. L td.,	Workers Association,
P.O. Bhaga (Dhanbad.)	Bekar Bandhu,
	Dhanbad.
24-7-1982	24-7-1982

WITNESSES:

1. Sd/-

2. Sd/-

I hereby give my consent to act as Arbitrator under Section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 in the above dispute

No. L 20013 (5)/82—D III (A)

SHYAM KRISHNA,
Regional Labour Commissioner (Central),
Dhanbad.

आदेश

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 1982

का० आ० 3017.—मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, कोयला भवन का मुख्यालय, डाकघर, कोयला नगर, जिला धनबाद के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, जिनका प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ (इन्टक) करती है, एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और उक्त नियोजकों और कर्मकारों ने औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 10-क की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में एक लिखित करार द्वारा उक्त विवाद को माध्यस्थम् के लिए निर्देशित करने का करार कर लिया है और उक्त माध्यस्थम् करार की एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजी गई है ,

अब, अब उक्त अधिनियम की धारा 10-क की उपधारा (3) के उपबन्धों के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार उक्त माध्यस्थम् करार को, जो उसे 31 जुलाई, 1982 को मिला था, एतद्द्वारा प्रकाशित करती है ।

(करार)

(औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10-क के अधीन)

पक्षकारों के नाम ,

नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले	श्री टी० एन० श्रीवास्तव, उप मुख्य कार्मिक प्रबन्धक, मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, कोयला भवन, डाकघर कोयला नगर, जिला धनबाद ।
कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले	श्री जी० डी० पाठे, सैक्रेटरी, राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ (इन्टक), राजेन्द्रपथ, धनबाद ।

पक्षकारों के बीच निम्नलिखित औद्योगिक विवाद को श्री श्याम कृष्णन, क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), धनबाद के माध्यस्थम् के लिए निर्देशित करने का करार किया गया है ।

विनिर्दिष्ट विवाद ग्रस्त विषय :

1 क्या यूनियन की मांग कि श्री सुरेश प्रसाद सिंह को पूर्वापेक्षी प्रभाव से तकनीकी ग्रेड-बी में रखा जाना चाहिए, न्यायोचित है ? यदि हां, तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

(ii) विवाद के पक्षकारों का विवरण, जिस में अन्तर्वलित स्थापन का उपक्रम का नाम तथा पता भी सम्मिलित है ।	मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड कोयला भवन, डाकघर कोयला नगर, जिला धनबाद के मुख्यालय के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजक ।
(iii) कर्मकार का नाम, यदि वह विवाद में स्वयं शामिल है या यूनियन का नाम, यदि कोई हो, जो प्रश्नगत या कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करती है ।	राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ (इन्टक), राजेन्द्र पथ, धनबाद ।
(iv) प्रभाविम उपक्रम में नयोजित कर्मकारों की कुल संख्या ।	400
(v) विवाद द्वारा प्रभाविम या एक सभाव्यतः प्रभावित होने वाले कर्मकारों की प्राक्कलित संख्या ।	

मध्यस्थ अपना पंचाट सरकारी राजपत्र में मध्यस्थ करार के प्रकाशन की तारीख से छ मास की अवधि के भीतर या इतने समय के भीतर, जो हमारे बीच पारस्परिक लिखित करार द्वारा बढ़ाया जाए, देगा । यदि उपर्युक्त कालावधि के भीतर पंचाट नहीं दिया जाता, तो माध्यस्थम् के लिए बातचीत करने को स्वतंत्र होंगे ।

पक्षकारों के हस्ताक्षर

ह०
(टी० एन० श्रीवास्तव)
उपमुख्य कार्मिक प्रबन्धक,
मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड,
कोयला भवन, डाकघर कोयला नगर,
जिला धनबाद । 24-7-1982 ।

ह०
(जी० डी० पाडे)
सेक्रेटरी
राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ राजेन्द्र
पथ, धनबाद । 24-7-1982 ।

साक्ष्य

1. ह०/-
2. ह०/-

मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, मुख्यालय, कोयला नगर (धनबाद) के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजक

और

राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ (इन्टक), राजेन्द्र पथ, धनबाद श्री सुरेश प्रसाद सिंह के संबंध में, जो अब मैसर्स बी० सी० सी० एल० की ओर से राउरकेला स्टील प्लांट, क्वालिटी कन्ट्रोल विभाग में तकनीकी सहायक के रूप में कार्य कर रहे है ।

मैं औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10क के अनुसरण उक्त विवाद में माध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए अपनी सहमति देता हूं ।

(श्याम कृष्णन)
क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), धनबाद
[संख्या एल-20013/6/82-डी०III(ए)]

ORDER

New Delhi, the 18th August, 1982

S. O. 3017.—Whereas an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Headquarters of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Koyala Bhawan, Post Office Koyala Nagar, District Dhanbad and their workmen represented by Rashtriya Colliery Mazdoor Singh (INTUC)

And whereas, the said employers and their workmen have by a written agreement under sub-section (1) of section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), agreed to refer the saiddispute to arbitration and have forwarded to the Central Government a copy of the said arbitration agreement

Now therefore, in pursuance of sub-section (3) of section 10A of the said Act, the Central Government hereby publishes the said agreement which was received by it on the 31st July, 1982.

AGREEMENT

(Under Section 10A of the Industrial Dispute Act, 1947)

BETWEEN

Name of parties:

Representing Employers: Shri T.N. Srivastava, Dy. Chief Personnel Manager M/s. Bharat Coking Coal Ltd. Koyala Bhawan, P.O. Koyala Nagar Distt. Dhanbad.

Representing Workman: Shri G.D. Padney, Secretary Rashtriya Colliery, Mazdoor Singh (INTUC) Rajendra Path Dhanbad.

It is hereby agreed between the parties to refer the following dispute to the arbitration of Shri Shyam Krishna, Regional Labour Commissioner (Central), Dhanbad.

(i) Specific Masters in dispute; "Whether the demand of union that Sri Suresh Pd. Singh should be placed in Technical Grade-B with retrospective effect is justified ? If so, what relief the workman is entitled to ?"

(ii) Details of the parties to dispute including the name and address of the establishment of undertakings involved: Employers in relation to management of Headquarters of M/s. Bharat Coking Coal Ltd, Koyala Bhawan, P.O. Koyala Nagar, Dist, Dhanbad.

(iii) Name of the workman in case he himself is involved in the dispute or the name of the union, if any, representing the workman or workmen in question: Rashtriya Colliery Mazdoor Singh (INTUC) Rajendra Path, Dhanbad.

iv) Total number of workmen employed in the undertaking affected: 400

(v) Estimated number of workmen affected or likely to be affected by the dispute: ONE

The Arbitrator shall make his award within a period of six months from the date of publication of the arbitration agreement in the official gazette or within such further time as is extended by mutual agreement between us in writings. In case the award is not made within the period aforementioned the reference to arbitration shall stand automatically cancelled and we shall be free to negotiate for fresh arbitration.

SIGNATURE OF THE PARTIES

Sd/-
(T.N. Srivastava)
Dy. Chief Personnel Manager,
M/s. Bharat Coking Coal Ltd.
Koyala Bhawan, P.O. Koyala Nagar, Distt. Dhanbad.

24-7-1982

Sd/-
(G.D. Pandey
Secretary
Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh, Rajendra Path, Dhanbad

24-7-1982

Witnesses:

1. Sd/-
2. Sd/-

I hereby give my consent to act as Arbitrator under section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 in the above dispute.

Sd/-
Shyam Krishna
Regional Labour Commissioner (Central)
Dhanbad.

[No. L-20013 (6) /82-D III(A)]

आदेश

का॰आ॰ 3018.—मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, की बरारी कोलियरी, डाकघर भूलन बरारी, जिला धनबाद के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, जिनका प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ, राजेन्द्र पथ, डाकघर और जिला धनबाद करती है, एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ,

और उक्त नियोजकों और कर्मकारों ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10क की उपधारा (1) के अनुसरण में एक लिखित करार द्वारा उक्त विवाद को माध्यस्थम के लिए निर्देशित करने का करार कर लिया है और उक्त माध्यस्थम करार की एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजी गई है ,

अतः, अब, उक्त अधिनियम, की धारा 10क की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार उक्त माध्यस्थम करार को, जो उसे 3 अगस्त, 1982 को मिला था, एतद्द्वारा प्रकाशित करती है ।

(करार)

(औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10क के अधीन)

पक्षकारों के नाम

नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले :	श्री एस॰ के॰ राय चौधरी, एजेंट, मैसर्स बी॰ सी॰ सी॰ एल॰ की बरारी कोलियरी, डाकघर भूलन-बरारी जिला धनबाद ।
कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले :	श्री जी॰ डी॰ पांडे, सक्रेटरी, राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ, राजेन्द्र पथ, डाकघर व जिला धनबाद ।

पक्षकारों के बीच निम्नलिखित औद्योगिक विवाद को श्री के॰ मानमुथवेल, उप मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय), धनबाद के माध्यस्थम के लिए निर्देशित करने का करार किया गया है ।

1. विनिर्दिष्ट विवादग्रस्त विषय :

क्या यूनियन की श्री गंगादयाल सिंह, लिपिक को लिपिकीय ग्रेड-1 में रखने की मांग न्यायोचित है। यदि हां, तो वह किस अनुतोष का हकदार है ,

2. विवाद के पक्षकारों के विवरण (जिसमें अन्तर्वलित स्थापन या उपक्रम का नाम तथा पता भी सम्मिलित है)	1. मैसर्स बी॰ सी॰ सी॰ लिमिटेड की बरारी कोलियरी, डाकघर भूलनबरारी, जिला धनबाद के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजक । 2. राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ, राजेन्द्र पथ, धनबाद ।
3. कर्मकार का नाम, यदि वह विवाद में स्वयं शामिल है या यूनियन का नाम यदि कोई हो, जो प्रश्नगत कर्मकार या कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करती है ।	श्री गंगा दयाल सिंह, लिपिक, का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ, राजेन्द्र पथ धनबाद करती है ।
4. उपक्रम में नियोजित श्रमिकों की कुल संख्या	2209
5. विवाद द्वारा प्रभावित या संभाव्यत प्रभावित होने वाले कर्मकारों की प्राक्कलित संख्या ।	(केवल एक)

मध्यस्थ अपना पंचाट राजपत्र में माध्यस्थता करार के प्रकाशन की तारीख से छः मास की अवधि के भीतर देगा या इतने समय के भीतर, जो हमारे बीच पारस्परिक लिखित करार द्वारा बढ़ाया जाए, देगा । यदि उपर्युक्त कालावधि के भीतर पंचाट नहीं दिया जाता तो माध्यस्थम के लिए निदेश स्वतः रद्द हो जाएगा और हम नए माध्यस्थम के लिए बातचीत करने को स्वतंत्र होंगे ।

पक्षकारों के हस्ताक्षर

(एन॰ के॰ पी॰ सिन्हा), पी॰ एम (जी॰ डी॰ पांडे)
मोदरा क्षेत्र एजेंट मैसर्स बी॰ सी॰ सी॰ एल॰
की बरारी कोलियरी, डाकघर मोदरा जिला धनबाद।

सैक्रेटरी,
राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ,
राजेन्द्र पथ, डाकघर और जिला धनबाद

साक्ष्य:

(1) अपाठ्य दिनांक 31-7-1982 जिला धनबाद
(2) अपाठ्य

मैसर्स भारत कोकिंग कोल लि॰, की बरारी कोलियरी डाकघर भूलन-बरारी जिला धनबाद

और

राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ, राजेन्द्र पथ, धनबाद के बीच औद्योगिक विवाद के मामले

विशेष मामला

क्या यूनियन की यह मांग कि श्री गंगादयाल सिंह, लिपिक को लिपिकीय ग्रेड-1 में रखने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि हां, तो वह किस अनुतोष का हकदार है।

मैं औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 क के अन्तर्गत उक्त विवाद में मध्यस्थ के रुप में कार्य करने की सहमति देता हूं।

ह॰ के॰ मानमुथवेल
मध्यस्थ के हस्ताक्षर

ह॰/—

[संख्या एल॰-20013-III (ए॰)/82-डी]

ORDER

S.O. 3018.—Whereas an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Bararee Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Bhulanbararee, District Dhanbad and their workmen represented by Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh, Rajendra Path, Post Offic and Distrlot Dhanbad;

And Whears, the said employers and their workmen have by a written agreement under sub-section (1) of section 10A of the Industrial Dsiputes Act, 1947 (14 of 1947), agreed to refer the said dispute to arbitration and have forwarded to the Central Government a copy of the said arbitration agreement;

Now Therefore, in pursuance of sub-section (3) of section 10A of the said Act, the Central Government hereby publishes the said agreement which was received by it on the 3rd August, 1982.

(AGREEMENT)

(Under Section 10-A of the Industrial Dipsutes Act, 1947)
Between

Name of the parties:

Representing the Employer:	Shri S.K. Roy Choudhury. Agent, Bararee Colliery of BCCL, P.O. Bhulanbararee, District Dhanbad.

Representing the workmen: Shri G.D. Pandey.,
Secretary, Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh, Rajendra Path, P.O. & District Dhanbad.

It is hereby agreed between the parties to refer the following dispute to the arbitration of Shri K. Shanmughavel, Deputy Chief Labour Commissioner (Central), Dhanbad.

1. Specific matter in dispute:
"Whether the Union's demand for placing Shri Ganga Dayal Singh, Clerk, in Cl. Grade-I is justified ? If so what relief he is entitled to ?"

2. Details of the parties to the dispute (including the name and address of the establishment/undertaking involved).	1. Employers in relation to the management of Bara Colliery of M/s. B.C.C. Ltd P.O Bhulanbararee, District Dhanbad. 2. Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh, Rajendra Path, (Dhanbad).
3. Name of the workman in case he himself is involved in the dispute or the name of the union, if any, representing the workman or workman in question:	Shri Ganga Dayal Singh, Clerk is represented by Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh, Rajendra Path, Dhanbad.
4. Total No. of workmen employed in the undertaking.	2209.
5. Estimated No. of workmen affected or likely to be affected by dispute.	1 (one only).

The arbitrator shall make his award within a period of six months from the date of publication of the arbitration agreement in the official gazette or within such further time as is extended by mutual agreement between us in writing. In case the award is not made within the period aforementioned, the reference to arbitration shall stand automatically cancelled and we shall be free to negotiate for fresh arbitration.

Signature of the parties.

Sd/-	Sd/-
(N.K.P SINHA, P.M.)	(D.G. Pandey)
Bhowra Area of Messrs BCCL	Secretary
Post Office Bhowra, District Dhanbad.	Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh, Rajendra Path, P.O & District Dhanbad.

WITNESS:

(1) Sd/-

(2) Sd/-

Dated 31st July, 1982.

IN THE MATTER OF INDUSTRIAL DISPUTE BETWEEN

Bararee Colliery of M/s Bharat Coking Coal Ltd., P.O. Bhulanbararee, District Dhanbad.

AND

Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh, Rajendra Path, Dhanbad

Specific matter.

"Whether the Union's demand for placing Shri Ganga Dayal Singh, Clerk in Cl. Grade-I is justified ? If so, what relief he is entitled to ?"

I hereby give my consent to act as an Arbitrator under Section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 in the above dispute.

Sd/-
(K. SHANMUGHVEL)
Signature of the Arbitrator
[No. L-20013(9)/82-D. III(A)]

आदेश

का०आ० 3019—मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, डाकघर सोनारडीह जिला धनबाद की गोविन्दपुर एरिया (नं० 3) के प्रबन्धतन्त्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, जिनका प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ राजेन्द्रपथ डाकघर और जिला धनबाद करती है, एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है,

और उक्त नियोजकों और कर्मकारों ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10-क की उपधारा (1) के अनुसरण में एक लिखित करार द्वारा उक्त विवाद को माध्यस्थम् के लिए निर्देशित करने का करार कर लिया है और उक्त माध्यस्थम् करार की एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजी गई है।

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क की उपधारा (3) के उपबन्धों के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार उक्त माध्यस्थम् करार को, जो उसे 5 अगस्त, 1982 को मिला था, एतद्द्वारा प्रकाशित करती है।

(करार)

(औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10-क के अधीन)

पक्षकारों के नाम :

नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले

1. श्री सुरेन्द्र सिंह, उप कार्मिक प्रबन्धक, गोविन्दपुर क्षेत्र संख्या 3 मैसर्स बी० सी० सी० एल० लिमिटेड, डाकघर सोनारडीह जिला धनबाद।

कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री जी० डी० पांडे, सेक्रेटरी, राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ राजेन्द्रपथ, डाकघर व जिला धनबाद।

पक्षकारों के बीच निम्नलिखित औद्योगिक विवाद को श्री के० शनमुघवेल उप मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) धनबाद के माध्यस्थम् के लिए निर्देशित करने का करार किया गया है।

1. विनिर्दिष्ट विवादग्रस्त विषय :

"क्या राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ, राजेन्द्रपथ की मांग कि मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, डाकघर सोनारडीह, जिला धनबाद की कुरिडीह कोलियरी के श्रमिक, श्री गुरचरन सिंह को अगस्त, 1977 से काम करने न्यायोचित है यदि नहीं तो, उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है।"

2. "क्या मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, डाकघर सोनारडीह, जिला धनबाद की कुरिडीह कोलियरी के प्रबन्धतंत्र की जनवरी, 1977

में रोजगार के दौरान तथा ड्यूटी पर रहते हुए दुर्घटना के कारण श्री गुरुचरण सिंह, खनिक की एक आंख की नजर चले जाने पर उनको यथोचित मुआवजा न देने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो उक्त कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?"

(ii) विवाद के पक्षकारों के ब्यौरे (जिसमे अन्तर्वलित स्थापन या उपक्रम का नाम तथा पता भी सम्मिलित है)	1. मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, डाकघर सोनारडीह, जिला धनबाद की कूरिडीह कोलियरी के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजक । 2 राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ, राजेन्द्रपथ, डाकघर व जिला धनबाद ।
(iii) कर्मकार का नाम, यदि वह विवाद में स्वयं शामिल है या यूनियन का नाम, यदि कोई हो, जो प्रश्नगत कर्मकार या कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करती है।	श्री गुरुचरण सिंह, खनिक मैसर्स बी० सी० सी० एल० लिमिटेड की कूरिडीह कोलियरी, जिसका प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय कोलियरी मजदूरी संघ, राजेन्द्रपथ, डाकघर व जिला धनबाद करती है।
(iv) प्रभावित उपक्रम में नियोजित कर्मकारों की कुल संख्या।	1700 (एक हजार और सात सौ)
(v) विवाद द्वारा प्रभावित या सम्भाव्यतः प्रभावित होने वाले कर्मकारों की प्राक्कलित संख्या ।	केवल एक

मध्यस्थ अपना पंचाट समुचित सरकार द्वारा राजपत्र में इस करार के प्रकाशन की तारीख से छः मास की अवधि के भीतर या इतने समय के भीतर, जो हमारे बीच पारस्परिक लिखित करार द्वारा बढ़ाया जाए, देगा। यदि उपर्युक्त कालावधि के भीतर पंचाट नहीं दिया जाता तो माध्यस्थम के लिए निर्देश स्वतः रद्द हो जाएगा और हम नए माध्यस्थम के लिए बात-चीत करने को स्वतंत्र होंगे ।

पक्षकारों के नाम

हस्ता०

(श्री सुरेन्द्र सिंह)	जी० डी० पांडे
उप कार्मिक प्रबन्धक,	(सेक्रेटरी)
मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड,	राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ,
डाकघर व जिला धनबाद	राजेन्द्र पथ, धनबाद

साक्ष्य :

(1) अपाठ्य 31-7-82

(2) मिद्रा प्रसाद 31-7-82

दिनांक 31 जुलाई, 1982

मैं औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10-क के अधीन उक्त विवाद में मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए अपनी सहमति देता हूं।

दिनांक 31-7-82

के० षनमुघवेल, मध्यस्थ के हृ०

[संख्या एल०-20013/10/82-डी०-3(ए०)]

ए०बी०एस सर्मा,

डैस्क अधिकारी

ORDER

S.O. 3019—Whereas an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Govindpur Area (No. III) of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Sonardih, District Dhanbad and their workmen represented by Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh, Rajendra Path, Post Office and District Dhanbad;

And whereas the said employers and their workmen have by a written agreement under sub-section (1) of sect n 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), agreed to refer the said dispute to arbitration and have forwarded to the Central Government a copy of the said arbittration agreement.

Now therefore, in pursuance of sub-section (3) of section 10A of the said Act, the Central Government hereby publishes the said agreement which was received by it on the 5th August, 1982.

AGREEMENT

(under Section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947)

BETWEEN

Name of the parties:

Representing Employers:	Shri Surender Singh, Deputy Personnel Manager, Govindpur Area (No. III). M/s Bharat Colking Coal Ltd., P.O. Sonardih, District Dhanbad.
Representing the workmen;	Shri G.D. Pandey, Secretary, Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh, Rajendra Path, P.O. & Distt: Dhanbad.

It is hereby agreed between the parties to refer the following dispute to the arbitration of Shri K. Shanmughavel, Deputy Chief Labour Commissioner (Central), Dhanbad.

(i) Specific matters in dispute :

1. "Whether the demand of Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh, Rajendra Path, Dhanbad, that the stoppage from work of Shri Gurucharan Singh, Miner, Kooridih Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, P.O. Sonardih, District Dhanbad from August, 1977 is justified ? If not, to what relief is the said workman entitled ?"
2. "Whether the action of the management of Kooridih Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, P.O. Sonardih, District Dhanbad in not giving the due compensation to Shri Gurucharan Singh, Miner due to loss of sight of one of his eyes on account of accident while on duty and in course of employment in January, 1977 is justified ? If not, to what relief is the said workman entitled?"

(ii) Details of the parties to the dispute including the name and address of the establishment or undertaking involved).	1. Employers in relation to the management of Kooridih Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, P.O. Sonardih, Distt. Dhanbad. 2. Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh, Rajendra Path, P.O. & Distt. Dhanbad.
(iii) Name of the workman in case he himself is involved in the dispute, or the name of the union if any representing the workman or workmen in question.	Shri Gurucharan Singh, Miner, Kooridih Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Ltd., represented by Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh, Rajendra Path, Dhanbad.

(iv) Total number of workmen employed in the undertaking.	1700 (one thousand and seven hundred).
(v) Estimated number of workmen affected or likely to be affected by the dispute.	One only.

The Arbitrator shall make his award within a period of six months from the date of publication of this agreement in the official gazette by the appropriate Government, or within such further time as is extended by mutual agreement between us in writing. In case award is not made within the period aforesaid, the reference to arbitration shall stand cancelled and we shall be free to negotiate for fresh arbitration.

Signature of the parties :

Sd/-	Sd/-
Shri Surender Singh, Deputy Personnel Manager, M/s. B.C.C. Ltd., P.O. & Distt: Dhanbad. 31-7-1982	G.D. Pandey, Secretary, Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh, Rajendra Path, Dhanbad. 31-7-1982

Witnesses:
(1) Sd/-
(2) Sd/-

Dated, the 31st July, 1982

I hereby give my consent to act as an Arbitrator under section/10A of the Industrial Disputes Act, 1947 in the above disputes.

K. SHANMUGHAVE
Signature of the Arbitrator

[No. L-20013(10)/82-D. III (A)]

आदेश

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 1982

का० आ० 3020.—मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, कार्मिक भवन, डाकघर सरायढेला, जिला धनबाद के प्रबंधतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, जिनका प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ करता है, एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और उक्त नियोजकों और उनके कर्मकारों ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत एक लिखित करार द्वारा उक्त विवाद को माध्यस्थम के लिए निर्देशित करने का करार कर लिया है और उक्त माध्यस्थम करार की एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजी गई है ।

अतः अब औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 10-क की उपधारा (3) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार उक्त माध्यस्थम करार को जो उसे 3 अगस्त 1982 को मिला था एतद्द्वारा प्रकाशित करती है ।

करार

(औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 10-क के अधीन)

पक्षकारों के नाम :—

नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले . श्री सी० चौबे,
उप कार्मिक प्रबंधक
मैं० भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
कार्मिक भवन,
धनबाद ।

कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले . श्री जी० डी० पाडें,
सैक्रेटरी,
राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ
राजेन्द्र पथ, धनबाद ।

पक्षकारों के बीच निम्नलिखित औद्योगिक विवाद को श्री के० शनमुघवेल उप मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) धनबाद के माध्यस्थम के लिए निर्देशित करने का करार किया गया है ।

(i) विनिर्दिष्ट विवादग्रस्त विषय	"क्या यूनियन की यह मांग न्यायोचित है कि श्री सुदामा तिवारी को पहली जनवरी, 1980 से श्रेणी-V में मैकेनिकल फिटर के रूप में निर्दिष्ट किया जाए ? यदि हां, तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?"
(ii) विवाद के पक्षकारों का विवरण जिसमें अंतर्वलित स्थापन या उपक्रम का नाम और पता भी सम्मिलित है।	मैसर्स भारत कोकिंग कोल लि०, कार्मिक भवन डाक-सरायढेला, धनबाद के मुख्यालय के प्रबंधतंत्र से संबद्ध नियोजक।
(iii) कर्मकार का नाम यदि वह स्वयं विवाद में अंतर्ग्रस्त हो या यदि कोई संघ प्रश्नगत कर्मकार या कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करता हो तो उसका नाम ।	राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ (इंटक), राजेन्द्र पथ, धनबाद
(iv) प्रभावित उपक्रम में नियोजित कर्मकारों की कुल संख्या।	300
(v) विवाद द्वारा प्रभावित या सम्भाव्यतः प्रभावित होने वाले कर्मकारों की प्राक्कलित संख्या	एक

मध्यस्थ अपना पंचाट इस माध्यस्थम करार के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से छह माह की अवधि के अन्दर या इतने और समय के भीतर जो हमारे बीच पारस्परिक लिखित करार द्वारा बढ़ाया जाए, देगा। यदि पूर्व वर्णित अवधि के भीतर पंचाट नहीं दिया जाता तो माध्यस्थम के लिए निदेश स्वतः रद्द हो जाएगा और हम नए माध्यस्थम के लिए बातचीत करने को स्वतंत्र होंगे

पक्षकारों के हस्ताक्षर :

ह० सी० चौबे,	ह० जी० डी० पाडें,
उप कार्मिक प्रबंधक,	सैक्रेटरी,
मैसर्स भारत कोकिंग कोल लि०	राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ,
कार्मिक भवन,	राजेन्द्र पथ,
डाकघर सरायढेला,	धनबाद ।
धनबाद ।	

23-7-82

साक्षी :—

1. ह०/—अपठनीय
2. ह०/—अपठनीय

मैसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, कार्मिक भवन डाकघर सरायढेला, जिला धनबाद के वाटर डिवीजन के प्रबंधतंत्र से संबद्ध नियोजक

और

राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ (इंटक) राजेन्द्र पथ धनबाद--श्री सुदामा तिवारी मैकेनिकल फिटर कर्मकार वाटर डिवीजन मैं० भारत कोकिंग कोल लि० कार्मिक भवन डाकघर सरायढेला जिला धनबाद के बारे में

के बीच औद्योगिक विवाद के

मामले में

औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 10-क के अन्तर्गत उपयुक्त विवाद में मध्यस्थ के रूप में काम करने के लिए अपनी सहमति देता हूं।

ह०/--के शनमुघवेल

उपमुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय)

धनबाद और माध्यस्थ

23-7-1982

[संख्या एल०-20013/8/82-डी (III)ए]

ए० वी०एस० शर्मा, डैस्क अधिकारी

ORDER

New Delhi, the 21st August, 1982

S.O. 3020.—Whereas an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Karmik Bhavan, Post Office Saraidhela, District Dhanbad and their workmen represented by Rashtriay Colliery Mazdoor Sangh;

And whereas the said employers and their workmen have by a written agreement under sub-section (1) of section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), agreed to refer the said dispute to arbitration and have forwarded to the Central Government a copy of the said arbitration agreement ;

Now therefore, in pursuance of sub-section (3) of section 10A of the said Act, the Central Government hereby publishes the said agreement which was received by it on the 3rd August, 1982.

AGREEMENT

(under section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947)

Name of Parties:

Representing Employer:	Shri C. Choubey, Deputy Personnel Manager, M/s. Bharat Coking Coal Ltd., Karmik Bhavan, Dhanbad.
Representing workmen:	Shri G.D. Pandey, Secretary, Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh, Rajendra Path, Dhanbad.

It is hereby agreed between the parties to refer the following dispute to the arbitration of Shri K. Shanmughavel, Deputy Chief Labour Commissioner (Central, Dhanbad).

(i) Specific matter in dispute	Whether the demand of the union that Shri Sudama Tewary should be designated as Mechanical Fitter in Category-V with effect from the 1st January, 1980 is justified ? If so, to what relief the workman is entitled ?
(ii) Details of the parties to the dispute including the name and address of the establishment or undertaking involved:	Employers in relation to th management of Headquarters of M/s Bharat Coking Coal Ltd., Karmik Bhavan, P.O. Saraidhela, Dhanbad.
(iii) Name of the workman in case he himself is involved in the dispute or the name of the union, if any, representing the workman or workmen in question:	Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh, (INTUC), Rajendra Path, Dhanbad.
(iv) Total number of workmen employed:	300
(v) Estimated number of workmen affected or likely to be affected by the dispute:	I (One)

The Arbitrator shall make his award within a period of six months from the date of publication of the aribtration agreement in the official gazette or within such further time as is extended by mutual agreement between us in writing. In case the award is not made within the period aforementioned, the reference to arbitration shall stand automatically cancelled and we shall be free to negotiate for fresh arbitration.

Signature of the parties:

Sd/-	Sd/-
C. Choubey,	G.D. Pandey,
Dy. Personnel Manager, M/s Bharat Coking Coal Ltd., Karmik Bhavan, Dhanbad.	Secretary, Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh, Rajendra Path, Dhanbad.

the 23rd July, 1982.

In the matter of Industrial Dispute between Bharat Coking Coal Ltd., Karmik Bhavan, P.O. Saraidhela, Dhanbad, and Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh, Rajendra Path Dhanbad

Specific matter:

"Whether the demand of the union that Shri Sudama Tewary should be designated as Mechnical Fitter in Category-V with effect from the 1st January, 1980 is justified ? If so to what relief the workman is entitled ?"

I hereby give my consent to act as Arbitrator under Section 10A of the Industrial Disputes Act, 1947 in the above dispute.

K. SHANMUGHAVEL

Deputy Chief Labour Commissoner (Central)

Dhanbad and Arbitrator. 23-7-82

[No. L-20013(8)/82-D. III (A)]

(A. V. S. SARMA), Desk Officer

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 1982

का०आ० 3021.—केन्द्रीय सरकार लौह अयस्क खान तथा मैंगनीज अयस्क खान श्रम कल्याण निधि नियम 1978 के नियम-3 के साथ पठित लौह अयस्क खान तथा मैंगनीज अयस्क खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1976 (1976 का 61) की धारा-6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र भाग II खंड-3 उपखंड (ii) तारीख 3 अक्तूबर 1981 के पृष्ठ 3334 पर प्रकाशित भारत सरकार

अब मंत्रालय को अधिसूचना संख्या का०आ० 2692 तारीख 14 सितम्बर 1981 में निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या-10 के सामने की प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :—

"10 श्री जी० डी० सिंह

सहायक महाप्रबंधक
किरिबुरु लौह अयस्क प्रोजेक्ट
बोकारो स्टील प्लांट
सिंहभूम (बिहार) ।"

[एफ० सं० यू–23017/10/80-एम IV]

अशोक गुप्त, उप सचिव

New Delhi, the 17th August, 1982

S.O. 3021.—*In exercise of the powers conferred by section 6 of the Iron Ore Mines and Manganese Ore Mines Labour Welfare Fund Act, 1976 (61 of 1976) read with rule 3 of the Iron Ore Mines and Manganese Ore Mines Labour Welfare Fund Rules, 1978, the Central Government makes the following amendment to the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 2692 dated 14th September, 1981 published at page 3335 of the Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (ii) dated 3rd October, 1981 namely :—*

In the said notification, for the entry against serial No. 10 the following shall be substituted namely :—

"10. Shri G. D. Singh

Assistant General Manager,

Kiriburu Iron Ore Project,

Singhbhum (Bihar) of Bokaro Steel Plant".

[F. No. U-23017/10/80-M.IV]
ASHOK GUPTA, Director

नई दिल्ली, 10 अगस्त 1982

का०आ० 3022 केन्द्रीय सरकार कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 91क के साथ पठित धारा 88 द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के नियमित कर्मचारियों को 23 अक्तूबर, 1977 से 30 सितम्बर, 1982 जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, तक की अवधि के लिए उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से छूट देती है।

2 उक्त छूट की शर्तें निम्नलिखित हैं अर्थात् :—

(1) पूर्वोक्त कारखाना जिसमें कर्मचारी नियोजित हैं एक रजिस्टर रखेगा जिसमें छूट प्राप्त कर्मचारियों के नाम और पदाभिधान दिखाए जाएंगे;

(2) इस छूट के होते हुए भी कर्मचारी उक्त अधिनियम के अधीन ऐसी सुविधाएं प्राप्त करते रहेंगे जिनको पाने के लिए वे इस अधिसूचना द्वारा दी गई छूट के प्रवृत्त होने की तारीख से पूर्व पंक्त अभिदायों के आधार पर हकदार हो जाते;

(3) छूट प्राप्त अवधि के लिए यदि कोई अभिदाय पहले ही किए जा चुके हों तो वे वापस नहीं किए जाएंगे;

(4) उक्त कारखाने का नियोजक उस अवधि की बाबत जिसके दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवर्तमान था (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त अवधि" कहा गया है) ऐसी विवरणियां ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अधीन उसे उक्त अवधि की बाबत देय था ;

(5) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्ति किया गया कोई निरीक्षक या निगम या इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य पदधारी —

(1) उक्त अवधि की बाबत धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन दी गई किसी विवरणी की विशिष्टियों को सत्यापित करने के प्रयोजनार्थ या

(2) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा यथा-अपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख उक्त अवधि के लिए रखे गये थे या नहीं या

(3) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी नियोजक द्वारा दिए गए उन फायदों को जिसके प्रतिफल स्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है नकद और वस्तु रूप में पाने का हकदार बना हुआ है या नहीं या

(4) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि उस अवधि के दौरान जब उक्त कारखाने के संबंध में अधिनियम के उपबन्ध प्रवृत्त थे ऐसे किन्हीं उपबन्धों का अनुपालन किया गया था या नहीं ,

निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा :—

(क) प्रधान या अव्यवहित नियोजक से अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जिसे उपरोक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी आवश्यक समझता है

(ख) ऐसे प्रधान या अव्यवहित नियोजक के अधिभोगाधीन किसी कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके प्रभारी से यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के संदाय से संबंधित ऐसे लेखा-बहियां और अन्य दस्तावेज ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करे और उसे उनकी परीक्षा करने दे या उसे ऐसी जानकारी दे जिसे वह आवश्यक समझता है या

(ग) प्रधान या अव्यवहित नियोजक के उसके अभिकर्ता या सेवक की या ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में पाया जाए या ऐसे किसी व्यक्ति की जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह कर्मचारी है, परीक्षा करना या

(घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर लेखाबही या अन्य दस्तावेज की नकल तैयार करना या उससे उद्धरण लेना।

[स० एस-38014/38/81-एच० आई०]

स्पष्टीकरण ज्ञापन

इस मामले में पूर्वापेक्षी प्रभाव से छूट देनी आवश्यक हो गई है क्योंकि छूट की मंजूरी के लिए प्रार्थनापत्र देर से प्राप्त हुआ। तथापि यह प्रमाणित किया जाता है कि पूर्वापेक्षी प्रभाव से छूट देने से किसी के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

New Delhi, the 10th August, 1982

S.O. 3022.—In exercise of the powers conferred by section 88 read with section 91A of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby exempts the regular employees of the Central Road Research Institute, New Delhi, beloging to Council of Scientific and Industrial Research from the operation of the said Act for the period from 23rd October, 1977 upto and inclusive of the 30th September, 1982.

The above exemption is subject to the following conditions, namely :—

(1) The aforesaid factory wherein the employees are employed shall maintain a register showing the names and designations of the exempted employees ;

(2) Notwithstanding this exemption, the emloyees shall continue to receive such benefits under the said Act to which they might have become entitled to on the basis of the cotributions paid prior to the date from which exemption granted by this notification operates ;

(3) The contributions for the exempted period, if already paid, shall not be refunded ;

(4) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 ;

(5) Any inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act, or other official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purposes of—

(i) verying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period; or

(ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General Regulations, 1950 for the said period ; or

(iii) ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification ; or

(iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act had been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory

be empowered to—

(a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary ; or

(b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found incharge thereof to produce to such inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary ; or

(c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such factory, establishment, office or other premises or any person whom the said inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee ; or

(d) make copies of or take extracts from, any register, accunot book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises.

[No. S-38014/38/81-III]

EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case, as the application for exemption was received late. However, it is certified that the grant of exemptios with retrospective effect will not affect the interest of anybody adversely.

CORRIGENDUM

New Delhi, the 11th August, 1982

S.O. 3023.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S. O. 911(E) dated 26th December 1981 published in the Gazette of India Extraordinary, Part II Section 3 Sub-section (ii), dated the 26th December 1981, at page-1580 in line 10, for

"URUAIYAR" read "URUVAIYAR".

[No. S-38013/31/81-HI]

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 1982

का०आ० 3024—भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में दिनांक 12 फरवरी, 1982 को प्रकाशित, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का०आ० 73 (अ), दिनांक 12 फरवरी, 1982 में,—

पृष्ठ 121 की 13वीं पंक्ति में "पठानकोट जिले" के स्थान पर "गुरदासपुर जिले" पढ़ें।

[सं० एस-38013/3/82-एच०आई०]

CORRIGENDUM

New Delhi, the 11th August, 1982

S.O. 3024.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S. O. 73(E), dated 12th February, 1982 published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated 12th February 1982, at page-122 in line 4, for 'district Pathankot" read "district Gurdaspur".

[No. S-38013/3/82-HI]

नई दिल्ली, 13 अगस्त 1982

का०आ० 3025—मैसर्स कर्नाटक डेरी डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड रजिस्टर्ड एंड सेन्ट्रल आफिस, 22 पूर्णिमा बिल्डिंग, जयचमा राजेन्द्र फर्स्ट क्रास, बंगलोर-27

(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो कि केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2 नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3 सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के रचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7 सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर उस स्कीम के अधीन देय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8 सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट वापस ले ली जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12 उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय, तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं० एस-35014(90)/82-पी०एफ०-II]

New Delhi, the 13th August, 1982

S.O. 3025.—Whereas Messrs Karnataka Dairy Development Corporation Limited, Regd. and Central Office, 22, Poornima Buildings, Jayachamarajandra Road, 1st Cross Bangalore-27, (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefit under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1 The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and maintain such accounts and provide for such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges, etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the notice board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended along with a translation of the salient features thereof, in the Language of majority of the employees.

5. Where the employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7 Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8 No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving him approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason the employees of the establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the establishment or the benefits to the employees under this Scheme are reduced to any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10 Where, for any reason the employer fails to pay the premium within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12 Upon the death of the member covered under the Scheme, the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(90)/82-PF. II]

का०आ० 3026—मैसर्स नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव मिल्क प्राडयूसर्स यूनियन लिमिटेड, ऊटाकमण्ड-643001 (टी एस 3102) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिससे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारी निक्षेप के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है;

अत केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापना को सीमत वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1 उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाए प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2 नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3 सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4 नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचनापट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5 यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6 यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से में वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हो, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8 सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9 यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10 यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11 नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12 उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं० एस-35014(91)/82-पी एफ-II]

S.O. 3026.—Whereas Messrs Nilgiris District Cooperative Milk Producers Union Limited, Ootacammund-643001 (TN. 3102) (hereinafter referred to as the said establishment) have been applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Depositlinked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Not, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and maintain such accounts and provide for such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-sectin (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges, etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the notice board of the establishmen, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended along with a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Where the employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Providen Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him o the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving him approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason the employees of the establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the establishment or the benefits to the employees under this Scheme are reduced to any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason the employer fails to pay the premium within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme, the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014 (91)/82-PF-II]

का० आ० 3027.—मैसर्स पंचमहल डिस्ट्रिक्ट को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड गोधरा जिला पंचमहल (जी ने 14659) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1 उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त गुजरात को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2 नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3 सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना बीमा प्रीमियम का संदाय लेखाओं का अंतरण निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है होने वाले सभी व्यय का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4 नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बिमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बजमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7 सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8 सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त गुजरात के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व अकर्मचारियों अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10 यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम निश्चित करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11 नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं० एस-35014(92)/82-पी एफ-II]

S.O. 3027.—Whereas Messrs Panchmahal District Co-operative Bank Limited, Godhra District, Panchmahals (GT/4659) (hereinafter referred to as the said establishment) have been applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurancec Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat and maintain such accounts and provide for such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges, etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the notice board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended along with a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Where the employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment, a copy of the rules of the Group Insurance his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving him approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason the employees of the establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the establishment or the benefits to the employees under this Scheme are reduced to any manner, the exemption shall be liable to the cancelled.

10. Where for any reason the employer fails to pay the premium within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme, the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014 (92)/82-PF. II]

का०आ० 3028.—मैसर्स गुजरात कोआपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, अमूल डेरी रोड, आनन्द-388001(टी०जे०/7286) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अहमदाबाद को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे।

3 सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5 यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6 यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8 सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अहमदाबाद, के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में, भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं०एम०-35014/96/82-पी०एफ-2]

S.O. 3028.—Whereas Messrs Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation Limited, Amul Dairy Road, Anand-388001 (GJ/7286) (hereinafter referred to as the said establishment) have been applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Ahmedabad and maintain such accounts and provide for such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month

3 All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme including maintenance of accounts, submission of returns payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges, etc. shall be borne by the employer

4 The employer shall display on the notice board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended along with a translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Where the employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India

6 The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme

7 Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation

8 No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Ahmedabad and where any amendment is likely to affect adversely, the interest of the employees the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving him approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view

9. Where for any reason the employees of the establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the establishment or the benefits to the employees under this Scheme are reduced to any manner, the exemption shall be liable to the cancelled

10 Where, for any reason the employer fails to pay the premium within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11 In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benets to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer

12. Upon the death of the member covered under the Scheme, the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the su massured from the Life Insurance Corporation of India

[No S-35014(96)/82-PF-II]

का० आ० 3029—मैसर्स करूणमविगै मिल्स लिमिटेड, पोस्ट बॉक्स स० 2, सोमनूर डाकघर, कोयम्बटूर जिला, तमिलनाडु (जिसे इसमे इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप मे फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1 उक्त स्थापन के संबंध मे नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2 नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3 सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन मे, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4 नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमे संशोधन किया जाए, तब उन संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा मे उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5 यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप मे उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6 यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7 सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप मे दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8 सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु, के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते है, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10 यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का सदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को यदि यह, छूट नहीं दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के सबध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का सदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं० एस०-35014/119/82-पी०एफ-2]

S.O. 3029.—Whereas Messrs Karunanbigai Mills Limited, Post Box No. 2, Somanur P. O., Coimbatore District, Tamil Nadu, (hereinafter referred to as the said establishment have be applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and, maintain such accounts and provide for such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges, etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the notice board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended along with a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Where the employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving him approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason the employees of the establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the establishment or the benefits to the employees under this Scheme are reduced to any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason the employer fails to pay the premium within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the reesponsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme, the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assuerd from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(119)/81-PF-II]

का०आ० 3030.—मैसर्स कैन्को इंडियन/फार्मास्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड, रजिस्ट्रीकृत कार्यालय, 20 डाक्टर ई० मोसेज मार्ग, बम्बई 400011 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हे अनुज्ञेय हैं,

अत केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक निधि आयुक्त, महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं० एस-35014/137/82-पी० एफ-2]

S.O. 3030.—Whereas Messrs Franco Indian Pharmaceuticals Private Limited, Regd. Office 20, Dr. E. Moses Road, Bombay-400011. (hereinafter referred to as the said establishment) have been applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra maintain such accounts and provide for such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges, etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the notice board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended along with a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Where the employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Gorup Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and

where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving him approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason the employees of the establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the establishment or the benefits to the employees under this Scheme are reduced to any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason the employer fails to pay the premium within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme, the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assuerd to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation o India.

[No. S-35014(137)/82-PF. II]

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 1982

का०आ० 3031.—मैसर्स राजपूताना मोटर्स 6 मनोरमागंज, इन्दौर-452001 (मध्य प्रदेश) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप संहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणिकाएं भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षक के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना बीमा प्रीमियम का संदाय लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी खर्चों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा तथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब उन संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों को बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए समुचित बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट नहीं गई होती उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं० एस० 35014/9/82-पी०एफ 2]

New Delhi, the 17th August, 1982

S O. 3031.—Whereas Messrs Rajputana Motors, 6, Manoramaganj Indore-452001 (Madhya Pradesh), (hereinafter referred to as the said establishment have been applied for

exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act),

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and maintain such accounts and provide for such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges, etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the notice board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended along with a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Where the employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving him approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason the employees of the establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the establishment or the benefits to the employees under this Scheme are reduced to any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason the employer fails to pay the premium within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurence benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme, the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(9)/82-PF. II]

का० आ० 3032—मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड, एक्सप्रेस बिल्डिंग बहादुरशाह जफर मार्ग, पोस्ट बाक्स सं० 7003 नई दिल्ली 110002 (दि०/155) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त दिल्ली को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निदिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे।

3 सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4 नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5 यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा

और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप में वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, दिल्ली के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन सब सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं० एस० 35014/15/82-एस० सि० (II)]

S.O. 3032.—Whereas Messrs Hindustan Lever Limited, Express Building, Bahadur Shah Zafar Marg, P. O. Box No. 7003, Nw Delhi-110002 (DL/155), (hereinafter referred to as the said establishment) have been applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter refedred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees that the benefits admissible under the Employees Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi maintain such accounts and provide for such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges, etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the notice board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended along with a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Where the employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benfits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and where any amendement is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving him approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason the employees of the establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the establishment or the benefits to the employees under this scheme are reduced to any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason the employer fails to pay the premium within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme, the employer in relation to the said establishment

shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(19)/82-PF. II]

का० आ० 3033.—मैसर्स आई० डी० एल० केमिकल्स लिमिटेड, पोस्ट बाक्स सं०, 1 सन्तनगर, हैदराबाद-500018 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ।

अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के भी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, आन्ध्र प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करे।

2 नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे।

3 सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6 यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बताए जाते है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हो, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए, भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में सदेय होती जब वह, उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, आन्ध्र प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपने अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9 यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते है, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11 नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं० एम० 35014/22/82-पी० एफ (II)]

S.O. 3033.—Whereas Messrs I. D. L. Chemical Limited, P.B. No. 1, Santhnagar, Hyderabad-500018, (hereinafter referred to as the said establishment) have been applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh maintain such accounts and provide for such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time driect under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges, etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the notice board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended along with a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Where the employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradsh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving him approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason the employees of the establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the establishment or the benefits to the employees under this Scheme are reduced to any manner, the exemption shall be liable to the cancelled.

10. Where, for any reason employer fails to pay the premium within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurence benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme, the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(22)/82-PF. II]

का० आ० 3034.—मैसर्स मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड, 23 शापिंग सेन्टर, न्यू मार्केट टी० टी० नगर, भोपाल (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है :

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) के खण्ड (क) के अधीन-समय समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधित की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9 यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम का, जिसे स्थापन पहले अपनाचुका है अधीन नहीं रह जाते है, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10 यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवना बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने मे असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय मे किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यो के नामनिर्देशितियो या विधिक वारिसो को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदो के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियो/विधिक वारिसो को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा मे, भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं० एस 35014 (27)/82-पी०एफ०-II)]

S.O. 3034.—Whereas Messrs Madhya Pradesh Laghu Udyog Nigam Limited, 23, Shoping Centre, New Market, T. T. Nagar, Bhopal, (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and maintain such accounts and provide for such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges, etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the notice board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended along with a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Where the employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7 Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving him approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason the employees of the establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the establishment or the benefits to the employees under this Scheme are reduced to any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason the employer fails to pay the premium within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme, the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(27)/82-PF II]

का० आ० 3035.—मेसर्स गोयट्ज (इंडिया) लिमिटेड, तेज बिल्डिंग, बी/8 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, दिल्ली को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7 सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त दिल्ली के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं० एस० 35014(52) 82 पी एफ-II]

S.O. 3035.—Whereas Messrs GOETZE (INDIA) Limited, Tej Building, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi-110002, (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and maintain such accounts and provide for such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the clouse of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges, etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the notice board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended along with a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Where the employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the

said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Delhi and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving him approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason the employees of the establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the establishment or the benefits to the employees under this Scheme are reduced to any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason the employer fails to pay the premium within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme, the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(52)/82-PF-III

का०आ० 3036.—मैसर्स एच०एम०टी० लिमिटेड, घड़ी कारखाना एच० एम० टी० डाकघर, बंगलौर-560031 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है :

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त कर्नाटक को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन की सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होता जब वह उक्त स्कीम अधीन होती तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त कर्नाटक के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, यह इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11 नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12 उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं० एस० 35014/53/81 भ० नि० (II)]

S.O. 3036.—Whereas Messrs H.M.T. Limited, Watch Factory, H.M.T. P.O. Bangalore-560031, (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said scheme for period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and maintain such accounts and provide for such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges, etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the notice board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended along with a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Where the employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving him approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason the employees of the establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the establishment or the benefits to the employees under this Scheme are reduced to any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason the employer fails to pay the premium within the due date as fixed by the life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme, the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014 (53)/81-PF-II]

का० आ० 3037.—मैसर्स नेशनल फिनरल डयलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, सोमाजिगुड़ा, हैदराबाद के मैसर्स (i) डायमण्ड प्रोजेक्ट पन्ना (मध्य एम० पी० 1444) (ii) बैलेडिला आइरन ओर प्रोजेक्ट, बचली एम० पी० 2278 और (iii) बैलेडिला आयरन प्रोजेक्ट किरनदल एम पी/2279) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा तथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को, जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं० एस० -35014(65)/82-पी एफ-II]

S.O. 3037.—Whereas Messrs (i) The Diamond Mining Project, Panna (MP/1444), (ii) The Bailadila Iron Ore Project, Bacheli (MP/2278) and (iii) The Bailadila Iron Ore Project, Kirandul (MP/2279) belonging to the National Mineral Development Corporation Limited, Somajiguda, Hyderabad (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), (hereinafter referred to as the said Act) ;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution of payment of premium, the enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the said Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and, maintain such accounts and provide for such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges, etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Where the employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced to any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer on payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme, the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014 (65)/82-PF-II]

का० आ० 3038.—मैसर्स आंध्र प्रदेश कोआपरेटिव सैन्ट्रल एग्रीकल्चर डवलपमेंट बैंक लिमिटेड बरकुतपुरा, हैदराबाद (ए पी/12505) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त आंध्र प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2 नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, आंध्र प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा, और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं० एस-35014(66)/82-पीएफ०-II]

S.O. 3038.—Whereas Messrs Andhra Pradesh Cooperative Central Agriculture Development Bank Limited, Barkatpura, Hyderabad (AP/2505), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh and maintain such accounts and provide for such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges, etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the notice board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when admended along with a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Where the employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, this employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under the scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Andhra Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving him approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason the employees of the establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the establishment or the benefits to the employees under this Scheme are reduced to any manner, the extension is liable to be cancelled.

10. Where for any reason the employer fails to pay the premium within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of the exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(66)/82-P.F. II]

का० आ० 3039—मैसर्स न्यू शोरोफ मिल्स, को-आपरेटिव कंजमर्स सोसायटी लिमिटेड, नांदेड (जी० जे०/4893) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त गुजरात को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण, प्रभारों का संदाय आदि भी है होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त गुजरात के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल

प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9 यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10 यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय सत्वरता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं० एस० 35014/84/82 पी० एफ० (ii)]

S.O. 3039.—Whereas Messrs New Shorrock Mills Co-operatve Consumers Society Limited, Nadiad (GJ/4823) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefit admissible under the Employees Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat and maintain such accounts and provide for such facilities for inspection as the Central Government may from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges, etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the notice board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended along with a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Where the employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving him approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason the employees of the establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the establishment or the benefits to the employees under this Scheme are reduced to any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason the employer fails to pay the premium within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme, the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S 35014(84)/82-PF.II]

का० आ० 3040—मैसर्स राजकोट कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड "सहयोग" ढेबर भाई रोड राजकोट (जी जे/4660) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा

स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ;

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त गुजरात को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया, जाना बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण, प्रभारों का संदाय आदि भी है होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/ नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त गुजरात के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होने बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय सत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं० एस 35014/85/82-पी० एफ 2]

S.O. 3040.—Whereas Messrs Rajkot District Cooperative Bank Limited, "Sahyog" Debarbhai Road, Rajkot (GJ/4660), (hereinafter referred to as the said estabilshment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exericse of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such reutrns to the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat and maintain such accounts and provide for such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the notice board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended along with a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Where the employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an estabilshment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him

as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation

8. No amendment of the pprovision of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving him approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason the employees of the establishment do not remain covered under the Group Insurance Scehme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the estabilshment or the benefits to the employees under this Scheme are reduced to any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason the employer fails to pay the premium within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme, the employer in relation to the said estabilshment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(85)/82-PF.II]

का०आ० 3041—मैसर्स मेटल लेम्प कोर्स (इण्डिया) लिमिटेड 2, मर्फी रोड पी०बी०नं० 876 यलसूर बंगलोर-560008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

551 G of I/82—10

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2 नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3 सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4 नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट पर प्रदर्शित करेगा ।

5 यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6 यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/सामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8 सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9 यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10 यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं०एस-35014(93)/82-पी०एफ-II]

S.O. 3041.—Whereas Messrs Metal Lamp Caps (India) Limited 2, Murphy Road, P.B. No. 876, Ulsoor, Bangalore-560008, (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952) (hereinafter rereferred to as the said Act;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Inurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and maintain such accounts and provide for such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges, etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the notice board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended along with a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Where the employee, who is already a member of the Employee' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving him approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason the employees of the establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the establishment or the benefits to the employees under this Scheme are reduced to any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason the employer fails to pay the premium within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the members covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(93)/82-PF. II]

का०आ० 3042.—मैसर्स डी०पी०एफ०टेक्सटाइल्स लिमिटेड मेट्टुपलयम रोड, कोयम्बटूर-641029 (टी०एन०/1059) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6 यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपबन्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7 सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8 सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9 यदि किसी कारणवश स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10 यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11 नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं०एस-35014(91)82-पी०एफ० 2]

S.O. 3042.—Whereas Messrs D.P.I. Textiles Limited, Mettupalayam Road, Coimbatore-641029 (TN/1059) (hereinafter referred to as the said establishment) have been applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Not, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishmnt from the operation of all the provisions of the said scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and maintain such accounts and provide for such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges, etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the notice board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended along with a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Where the employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving him approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason the employees of the establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the establishment or the benefits to the employees under this Scheme are reduced to any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason the employer fails to pay the premium within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme, the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(94)/82-P.F.II]

का० आ० 3043—मैसर्स ला० गज्जर मशीनरीज प्राईवेट लिमिटेड, अपोजिट कल्याण मिल्स, नरोदा रोड अहमदाबाद-380025 (जी जे /20 ई) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीते रहते हुए , उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त गुजरात को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7 सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, गुजरात के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय सत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं० एस- 35014 / 95 /82-पी एफ (II)]

S.O. 3043.—Whereas Messrs La Gajjar Machineries Private Limited, Opp. Kalyan Mills Naroda Road, Ahmedabad-380025 (GJ|20E) (hereinafter referred to as the said establishment) have been applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) ;

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat maintain such accounts and provide for such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges, etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the notice board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended along with a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Where the employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving him approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason the employees of the establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the establishment or the benefits to the employees under this Scheme are reduced to any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason the employer fails to pay the premium within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme, the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(95)/82-P.F.II]

का० आ० 3044—मैसर्स साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड (साबर डेरी) हिम्मत नगर (गुजरात) (जी० ओ० / 3558) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिये ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, गुजरात को ऐसी विवरणिया भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5 यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों

को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस / नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त गुजरात के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, यह इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवना बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं० एम-35014 / 97 / 82-पी० एफ -2]

S.O. 3044.—Whereas Messrs Sabarkantha District Co-operative Milk Producers Union Limited (Sabar Dairy) Himabnagar (Gujarat) (GJ/3558) (hereinafter referred to as the said establishment) have been applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat and maintain such accounts and provide for such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges, etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the notice board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended along with a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Where the employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving him approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason the employees of the establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the establishment or the benefits to the employees under this Scheme are reduced to any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason the employer fails to pay the premium within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsiblity for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs o deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme, the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(97)/82-PF.II]

का० आ० 3045.—मैसर्स खेपी-सीमी इक्विपमेंट पोलची रोड, मलुम चमपट्टी पोस्ट कोयम्बटूर-641021 (टी० एन०-19884). (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके

पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना-पट पर प्रदर्शित करेगा

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा

9 यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10 यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11 नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12 उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं० एस-35014/98/82-पी०एफ-2]

S.O. 3645.—Whereas Messrs Revathi CP Equipment, Pollachi Road, Malumachampatti Post, Coimbatore-641021 (TN/9884), (hereinafter referred to as the said establishment) have been applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and maintain such accounts and provide for such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges, etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the notice board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended along with a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Where the employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving him approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason the employees of the establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as alread adopted by the establishment or the benefits to the employees under this Scheme are reduced to any manner, the exemption shall be liable to the cancelled.

10. Where, for any reason the employer fails to pay the premium within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme, the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(98)/82-PF-II]

का०आ० 3048.—मैसर्स मिश्र धातु निगम लिमिटेड, सुपर अलायस प्रोजेक्ट, डाकघर कांचनबाग, हैदराबाद-500258(ए०पी०/3988) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, आन्ध्र प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा स्कीम निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए, भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8 सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, आन्ध्र प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने की युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उस मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं०एस-35014/108/82-पी एफ-2]

S.O. 3046.—Whereas Messrs Mishra Dhatu Nigam Limited Superalloys Project, P. O. Kanchan Bagh, Hyderabad-500258 (AP/3986) (hereinafter referred to as the said establishment) have been applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme),

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Ahmadabad maintain such accounts and provide for such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges, etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the notice board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended along with a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Where the employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme, are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Ahmadabad and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund [illegible] before giving him approval, give a [illegible] to the employees to explain their [illegible].

9. Where for any reason the employees of the establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the establishment or the benefits to the employees under this Scheme are reduced to any manner, the exemption shall be liable to the cancelled.

10. Where, for any reason the employer fails to pay the premium within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme, the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014 (108)/82-PF. II]

का०आ० 3047.—मैसर्स ला-गज्जर ब्लोअर्स प्राईवेट लिमिटेड कल्याण मिल्स के निकट, नरोदा रोड, अहमदाबाद - 380025 (ग/20 सी) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1 उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अहमदाबाद को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2 नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3 सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4 नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तो उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उक्त स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत अपेक्षित प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ा दिए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप में वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अहमदाबाद के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में, असफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं० एस०-35014(122)82-पी एफ-2]

S.O. 3647.—Whereas Messrs La-Gajjar Blowers Private Limited, Near Kalyan Mills, Naroda Road, Ahmedabad-380025 (GJ/20c) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Ahmedabad and maintain such accounts and provide for such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges, etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the notice board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended along with a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Where the employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme, are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Ahmedabad and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason the employees of the establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the establishment or the benefits to the employees under this Scheme are reduced to any manner, the exemption shall be liable to the cancelled.

10. Where, for any reason the employer fails to pay the premium within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of

assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme, the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014 (122)/82-PF II]

का०आ० 3048—मैसर्स क्रेसट डाइज एंड केमिकल्स, 34, चौरिंगी रोड, कलकत्ता-700071, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कलकत्ता को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता, तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कलकत्ता के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं० एस० 35014/126/81-भ०नि०-2]

S.O. 3048.—Whereas Messrs Crescent Dyes and Chemicals, 34, Chowringhee Road, Calcutta-700071. (hereinafter referred to as the said establishment) have been applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Calcutta and maintain such accounts and provide for such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges, etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the notice board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended along with a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Where the employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme, are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under his scheme less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Calcutta and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving him approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason the employees of the establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the establishment or the benefits to the employees under this Scheme are reduced to any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason the employer fails to pay the premium within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased member, who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme, the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014 (126)81-PF. II]

का० आ० 3049—मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड, हिन्दुस्तान लीवर हाउस, 165-166, बैकबे रेक्लेमेशन, मुम्बई-400020 (महा०/917) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे, उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तत्काल दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिसों/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते है, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[एस० 35014/130/82-पी०एफ०-2]

S.O. 3049.—Whereas Messrs Hindustan Lever Limited, Hindustan Lever House, 165-166, Backbay Reclamation, Bombay-400020 (MH/917) (hereinafter referred to as the said establishment) have been applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Depositlinked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and maintain such accounts and provide for such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges, etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the notice board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended along with a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Where the employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme, are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving him approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason the employees of the establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the establishment or the benefits to the employees under this Scheme are reduced to any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason the employer fails to pay the premium within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme, the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014 (130)/82 PF. II]

का० आ० 3050—मैसर्स भारत फ्रिट्ज वर्नर प्राइवेट लिमिटेड, रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पीनियां, बंगलौर-560022 (के०एन०/2346) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सम्बद्ध बीमा स्कीम

1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5 यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो वह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं०एस० 35014/133/82-श्र०नि० (II)]

S.O. 3050.—Whereas Messrs Bharat Fritz Werner Private Limited, Regd. Office, Peenya, Bangalore-560022(KN/2346) (hereinafter referred to as the said establishment) have been applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act).

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and maintain such accounts and provide for such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges, etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the notice board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended along with a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Where the employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme, are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and where any amendment is taking to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving him approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason the employees of the establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the establishment or the benefits to the employees under this Scheme are reduced to any manner, the exemption shall be liable to the cancelled.

10. Where for any reason the employer fails to pay the premium within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme, the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(133)/82-PF.II]

का० आ० 3051—मैसर्स एलिडाक डिस्ट्रिब्यूटर्स, 371-372, ईसानपुर, अहमदाबाद-382443 (जी० जे०/10832) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अहमदाबाद को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, इसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा। और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी का उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अहमदाबाद के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं; तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं० एस-35014/(134)/82-भ०नि०-2]

S.O. 3051.—Whereas Messrs ALIDAC Distributors 371-372, Isanpur, Ahmedabad-382443 (GJ/10832), (hereinafter referred to as the said establishment) have be applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees th the benefits admissible under the Employees Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Not, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Ahmedabad and maintain such accounts and provide for such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges, etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the notice board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended along with a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Where the employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme, are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Ahmedabad and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving him approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason the employees of the establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the establishment or the benefits to the employees under this Scheme are reduced to any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason the employer fails to pay the premium within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelltd.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme, the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S.35014(134)/82-P.F II]

का०आ० 3052—मैसर्स एन० जी० ई० एफ० लिमिटेड, रजिस्ट्रीकृत कार्यालय ग्राउन्ड, मद्रास रोड, ब्याप्पनाहल्ली, पोस्ट बाक्स नं० 3876 बंगलौर 560038(के०एन०/2835) ,(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप मे फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियो के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हे अनुज्ञेय है,

अत केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धो के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1 उक्त स्थापन के संबंध मे नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त कर्नाटक को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2 नियोजक, ऐसे निरीक्षणों प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3 सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन मे, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4 नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा मे उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि

का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6 यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7 सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों स्कीमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, कर्नाटक के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9 यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसमें स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रहे जाते है, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति में कम हो जाते है; तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11 नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों का जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12 उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं० एस-35014/141/82-पी० एफ-2]

S.O. 3052.—Whereas Messrs NGEF Limited, Regd. Office, Old Madras Road, Byappanahalli, P.B. No. 3876, Bangalore-560038 (KN/2835) (hereinafter referred to as the said establishment) have been applied for exeption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employ es Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Not, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and maintain such accounts and provide for such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges, etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the notice board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended along with a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Where the employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme, are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving him approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason the employees of the establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the establishment or the benefits to the employees under this Scheme are reduced to any manner, the exemption is liable to be cancelled.

10. Where for any reason the employer fails to pay the premium within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelltd.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees of the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme, the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No S-35014(141)/82-P.F.-II]

का० आ० 3053.—मैसर्स मंजेस्टिक आटो लिमिटेड, सी/48-51, फोकल पाइंट, लुधियाना-141001, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पंजाब को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंकेक्षण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उसमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उनके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप में वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पंजाब के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी का व्ययपगत हो जाने दिया जाता तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए, किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[स. एस-35014/112/82-पी एफ-2]

ए० के० भट्टाचार्य, अवर सचिव

S.O. 3053.—Whereas Messrs Majestic Auto Limited, C/48-51, Focal Point, Ludhiana-141001 (hereinafter referred to as the said establishment) have been applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Punjab and maintain such accounts and provide for such facilities for inspection as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges, etc shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the notice board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended along with a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Where the employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme, are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Punjab and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving him approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason the employees of the establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the establishment or the benefits to the employees under this Scheme are reduced to any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason the employer fails to pay the premium within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme, the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(142)/82-PF.II]

A. K. BHATTARAI, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982